राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

Www.gauravshalibharat.com

गौरवशाली भारत

नई दिल्ली से प्रकाशित

वर्ष : 11
अंक : 309
पृष्ठ : 08
नई दिल्ली
शनिवार 21 मई 2022
मूल्य : 1.50/-
RNI No .DELHIN/2011/38334

मुख्य अपडेट | पेज 3 मुंडका में हुए अग्निकांड के खिलाफ ऐक्टू ने विरोध मार्च निकालते हुए मुख्यमंत्री के समक्ष किया प्रदर्शन | पेज 5 गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में पिछड़ी चीनी मिलों के खिलाफ होगी कार्रवाई : डा. दिनेश्वर मिश्र | पेज 7 अमेरिका तक पहुंचा मंकी पॉक्स, जानें- कैसे होता है संक्रमण; किन्हें बना रहा ज्यादा शिकार

महाराष्ट्र में भीषण सड़क हादसा

लकड़ियों से भरे ट्रक और पेट्रोल टैंकर में टक्कर के बाद लगी आग, 9 लोगों की जलकर मौत

एजेंसी

चंद्रपुर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शुक्रवार तड़के हुई एक भीषण दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक और पेट्रोल टैंकर में इतनी भीषण टक्कर हुई कि दोनों वाहनों में आग लग गई। ट्रक लकड़ियों से भरा था, इसलिए आग को फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। ट्रक में बैठे 7 लोग और पेट्रोल टैंकर में बैठे 2 लोग आग की चपेट में आ गए और सभी ने मौके पर दम तोड़ दिया।

हादसे में शव इतनी बुरी तरह से जल गए हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। इस भीषण दुर्घटना के बाद कई घंटों तक चंद्रपुर शहर की ओर जाने वाली सड़क जाम रही। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। वहीं, आग की लपटों से पास के जंगल में आग लग गई।

दुर्घटना के बाद पास के जंगल में लगी आग

चंदरपुर सब डिवीजनल पुलिस अफसर सुधीर नंदनवार ने बताया कि शहर के मुख्य मार्ग पर अजयपुर गांव के पास ट्रक, टायर के फटने के बाद वह अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे टैंकर से टकरा गया और उसमें आग लग गई। इस दुर्घटना के बाद टैंकर से पेट्रोल फैलने की वजह से आसपास के कई पेड़ जल गए हैं। आग तड़के चार बजे के आसपास लगी थी और इस पर शुक्रवार सुबह 11 बजे पूरी तरह काबू पाया गया।

चंद्रपुर से फायर बिग्रेड की एक दर्जन गाड़ियों को आग बुझाने के लिए घटनास्थल पर बुलाया गया था। इस अग्निकांड के आबाद हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार नजर आई।

फायर ब्रिगेड पर देर से पहुंचने का लगा आरोप

वन विभाग के सूत्रों ने बताया कि अजयपुर से अग्निशमन दल के लोग इस दुर्घटना के करीब एक घंटे बाद मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने में कई घंटे लग गए।

सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शवों को क्षतिग्रस्त ट्रकों से निकालकर नजदीकी अस्पताल के शवग्रह में रखवाया गया।

ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

वाराणसी जिला जज 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करें; नमाज जारी रहेगी, शिवलिंग के दावे वाली जगह सुरक्षित रखें

नई दिल्ली। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को तीसरी बार बैठी। तीन जजों की बेंच ने केस वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। यानी अब मामले की सुनवाई बनारस के जिला जज करेंगे।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने 51 मिनट चली सुनवाई में साफ शब्दों में कहा कि मामला हमारे पास जरूर है लेकिन पहले इसे वाराणसी जिला कोर्ट में सुना जाए। कोर्ट ने कहा कि जिला जज 8 हफ्ते में अपनी सुनवाई पूरी करेंगे। तब तक 17 मई की सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देश जारी रहेंगे।

बता दें कि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में तीन बड़ी बातें कही थीं। पहला- शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित किया जाए। दूसरा- मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से न रोका जाए। तीसरा- सिर्फ 20 लोगों के नमाज पढ़ने वाला ऑर्डर अब लागू नहीं। यानी ये तीनों निर्देश अगले 8 हफ्तों तक लागू रहेंगे। इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। कोर्ट ने इतना कहने के बाद मामले में आगे की सुनवाई वाराणसी जिला कोर्ट के हवाले कर दी।

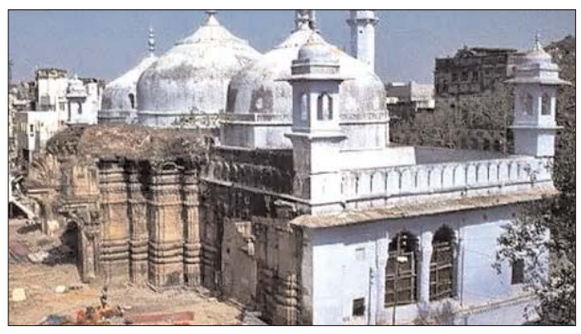

कोर्ट ने कहा- सभी के हित सुनिश्चित किए जाएंगे

कोर्ट ने कहा कि मामला जिला जज के पास भेजा जाए। उनके पास 25 साल का लंबा अनुभव है। इस मामले में सभी पक्षों के हित को सुनिश्चित किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह न समझा जाए कि हम मामले को निरस्त कर रहे हैं। आपके लिए आगे भी हमारे रास्ते खुले रहेंगे।

रिपोर्ट लीक कर माहौल बिगाड़ने की साजिश

मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि रिपोर्ट लीक कर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है।इस पर कोर्ट ने सख्त ऐतराज जताया और यह निर्देश दिया कि इस पर रोक लगाई जाए।

कोर्ट में हिन्दू और मुस्लिम पक्ष की दलील...

कोर्ट में हिंदू पक्षकार की ओर से सीनियर वकील वैद्यनाथन और मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद कमेटी के वकील हुजेफा अहमदी ने दलीलें पेश कीं। पढ़िए क्या-क्या कहा दोनों वकीलों ने...

1. कमीशन की रिपोर्ट पर

हिंदू पक्ष ने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट आ गई है। पहले उसे देखा जाए। इसके बाद ही फैसले पर विचार हो। मुस्लिम पक्ष ने जवाब में कहा कि सर्वे को लेकर जो भी निर्देश दिए गए हैं, वो अवैध है। इसलिए इसे निरस्त किया जाए। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 15 अगस्त 1947 के समय ज्ञानवापी विवादित नहीं था। ऐसे में इस पर कोई भी फैसला नहीं दिया जाना चाहिए।

2. लोअर कोर्ट के फैसले पर

मुस्लिम पक्ष ने लोअर कोर्ट के फैसले को भी अवैध बताया। वहीं हिंदू पक्ष ने कहा कि पहले रिपोर्ट देख लीजिए। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट लीक करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश में एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। इसे सिर्फ एक केस न मानें, देश में बड़ा प्रभाव डालेगा।

3. मस्जिद में नमाज पर

मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ने में दिक्कत हो रही है। अंदर के एरिया को सील कर दिया गया है। इसपर भी ध्यान दिया जाए। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हम आपके सामने अयोध्या मामले में जो फैसला आया था, उसका उदाहरण देना चाहते हैं।

वाराणसी लोअर कोर्ट ने दिया था सर्वे का निर्देश

वाराणसी कोर्ट ने 16 अप्रैल को दिल्ली की रहने वाली राखी सिंह और बनारस की रहने वाली लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की याचिका पर सर्वे का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया था। 18 अगस्त 2021 को चारों महिलाओं ने एक याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी परिसर में हिंदू देवी-देवताओं का स्थान है।

देश में कहीं गर्मी, कहीं बारिश : दिल्ली में बरसे मेघा

असम में बाढ़ से हालात खराब; एमपी में पारा 44 के पार

नई दिल्ली। भारत के कई हिस्सों में भयानक गर्मी पड़ रही है तो कई राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इसी बीच दिल्ली में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई। इससे मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार, 22, 23, 24 मई को भी बारिश हो सकती है। इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

असम में बाढ़ से बिगड़े हालात

असम में भारी बारिश और बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। राज्य में बाढ़ से प्रभावितों की संख्या बढ़कर 7 लाख से ज्यादा हो गई है। 27 जिले अब तक बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। लोग बेघर हो गए हैं, जिसके चलते 48,000 से अधिक लोगों को 248 राहत शिविरों में भेजा गया है। सेना की ओर से लगातार बचाव अभियान चलाया जा रहा है।

केरल में रेड अलर्ट

केरल में भारी बारिश होने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए केरल, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना जताई है। हालांकि, 21 मई के बाद से बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है।

एमपी में गर्मी का तांडव जारी

मध्यप्रदेश में अभी भी गर्मी का तांडव जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक, 22-23 मई के आसपास पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज आंधी के साथ बारिश होने का अनुमान है। वहीं, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत को लोगों को अगले दो दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि, 22 से 24 मई के बाद उत्तर पश्चिम भारत में बारिश हो सकती है।

बिहार में बारिश के बाद भी गर्मी

बिहार में हल्की बारिश के बाद अब उमस बढ़ने लगी है। राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह तेज हवा से थोड़ी राहत मिली, लेकिन दिन में धूप भी रही। यहां का अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री रहा। यह हालात अगले 48 घंटे तक बने रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक, बारिश और तेज हवाएं गर्मी से थोड़ी राहत दिलाने वाली हैं। गुरुवार की रात मौसम ठंडा रहा और शुक्रवार की सुबह पटना से लेकर कई जिलों में हवा की रफ्तार 30 से 35 किमी प्रति घंटे की रही है।

अश्विनी कुमार दिल्ली नगर निगम के विशेष अधिकारी नियुक्त

नयी दिल्ली। केन्द्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अश्विनी कुमार को दिल्ली नगर निगम में विशेष अधिकारी तथा ज्ञानेश भारती को निगमायुक्त नियुक्त किया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कुमार की नियुक्ति संबंधी आदेश तथा भारती की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि श्री कुमार को दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2022 की धारा 514 ए में मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली नगर निगम में विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्त 22 मई यानी रविवार से अगले आदेश तक प्रभावी होगी। निगम में चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होने के मद्देनजर वह निगम से संबंधित दिन प्रतिदिन के कामकाज का निर्वहन करेंगे।

पुणे में दर्दनाक दुर्घटना : दो अलग-अलग डैम में डूबने से 9 लोगों की हुई मौत

मरने वालों में 5 महिलाएं और 4 युवक शामिल

एजेंसी

पुणे। पाचों महिलाएं भाटघर में एक पार्टी में आई थीं। वे डैम पर घूमने चली गईं और नहाते समय डूब गईं। पुणे में गुरुवार शाम दो अलग-अलग डैम में डूबने से 9 लोगों की मौत हुई है। पहली दुर्घटना भोर तहसील के भाटघर में हुई है और दूसरी खेड़ तहसील के चासकमान में।

भाटघर में पांच महिलाओं ने जान गंवाई है तो वहीं, चासकमान डैम में पिकनिक मनाने गए चार युवक डूब गए। दोनों हादसों में 6 शव निकाल लिए गए हैं और अन्य की तलाश जारी है।

शाम 5 बजे भाटघर डैम में हुई दुर्घटना में खुशबू राजपूत (19), मनीषा राजपूत (20), चांदनी राजपूत (21), पूनम राजपूत (22) और मोनिका चव्हाण की मौत हुई है। ये पांचों महिलाएं डैम के पास घूमने के लिए आई थीं और नहाने के लिए पानी में चली गईं।

सभी पुणे की रहने वाली हैं। पानी में डूबी पांच में से चार महिलाओं के शवों को बाहर निकाल लिया गया है।

सेल्फी के चक्कर में डूबी महिलाएं

जांच में सामने आया है कि बांध के किनारे खड़े होकर महिलाएं सेल्फी ले रहीं थीं, इसी दौरान एक महिला का पैर फिसल गया और उसे बचाने के चक्कर में एक-एक करके चार अन्य महिलाएं पानी में कूदी और दुर्घटना का शिकार हुई हैं।

पानी में डूबी पांच में से चार महिलाएं एक ही परिवार से थीं।

स्कूल के चार छात्र पानी में डूबे

चासकमान डैम पर कृष्णमूर्ती फाउंडेशन, सह्याद्री स्कूल के चार स्टूडेंट्स पिकनिक मनाने गए थे। डैम के गेट से निकल रहे पानी में नहा रहा एक साथी डूबने लगा।

उसे बचाते समय बाकी तीन भी डूब गए। इनमें से दो के शव बाहर निकाले जा चुके हैं।

देश में कोरोना के सक्रिय मामले 15 हजार से अधिक

नयी दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण के नये मरीजों का मिलना निरंतर जारी है। इस दौरान हालांकि, सक्रिय मामलों में 375 की कमी आई है, जिसके साथ ही अब इनकी संख्या 15,044 रह गई है। वहीं, देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 2,259 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें गुरुवार के मुकाबले 105 की कमी आई है। गुरुवार को संक्रमित मरीजों की संख्या 2,364 थी। नए मामलों के साथ कुल संक्रमितों की संख्या चार करोड़ 31 लाख 31 हजार 822 हो गई है। हालांकि, इस दौरान मरने वालों का आंकड़ा एक दिन पहले के मुकाबले दोगुनी रही। जहां, गुरुवार को कोरोना की चपेट में आकर दस लोगों ने दम तोड़ा था, वहीं शुक्रवार को मरने वालों की संख्या 20 दर्ज की गई। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या पांच लाख 24 हजार 323 हो गई है।

इस बीच, देश में जारी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 191.96 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में शुक्रवार को 15,12,766 टीके लगाए गए।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 2,614 लोग कोविड से मुक्त हुए हैं और इसी के साथ अब तक कुल चार करोड़ 25 लाख 92 हजार 455 मरीज कोविड से उबर चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.75 प्रतिशत है। वहीं, सक्रिय दर 0.03 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.22 प्रतिशत है।

जम्मू-कश्मीर में रेस्क्यू के दौरान हादसा : रामबन में निर्माणाधीन टनल के बाहर फिर लैंडस्लाइड, 9 मजदूर अभी भी मलबे में फंसे

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के रामबन और रामसू के बीच नेशनल हाईवे पर गुरुवार देर रात निर्माणाधीन टनल का हिस्सा ढह गया। इस हादसे में 9 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। मजदूरों को निकालने के लिए देर रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच शुक्रवार शाम को टनल के बाहर फिर से लैंडस्लाइड हो गया। इससे पहले गुरुवार देर हुए हादसे में वहां काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई।

अब तक 3 मजदूरों को रेस्क्यू किया जा चुका है। मलबे में अभी भी 9 मजदूर फंसे हैं। रामबन के डिप्टी कमिश्नर मर्सरतुल इस्लाम के मुताबिक, फिर से हुए लैंडस्लाइड और तेज आंधी की वजह से बचाव कार्य में बाधा आई है। भूस्खलन के कारण गिरी पहाड़ी के मलबे में दो मशीनें दब गई हैं। इससे बचाव कार्य और बाधित हुआ है।

खूनी नाले पर हुआ हादसा

टनल धंसने का हादसा गुरुवार रात करीब 10 बजे रामबन जिले के मेकरकोट इलाके में जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे के पास खूनी नाले पर हुआ, जहां टनल बनाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, टनल के ढहने के तुरंत बाद पुलिस और सेना ने एक संयुक्त बचाव अभियान शुरू कर दिया था।

इस हादसे में सुरंग के सामने खड़े वाहनों बुलडोजर, ट्रकों सहित कई मशीनों को भी नुकसान पहुंचा है।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, मैं DC मुसरत इस्लाम के लगातार संपर्क में हूं। करीब 10 मजदूर मलबे में दबे हैं, अन्य 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बचाव कार्य जोरों पर चल रहा है। नागरिक प्रशासन और पुलिस अधिकारी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं।

ये मजदूर अभी भी लापता

लापता मजदूरों में 5 पश्चिम बंगाल, दो नेपाल, एक असम और दो जम्मू-कश्मीर के निवासी हैं। इनमें जादव रॉय (23), गौतम रॉय (22), सुधीर रॉय (31), दीपक रॉय (33), परिमल रॉय (38) निवासी पश्चिम बंगाल, नवाज चौधरी (26), कुशी राम (25) निवासी, शिव चौहान (26) निवासी असम, मुजफ्फर (38), इसरत (30) निवासी जम्मू-कश्मीर शामिल हैं।

सीबीआई रेड | **दिल्ली समेत 16 ठिकानों पर छापा, नौकरी के बदले जमीन लेने पर लालू-राबड़ी और दो बेटियों पर एफआईआर**

लालू पर सीबीआई की रेड, अफसरों के साथ धक्कामुक्की

पटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के 16 ठिकानों पर शुक्रवार को CBI ने छापेमारी की है। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर RJD कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी की। अफसरों के साथ धक्कामुक्की और अभद्रता की गई। महिला अफसर नीतू कुमारी को भी घेर लिया। अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। सीबीआई के कई अफसरों को राबड़ी देवी के आवास के मुख्य गेट के बजाए दूसरे गेट से निकाला गया। एक ही कार में सीट से ज्यादा अफसरों को बैठा कर भेजा गया। राजद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर उनकी गाड़ियों पर भी मुक्के मारे।

रेलवे भर्ती बोर्ड के ग्रुप डी में हुई गड़बड़ी के मामले में ये कार्रवाई हुई है। आरोप है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले एक लाख स्क्वॉयर फीट से ज्यादा की जमीन उपहार में ली गई है। रेलवे में नौकरी पाने वाले लोगों के घरों में भी सीबीआई ने छापा मारा है।

सीबीआई ने शुक्रवार को ही लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव समेत 15 लोगों पर केस दर्ज किया। पटना में राबड़ी देवी और बड़े बेटे तेजप्रताप यादव से CBI अलग-अलग कमरों में पूछताछ की। पूछताछ के लिए 3-3 अफसरों की दो टीमें बनाई गई है। वहीं दिल्ली में

मीसा भारती के आवास पर लालू यादव से CBI के एसपी और डीएसपी स्तर के अफसर पूछताछ की। लालू से भर्ती से जुड़ी फाइलों के बारे में जानकारी ली गई।

1 लाख 5 हजार स्क्वॉयर फीट जमीन नौकरी के बदले ली

सीबीआई के विज्ञप्ति के मुताबिक रेल मंत्री रहते हुए लालू ने 2004-2009 के दौरान समूह डी में नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीनें ट्रांसफर कराई। यह जमीन 1 लाख 5 हजार 292 स्क्वॉयर फीट है।

यह सारी जमीन पटना में हैं। ये जमीनें लालू के परिवार से संचालित कंपनी के नाम पर गिफ्ट के तौर पर लिया गया है।

सीबीआई ने कहा है कि यह भी आरोप है कि क्षेत्रीय रेलवे में ऐसी नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था। फिर भी पटना के निवासी नियुक्तियों को , जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में नियुक्ति दी गई।

इन पर एफआईआर

लालू-राबड़ी के अलावा मीसा भारती, हेमा यादव, राज कुमार सिंह,मिथिलेश कुन्नार, अजय कुन्नारी, संजय राय, धर्मेंद्र राय, विकास कुमार, पिंटू कुमार, दिलचंद कुमार प्रेम चंद कुमार, लाल चंद कुमार, हृदयानंद चौधरी, अभिषेक कुमार पर एफआईआर दर्ज की है।

दिल्ली सरकार 27 अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों का करेगी पुनर्विकास, युवाओं को मिलेगी नौकरी

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने हेतु दिल्ली सरकार की ओर से जल्द ही 27 नोटिफाइड औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास किया जाएगा। दिल्ली के उद्योग मत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को औद्योगिक क्षेत्र के संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा उपायों के साथ इन नोटिफाइड औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास पर चर्चा की। सरकार की ओर से इन औद्योगिक इलाकों के पुनर्विकास के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। दिल्ली सरकार ने डीएसआईआईडीसी को इन नोटिफाइड औद्योगिक इलाकों का ले-आउट तैयार करने का काम सौंपा है। डीएसआईआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में

सलाहकार फर्म को नियुक्त करेगी, जो अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्र का ले-आउट तैयार करेंगे। जैन ने बताया कि दिल्ली में कुल 27 नोटिफाइड औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहां कई औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं। इन औद्योगिक इलाकों को इसी आधार पर मंजूरी मिली थी कि इनका पुनर्विकास किया जाएगा, लेकिन सालों से यह मामला पुरानी सरकारों में टरकता रहा। अब केजरीवाल सरकार ने इन इलाकों के पुनर्विकास का बीड़ा उठाया है। इन सभी 27 इलाकों का ले-आउट प्लान तैयार करने की समय सीमा तय की गई है। ले-आउट प्लान तैयार करने वाले सलाहकारों पर दिल्ली सरकार और औद्योगिक संघ मिलकर 50-50 फीसद राशि खर्च करेंगे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों को हरा-भरा, स्वच्छ और बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। साथ ही सीवेज, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र, पेयजल आपूर्ति, औद्योगिक अपशिष्ट निपटान की व्यवस्था और सड़कों को बेहतर किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों में प्रोसेसिंग सेंटर, मान्यता प्राप्त टेस्ट लैब, ट्रेनिंग सेंटर, बिजनेस कन्वेंशन सेंटर, रॉ-मटेरियल बैंक और लॉजिस्टिक्स सेंटर समेत तमाम तरह के सेंटर बनाए जाएंगे।

शार्ट न्यूज

पैंगोंग झील पर एक और पुल बना रहा चीन, भारत ने कड़े विरोध के साथ जारी किया बयान

नई दिल्ली। लद्दाख में पैंगोंग झील पर चीन द्वारा दूसरा पुल बनाने की खबरों पर विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि दोनों पुल 1960 के दशक से चीन के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में हैं। हमने अपने क्षेत्र पर इस तरह के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है, न ही हमने अनुचित चीनी दावे या ऐसी निर्माण गतिविधियों को स्वीकार किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदम बागची ने कहा कि केंद्र ने कई मौकों पर यह स्पष्ट किया है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न अंग हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अन्य देश भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। बयान में आगे कहा गया है कि सरकार ने देश की सुरक्षा के हित में, विशेष रूप से 2014 के बाद से सीमा के बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाया है। बता दें कि एक दिन पहले बागची ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि इस तरह के घटनाक्रम पर भारत नजर रख रहा है।

शीना बोरा हत्याकांडः 6 साल बाद जेल से बाहर आईं इंद्राणी मुखर्जी, सुप्रीम कोर्ट से मिली थी बेल

नई दिल्ली। अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी छह साल से अधिक समय के बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भायखला जेल से बाहर आ गईं। अदालत ने कहा कि जमानत राशि 2 लाख रुपये तय की गई और इंद्राणी को दो सप्ताह के भीतर राशि जमा करनी होगी। 6 साल जेल की सजा काटने के बाद जमानत मिलने पर बाहर आईं इंद्राणी मुखर्जी ने कहा कि वो जेल से बाहर आकर बहुत खुश हैं। बताते चलें कि इंद्राणी मुखर्जी पिछली शादी से अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है। शीना बोरा का 2012 में कथित तौर पर अपहरण कर मर्डर कर दिया गया था। डेड बॉडी मुंबई के बाहरी इलाके में एक गड्ढे में मिला था। इंद्राणी मुखर्जी के अब पूर्व पति और मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी भी दो अन्य लोगों के साथ इस मामले में आरोपी थे। पीटर मुखर्जी भी इस मामले में जेल की सजा काट चुके हैं। पॉवरफुल दंपति के नाम से मशहूर इंद्राणी और पीटर की जोड़ी ने 2007 में आईएनएक्स नेटवर्क स्थापित किया था, लेकिन दो साल बाद गबन के आरोपों के बीच अपनी हिस्सेदारी बेच दी। प्रवर्तन निदेशक ने आरोप लगाया था कि 2008 में कार्ति चिदंबरम ने दंपति को उनके उद्योग में करोड़ों के विदेशी निवेश के लिए मंजूरी दिलाने में मदद की थी। जिसके लिए उन्हें कथित रूप से रिश्वत भी मिली थी। मामले की अभी जांच की जा रही है।

दैनिक भुगतान में देरी से स्पाइसजेट की कुछ उड़ानें दिल्ली एयरपोर्ट पर रोकी गईं, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली। स्पाइसजेट की कुछ उड़ानें शुक्रवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ समय के लिए रोकी गईं क्योंकि एअरलाइन द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को किए जाने वाले दैनिक भुगतान में देरी हो रही थी। सूत्रों के अनुसार, एअरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण दैनिक भुगतान में देरी हुई और उड़ानें अब सामान्य रूप से चल रही हैं। एएआई ने 2020 में स्पाइसजेट एयरवेज को कैश एंड कैरी के आधार पर रखा था क्योंकि वह अपने पिछले बकाया को चुकाने में असमर्थ था। कैश एंड कैरी मॉडल के तहत एअरलाइन को उड़ानें संचालित करने के लिए नेविगेशन, लैंडिंग, पार्किंग और अन्य विभिन्न शुल्कों का दैनिक भुगतान एएआई को करना पड़ता है। शुक्रवार की घटना के बारे में पूछे जाने पर स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा कि तकनीकी खराबी के कारण, स्वचालित दैनिक भुगतान की प्रक्रिया नहीं हो सकी। प्रवक्ता ने कहा कि यह एएआई को मैन्युअल रूप से किया जा रहा है, जिसे इस मुद्दे से अवगत कराया गया है। स्पाइसजेट का उड़ान परिचालन अब सामान्य रूप से जारी है।

अवैध हथियार गिरोह का पर्दाफाश, 10 देसी पिस्तौल बरामद

चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस ने अवैध हथियार बनाकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 देसी पिस्तौल और एक देसी डोगा बरामद किया है। पुलिस के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि पकड़ा गया आरोपी और उसके साथी खेतों में कच्ची नालियों में बैठकर अवैध हथियार बनाते थे और करीब 3000 से 4000 रुपए में बेचते थे। गिरफ्तार आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के हाथियाहाल नंगला के हाजी हनीफ के रूप में हुई है। महेन्द्रगढ़ जिले में पुलिस की सीआईए टीम ने अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत हनुमान उर्फ कालिया को काबू कर उसके कब्जे से एक देशी डोगा, एक रिवॉल्वर और छह कारतूस बरामद किए थे। पूछताछ में आरोपी ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले समीन उर्फ समीर के बारे में बताया, जिसे एक देशी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस सहित मेवात क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। समीन से पूछताछ में पुलिस का पता चला कि मथुरा जिले के हाजी हनीफ भी उनके गिरोह में शामिल है जो अवैध हथियार लाकर बेचता है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे काबू कर। इस दौरान आरोपी से 10 देसी पिस्तौल, एक देसी डोगा और भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने का सामान भी बरामद हुआ। अब तक तीनों आरोपियों के कब्जे से 11 देसी पिस्तौल, दो देसी डोगा, एक रिवाल्वर सहित 14 अवैध हथियार और आठ कारतूस बरामद किए हैं।

सरकार बताये किसानों की आमदनी दुगनी कब होगी : दीपेंद्र हुड्डा

सिरसा। सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बताए कि 2022 तो आ गया, किसान की आमदनी दोगुनी कब होगी ? हुड्डा यहाँ डबवाली में एक सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 2022 का पांचवां महीना चल रहा है और इस मुद्दे पर सरकार में बैठे लोगों की बयानबाजी बंद हो गयी है। उन्होंने कहा कि कहीं किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वायदा भी हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख और हर साल दो करोड़ नौकरियों वाले जुमलों की लिस्ट में तो नहीं शामिल कर दिया गया। सांसद ने कहा कि 29 मई को फतेहाबाद में 'विपक्ष आपके समक्ष' का नारा होगा 'गेहूं पर 500 रुपये क्विंटल बोनस दो, रिक्त पदों की भर्ती खोलो'।

ज्ञानवापी मस्जिद मामले की वाराणसी कोर्ट में ही होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया केस

नई दिल्ली। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम जिला जज पर सवाल नहीं उठा सकते, उनके पास 25 सालों का अनुभव है। इसके साथ ही कोर्ट ने %शिवलिंग% मिलने वाले स्थान को सील रखने और मुस्लिमों को सीमित संख्या में नमाज पढ़ने देने और अलग स्थान पर वजू करने के अपने अंतरिम आदेश को भी जारी रखा है। कोर्ट ने कहा कि 17 मई को लागू किया गया यह आदेश 8 सप्ताह यानी 17 जुलाई तक लागू रहेगा। उसके बाद ही इस मामले की शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जटिल सामाजिक समस्याएं हैं। इसमें मनुष्य द्वारा किया गया कोई भी समाधान सटीक नहीं हो सकता। हमारा आदेश इस बात पर था कि शांति व्यवस्था बनी रहे। यह काम अंतरिम आदेश से हो सकता है। हम देश की एकता के लिए एक संयुक्त मिशन पर हैं। इसके अलावा रिपोर्ट लीक होने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार

यहां रिपोर्ट आ जाए तो फिर वह सेलेक्टिव तौर पर लीक नहीं हो सकती। इसके साथ ही बेंच ने हिदायत दी कि रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ जज ही खोल सकते हैं।

हिंदू पक्ष बोला, प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट के दायरे में नहीं यह मामला

हिंदू पक्ष ने कहा कि यह मामला 100 साल से पुराना है और यह 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट के दायरे में नहीं आता है। ऐसे में इस केस की सुनवाई और सर्वे के लिए कोर्ट कमिशन के गठन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।

मुस्लिम पक्ष ने उठाया सवाल, आखिर लीक कैसे हो गई सर्वे रिपोर्ट

सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर सर्वे रिपोर्ट लीक कैसे हो गई। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने सर्वे के लिए कोर्ट कमिशन के गठन को भी असंवैधानिक करार दिया। इसके अलावा उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का सुझाव दिया। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला जज के फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, उनका 25 साल का लंबा अनुभव है और उन्हें सुनवाई करने देना चाहिए। बेंच ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि शांति, सौहार्द और भाईचारा बना रहे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला जज अनुभवी न्यायिक अधिकारी होते हैं, हम उन्हें आदेश जारी नहीं कर सकते।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में टली सुनवाई, अब 6 जुलाई की तारीख

इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी शुक्रवार को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन यह टाल दी गई। वाराणसी के अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने सुनवाई की अगली तारीख छह जुलाई तय की। इस केस में मूल वाद वर्ष 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में दायर किया गया था, जिसमें वाराणसी में जहां ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है, वहां प्राचीन मंदिर बहाल करने की मांग की गई थी। वाराणसी की अदालत ने आठ अप्रैल, 2021 को पांच सदस्यीय समिति गठित कर सदियों पुरानी ज्ञानवापी मस्जिद का समग्र भौतिक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था।

दिल्ली को दिया जा रहा है, उसके हक का पूरा पानी : सीएम खट्टर

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हरियाणा की ओर से उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार दिल्ली को उसके हक का 1049 क्यूसेक पूरा पानी दिया जा रहा है।

खट्टर ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हालांकि हरियाणा को खुद पानी की किल्लत है लेकिन इसके बावजूद दिल्ली को उसके हिस्से का पूरा पानी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी दिल्ली जल बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है तो यह साबित हुआ है कि हरियाणा के मूनक हेडवर्क्स से दिल्ली को उसके हिस्से के 719 क्यूसेक के मुकाबले 1049 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ रहा है लेकिन दिल्ली सरकार गलत बयानबाजी कर ओछी राजनीति कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी के मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय, दिल्ली सरकार को पंजाब सरकार को जल्द से जल्द हरियाणा के वैध हिस्से का पानी देने के ?लिए मनाना चाहिए। जिस दिन पंजाब, हरियाणा को उसके हिस्से का पूरा पानी दे देगा तब दिल्ली को और अधिक पानी मिल सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को यह समझना चाहिए कि उनकी पेयजल की आवश्यकता को पूरा करना अकेले हरियाणा की जिम्मेदारी नहीं है। वह भी जल प्रबंधन योजनाएँ बनाने की दिशा में कार्य कर सकती है।

श्री खट्टर ने कहा कि गत कुछ दिनों में प्रदेश में 1800 मेगावाट तक बिजली की कमी चल रही थी। वर्तमान समय में बिजली की मांग गत वर्ष की तुलना में 700 से 800 लाख यूनिट अधिक है। इस समय राज्य की अधिकतम मांग 9874 मेगावाट तक पहुंच गई है जबकि बिजली की आपूर्ति भी 9874 मेगावाट है। गत 16 मई से खपत के बराबर बिजली आपूर्ति करने में सफल रहे हैं। अडाणी की यूनिटों से भी 600 मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो गई है तथा वहां से और भी बिजली मिलने की सम्भावना है। आगामी 30 मई तक खेदड़ यूनिट-2 से अतिरिक्त 600 मेगावाट बिजली उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है। इसी तरह 26 मेगावाट सौर और पवन ऊर्जा मिलने लगी है और 15 जून तक 127 मेगावाट सौर ऊर्जा और भी उपलब्ध हो जाएगी। धान रोपाई के लिये बिजली की जरूरत पूरी करने के जम्मू-कश्मीर से 300 मेगावाट बिजली का प्रबंध किया गया है।

पेगासस मामला : सुप्रीम कोर्ट ने जांच रिपोर्ट सौंपने की समय-सीमा बढ़ाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए उसके द्वारा नियुक्त तकनीकी और निगरानी समितियों के रिपोर्ट सौंपने की समय-सीमा शुक्रवार को बढ़ा दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि इजराइली स्पाईवेयर के सिलसिले में 29 प्रभावित मोबाइल फोन की जांच की जा रही है और यह प्रक्रिया चार हफ्ते में पूरी हो जानी चाहिए। चीफ जस्टिस एन. वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि तकनीकी समिति स्पाइवेयर को लेकर प्रभावित मोबाइल फोन की जांच कर रही है और उसने पत्रकारों समेत कुछ लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। पीठ ने कहा कि प्रभावित उपकरणों की जांच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि तकनीकी समिति की जांच मई के अंत तक पूरी हो सकती है और फिर पर्यवेक्षी न्यायाधीश पीठ के विचार के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। पीठ के सदस्यों में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल हैं। पीठ ने एक अंतरिम रिपोर्ट मिलने का जिक्र करते हुए कहा कि तकनीकी समिति, जिसने स्पाईवेयर की जांच के लिए 29 मोबाइल फोन प्राप्त किये हैं, ने इस उद्देश्य (जांच) के लिए अपना सॉफ्टवेयर विकसित किया है और कुछ सरकारी एजेंसियों तथा पत्रकारों सहित व्यक्तियों को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा, %अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए वक्त देने का अनुरोध किया गया है। अब, यह प्रक्रिया के तहत है। हम उन्हें वक्त देंगे। पीठ ने कहा, तकनीकी समिति की प्रक्रिया चार हफ्तों में पूरी हो जानी चाहिए और पर्यवेक्षी न्यायाधीश को सूचित किया जाना चाहिए। वह उसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। (सुनवाई) जुलाई में किसी तारीख के लिए सूचीबद्ध की जाए। हालांकि, पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा किये गये अनुरोध से जुड़ा कोई आदेश नहीं जारी किया, जो कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हो रहे हैं। उन्होंने अंतरिम रिपोर्ट पक्षकरों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

फर्जी था हैदराबाद एनकाउंटर, पुलिस वालों पर चले हत्या का केस; पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट

नई दिल्ली। हैदराबाद में 2019 में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के 4 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया था। लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित किए गए पैनल ने फर्जी करार दिया है। पैनल ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी और 2019 में हुई मुठभेड़ को फर्जी करार दिया। इसके साथ ही एनकाउंटर में शामिल 10 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का केस चलाए जाने की भी सिफारिश की। पैनल ने कहा कि पुलिस की ओर से दावा किया गया था कि रेप और हत्या के आरोपियों ने उनसे पिस्तौल छीन ली थी और भागने का प्रयास किया था, लेकिन ये गलत पाए गए हैं।

पैनल ने साफ कहा- पुलिस के दावों पर नहीं कर सकते यकीन

पैनल ने कहा कि पुलिस की ओर से किए गए दावों पर विश्वास नहीं किया जा सकता और मौके पर मिल सबूत भी इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिसकर्मियों ने जानबूझकर गोलियां चलाई थीं और उन्हें पता था कि ऐसा करने पर उन लोगों की मौत भी हो सकती है। इसलिए यह एनकाउंटर फर्जी है और पुलिस के दावे गलत प्रतीत होते हैं। बता दें कि इसी साल जनवरी में जस्टिस सिरपुकर कमिशन ने सुप्रीम कोर्ट को इस एनकाउंटर के मामले में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी थी। यह रिपोर्ट सील लिफाफे में दी गई थी, जिसे लेकर अब जाकर खुलासा हुआ है।

टोल प्लाजा से डॉक्टर को किडनैप कर हुई थी दरिंदगी

बता दें कि 2019 में 27 साल की पशु चिकित्सक को किडनैप कर लिया गया था। इसके बाद उनके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और उनकी हत्या कर शव को दरिंदे एक पुल के नीचे फेंक दिया था। उन्हें एक टोल प्लाजा के पास से किडनैप किया गया था। उनके शव को जला दिया गया था और सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया था। आरोपी मोहम्मद आरिफ, सी. चेन्नाकेशवुलु, जोलु शिवा और जोलु नवीन को पुलिस ने नवंबर 2019 में ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 6 दिसंबर को इन लोगों का एनकाउंटर किए जाने की घटना उस वक्त सामने आई थी, जब पुलिस उन्हें सबूतों की तलाश में क्राइम सीन पर ले गई थी।

कोरोना और लॉकडाउन के चलते जांच रिपोर्ट में हुई देरी

पुलिस का कहना था कि आरोपियों ने पिस्तौल छीनकर भागने का प्रयास किया था। इसी दौरान एनकाउंटर में वे मारे गए। इस मुठभेड़ ने देश भर में चर्चा बटोरी थी। इसके बाद मामले की जांच के लिए एक कमिशन का गठन किया गया था। हालांकि जुलाई 2020 में कमिशन ने कहा था कि देश भर में लॉकडाउन लगा है। ऐसे में वह फिलहाल अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप सकता है।

6 करोड़ आबादी वाला फ्रांस राफेल बना रहा, 130 करोड़ का देश मंदिर-मस्जिद खोद रहा: शिवसेना

मुंबई। शिवसेना ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। मुखपत्र सामना में प्रकाशित संपादकीय के जरिए शिवसेना ने कहा है कि इन मुद्दों के जरिए ही भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव इन मुद्दों पर लड़ेगी। साथ ही पार्टी ने भारत की तुलना फ्रांस से की है और काशी-मथुरा मामले को लेकर कश्मीर घाटी में हिंदू पंडितों के दमन का मुद्दा उठाया है।

शुक्रवार को सामना हिंदी में प्रकाशित संपादकीय के अनुसार, साढ़े 6 करोड़ जनसंख्या वाला देश फ्रांस 'राफेल' बनाकर हमें बेच रहा है और 130 करोड़ लोगों का देश रोज मंदिर-मस्जिद और अवशेषों का उत्खनन कर रहा है। इसी को कुछ लोग विकास

समझते होंगे तो उन्हें साष्टांग दंडवत। इस दौरान पार्टी ने काशी-मथुरा, ताजमहल, जामा मस्जिद को लेकर जारी खबरों का भी जिक्र किया।

पार्टी ने कहा, भाजपा के विकास का मॉडल इस तरह से चल रहा है। हनुमान चालीसा, भोंगा प्रकरण बहुत ज्यादा नहीं चला। हर बार कोई नई राम कहानी अथवा कृष्ण कथा रची जाती है। इसका मूल रामायण-महाभारत से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन लोगों को उकसाते रहना है, ऐसा धंधा चल रहा है।

शिवसेना ने सरकार पर कश्मीर घाटी की स्थिति की अनदेखी करने के भी आरोप लगाए हैं। पार्टी ने लिखा, 'अयोध्या तो झांकी है, काशी-मथुरा बाकी है' यह घोषणा हिंदुत्ववादियों को सुख पहुंचानेवाली है ही, परंतु कश्मीर घाटी में हिंदू पंडितों का जो दमन फिर से शुरू हुआ है, वह मुद्दा भी काशी-मथुरा जितना ही गंभीर है। उस ओर सुविधानुसार अनदेखी चल रही है।

संजय राउत ने भी उठाए सवाल

बीते सप्ताह राउत ने कहा था कि राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद और ऐसे में जब भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो देश को स्थिरता की जरूरत है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राउत ने कहा, मुझे लगता है कि 2024 की तैयारियां इस तरह से की जा रही हैं कि देश में तनाव पैदा करने के लिए सभी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की खुदाई की जा रही है।

रामबन की सुरंग में फंसे 10 मजदूर, एक शव बरामद : अधिकारी

जम्मू। जम्मू- कश्मीर के रामबन जिले के जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक निर्माणाधीन सुरंग के ढहने से मलबे में कम से कम 10 मजदूर फंसे हुए हैं। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने यूनीवार्ता से कहा, मलबे से एक शव को निकाला गया है और बचाव अभियान जारी है। कुमार ने अतिरिक्त जम्मू जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) मुकेश सिंह के साथ बचाव अभियान की निगरानी के लिए घटना स्थल का दौरा किया। अधिकारियों ने कहा, गुरुवार रात लगभग सवा दस बजे, खूनी नाला रामबन के पास, अजीत सुरंग की टी-3 साइट पर काम कर रहे सरला कंपनी के 12 से अधिक मजदूरों के सुरंग के मलबे में फंसने की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि दो मजदूरों को बचाया गया है और उन्हें रामबन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां से झारखंड निवासी विष्णु गोला (33) को जीएमएस जम्मू भेजा गया है। लापता मजदूरों में जादव रॉय (23), गौतम रॉय (22) सुधीर रॉय (31), दीपक रॉय (33) परिमल रॉय (38) हैं। ये सभी पश्चिम बंगाल निवासी है। शिव चौहान (26) असम से, नवराज चौधरी (26) और कुशी राम (225) दोनों नेपाल से, मुजफ्फर (38) और इसरत (30) दोनों स्थानीय निवासी है।

कुपवाड़ा में सेना ने घुसपैठ को किया नाकाम, एक आतंकवादी ढेर

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती जिला कुपवाड़ा में सेना ने शुक्रवार को घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक आतंकवादी का मार गिराया है। सुरक्षा सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में सेना के सतर्क जवानों ने नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध गतिविधि देखी, सेना ने घुसपैठियों को ललकारा और घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा, सेना ने घुसपैठ रोधी अभियान शुरू किया गया, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया और अभियान अभी जारी है। उन्होंने कहा कि मारे गए आतंकवादी की पहचान और वह किस समूह के लिए काम करता है उसकी अभी जानकारी सामने नहीं आयी है। सेना ने इस संबंध में अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की है। अभियान अभी भी जारी है।

कश्मीरः आग दुर्घटना में थाना क्षतिग्रस्त

श्रीनगर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में रेजीडेंसी रोड पर स्थित कोठी बाग थाना आग दुर्घटना में जलकर खाक हो गया, जिसमें ऑपरेशन के दौरान दमकल और आपातकालीन कर्मियों को भी चोटें आईं। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि श्रीनगर में बुधवार को यातायात पुलिस मुख्यालय भी आग लगने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, इस दुर्घटना में मुख्यालय में जमा सभी रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचा। आग और आपातकालीन अधिकारियों ने कहा कि रेजीडेंसी रोड पर कोठीबाग थाना में गुरुवार देर रात को अचानक लगी आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने बताया कि सिटी सेंटर स्टेशनों से 12 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसी दौरान एक दमकल कर्मी अंसार अहमद घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों ने बताया कि आग में कुछ रिकॉर्ड क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुलिस थाने से हथियार और गोला बारूद को सुरक्षित निकाल लिया गया। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

DUSR और BYST के बीच हुआ सहयोग सहमति समझौता

कौशल पुनरुत्थान डिजिटल विश्वविद्यालय और बजाज-ऑटो भारतीय युवा शक्ति संस्था के बीच सहयोग सहमति समझौता हुआ है। इस समझौते के अनुसार DUSR और BYST ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के दौरान संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करेंगे साथ ही उद्यमशीलता विकास और व्यावसायिक मार्गदर्शन में एक दूसरे का समन्वय और सहयोग करेंगे। इस सहयोग सहमति समझौते के अनुसार DUSR और BYST उद्यमियों की सोर्सिंग और संयुक्त रूप से उद्यमिता विकास पर जागरूकता पैदा करने की गतिविधियों का आयोजन करेंगे जो युवा भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। इस समझौते में इस बात का भी उल्लेख है कि DUSR और BYST जब भी संभव हो एक-दूसरे को बैठक/कार्यशाला सुविधाएं प्रदान कराएंगे व नेटवर्किंग और लिंकेज विकसित करने में एक दूसरे की सहायता करेंगे। बता दें कि इस सहयोग सहमति समझौते से दोनों संस्थाओं से जुड़े युवाओं को विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करते हुए आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। DUSR और BYST के बीच हुआ यह समझौता दोनों संस्थाओं की प्रतिबद्धता और सहयोग को मजबूती प्रदान करते हुए युवाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

क्या है BYST

बजाज -ऑटो भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट व्यवसाय और (नौकरी चाहने वालों को नौकरी देने वालों में बदलना) यूथ फ़ोरल्ड का पसंदीदा भारतीय युवा उद्यमिता विकास कार्यक्रम है। BYST1992 में एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में शुरू किया गया था, जो 18-35 वर्ष के आयु वर्ग में वंचित युवा उद्यमियों - इच्छुक और मौजूदा दोनों की सहायता के लिए तत्पर है। ट्रस्ट को भारत के प्रमुख व्यवसायों का सामूहिक समर्थन प्राप्त है। BYST युवा वंचित उम्मीदवारों को सहायता प्रदान करता है जो अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करना या विकसित करना चाहते हैं। इस सहायता में वित्तीय मार्गदर्शन और बैंकों से जुड़ाव, व्यावसायिक सलाह, प्रशिक्षण, शिक्षा और उद्यम के स्थिर होने तक मार्गदर्शन शामिल है। BYST की अनूठी विशेषता गुरु-शिष्य परंपरा को अपनाना और अभ्यास करना है। मेंटर्स (गुरु) उद्यमियों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखते हैं, व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, उनकी प्रगति की निगरानी करते हैं, और समस्याओं को सुलझाने और व्यवसाय को विकसित करने में मदद करते हैं। BYST द्वारा समर्थित उपक्रमों में एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है, उदाहरण के लिए - हस्तशिल्प, फर्नीचर बनाना। सौंदर्य प्रसाधन और डिटर्जेंट बनाना, खानपान सेवाएं, डेस्कटॉप प्रकाशन, जातीय डिजाइनर वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक घटक और सिस्टम, इंजीनियरिंग, चमड़ा उद्योग और कई अन्य गतिविधियाँ। बीवाईएसटी के दस प्रतिशत उद्यमी एक करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के साथ करोड़पति बन गए हैं। BYST समाज की बड़ी वंचित आबादी तक पहुंचने के लिए, नए उद्यमियों और सलाहकारों को स्रोत बनाने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ सक्रिय रूप से भागीदारी करता है, इस प्रकार सफल होने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

क्या है DUSR

कौशल पुनरुत्थान डिजिटल विश्वविद्यालय (एक आभासी मेटा विश्वविद्यालय) गैर सरकारी संगठन-व्यवहारिक विकास एवं शोध संस्था की एक इकाई है जो वर्ष 2002-03 में संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। कौशल पुनरुत्थान डिजिटल विश्वविद्यालय ऑनलाइन माध्यम से संचालित एक आभासी मेटा विश्वविद्यालय है जो युवाओं में व्यावसायिक कौशल विकसित करने, व्यावसायिक उद्यमी नागरिकों में व्याप्त कौशल को अद्यतन करने तथा भारतीय ज्ञान पद्धति ,जीवन मूल्य और कौशल विकास को केंद्रीभूत करके कार्य करने के लिए संकल्पित है। कौशल पुनरुत्थान डिजिटल विश्वविद्यालय शैक्षिक तकनीक को आत्मसात करके मानव जीवन व्यवहार के सभी प्रमुख आयामों पर केंद्रित व्यावहारिक-व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण को प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

शार्ट न्यूज

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने नई दिल्ली जिले में पोल खोल अभियान के तहत लोगों से किया जनसंपर्क

नई दिल्ली। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय ने कहा कि आज लोगों के अंदर केजरीवाल सरकार को लेकर गुस्सा है क्योंकि सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान जो भी वायदा किया है, वह पूरी तरह से खोखला साबित हुआ है। डीटीसी बस घोटाला हो, निगम के पैसे को न देना हो, कोरोना काल के दौरान लोगों के अंदर डर पैदा करना हो, जैसे मुद्दों ने केजरीवाल की सच्चाई को सबके सामने उजागर किया है और यह साबित किया है कि केजरीवाल की कथनी और करनी में काफी अंतर है। आज नई दिल्ली जिले के जनपथ, रोज गार्डन और बंगाली मार्किट में केजरीवाल सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान के दौरान जनसंपर्क करते हुए श्री सतीश उपाध्याय ने कहा कि कोरोना काल के दौरान दिल्ली सबसे बदतर स्थिति में थी, उस समय केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने लोगों के अंदर ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों में बेड न मिलने का डर दिखाकर भय पैदा करने का काम किया। जबकि ऑक्सीजन की कालाबाजारी उन्हीं के लोग करते पकड़े गए। लोग मूल सुविधा न मिलने की वजह से 1000 किलोमीटर तक पैदल चलकर अपने राज्यों को पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोगों की मदद करने की जगह केजरीवाल और उनके मंत्री क्वारंटाइन हो गए जबकि भाजपा कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद की थी। सतीश उपाध्याय ने कहा कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने लोगों को सपने दिखाए वे चाहे स्वच्छ जल घर-घर पहुंचाने की बात हो, सीसीटीवी लगवाने की बात हो, पूरे दिल्ली में वाई-फाई लगाने की बात हो या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य की बात हो, हर मुद्दे पर दिल्लीवालों को केजरीवाल ने निराश किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता जाग चुकी है। आज केजरीवाल सरकार एक्सपायर्ड डीटीसी बसों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। इस मौके पर नई दिल्ली जिला अध्यक्ष श्री प्रशांत शर्मा सहित प्रदेश, मोर्चा, जिला एवं मंडल के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

एसडीएमसी शिक्षा समिति की अध्यक्षा नीतिका शर्मा ने एसडीएमसी शिक्षा विभाग के निदेशक को पत्र लिखकर हेल्प डेस्क बनाने की मांग की

नई दिल्ली। एसडीएमसी शिक्षा समिति की अध्यक्षा सुश्री नीकिता शर्मा ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग के निदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि एसडीएमसी के विद्यालयों में 3,20,000 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिन्हें विभिन्न तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे मिड-डे मील, वर्दी, किताबें, वजीफा, बैग, कन्या प्रोत्साहन राशि, खेल सामाग्री इत्यादी। ये सभी सुविधाएं बच्चों को सही समय पर मिल रही हैं या नहीं, इसकी जानकारी लेना भी हमारा कर्तव्य है। इसके लिए एक काल सेंटर या हेल्प डेस्क की जरुरत है। नीकिता शर्मा ने अपने पत्र में लिखा है कि हमारे द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं सभी बच्चों को सुचारु रुप से मिल रही है या नहीं इसके लिए जरुरी है कि हम अभिभावकों से सीधा संपर्क करें। इसके साथ-साथ हेल्प डेस्क या काल सेंटर के माध्यम से अगर किसी विद्यार्थी के अभिभावक भी समस्त योजनाओं के बारे में जानना चाहें तो वह कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की सुविधा होने से अभिभावक भी सीधे तौर पर विद्यालयों से जुड़ सकेंगे और अपनी बातों को रख पाएंगे।

आम्रपाली बिल्डर पर कसा सीबीआई का शिकंजा, 230 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का केस दर्ज

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आम्रपाली लेजर वैली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक अनिल शर्मा एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ 230 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सीबीआई अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि कंपनी ने कथित तौर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आंध्रा बैंक के साथ 230 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है। एफआईआर के मुताबिक, इन बैंकों ने उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के टेक जोन-4 इलाके में 1.06 लाख वर्ग मीटर भूखंड पर एक आवासीय भवन विकसित करने के लिए लोन की मंजूरी दी थी। कंपनी यह कर्ज चुकाने में विफल रही, जिसके बाद 31 मार्च, 2017 को उनके खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित कर दिया गया था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शिकायत में आरोप लगाया है कि इस रवैये से बैंक को 230.97 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। आम्रपाली समूह के फ्लैट खरीदारों के एक समूह ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में वादा किए गए फ्लैटों की समय पर आपूर्ति नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी। आम्रपाली डेवलपर्स का 42,000 फ्लैट विकसित करने और बेचने का वादा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया था। सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) एवं धारा 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

दिल्ली के मंगोलपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान रद्द

नई दिल्ली। उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में शुक्रवार को शुरू होने वाला अतिक्रमण विरोधी अभियान पर्याप्त पुलिस बल की अनुपलब्धता के कारण रद्द कर दिया गया। एनडीएमसी ने कहा कि पर्याप्त पुलिस बल की अनुपलब्धता के कारण बुधवार और गुरुवार को भी सुल्तानपुरी के मछली बाजार और जगदंबा मार्केट में अतिक्रमण विरोधी अभियान रद्द कर दिया गया था। उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के एक अधिकारी के मुताबिक, मंगोलपुरी के कटरान मार्केट इलाके में सड़कों और सरकारी जमीन से अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाना तय था। अधिकारी ने बताया कि मंगोलपुरी के कटरान मार्केट के आसपास के इलाकों में शुक्रवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जाना था, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल की अनुपलब्धता के कारण इसे रद्द कर दिया गया। पिछले महीने, दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को इसी कारण से जसोला-सरिता विहार में अपना डेमोलिशन ड्राइव रद्द करनी पड़ी थी। शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, मदनपुर खादर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मंगोलपुरी, रोहिणी, गोकुलपुरी, लोधी कॉलोनी, जनकपुरी सहित शहर के विभिन्न हिस्सों में पिछले एक महीने में तीन नगर निकायों द्वारा कई अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए गए हैं। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में अवैध ढांचों को बुलडोजर गिराए जाने के बाद एनडीएमसी पिछले महीने कई नागरिक अधिकार समूहों और विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई थी। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इस अभियान को रोक दिया गया था।

दिल्ली में कोरोना के 530 नए केस, एक्टिव मरीजों की संख्या अभी भी 2229

नई दिल्ली। दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना के 530 नए मामले सामने आए। जबकि 678 लोग रिकवरी के साथ घर लौटे। हालांकि अभी भी राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2229 है। शुक्रवार को दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना केसों में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 530 नए केस दर्ज किए गए। कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई साथ ही, 678 लोगों ने रिकवरी की और घर लौटे। हालांकि दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2229 है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर घटकर 2.17 प्रतिशत पहुंच गई है। दिल्ली में अभी भी कंटेनमेंट जोन की संख्या 895 है। स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने कहा कि दिल्लीवासियों को अभी भी कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। साथ ही सोशल डिस्टेसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य है।

केजरीवाल सरकार द्वारा गढ़ी मांडू में विकसित किया गया दिल्ली का पहला 'गौरेया ग्राम'

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गौरेया ग्राम का किया दौरा

प्रफुल्ल राय गौरवशाली भारत

नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री गोपाल राय ने आज बताया की दिल्ली में स्थित गढ़ी मांडू सिटी फॉरेस्ट में दिल्ली का पहला गौरेया ग्राम विकसित किया गया हैं। दिल्ली के राज्य पक्षी गौरेया को संरक्षित करने के उद्देश्य गढ़ी मांडू में गौरेया ग्राम बनाया गया है। गौरेया ग्राम में कीट घर और तितलियों के लिए नेचुरल हैबिटैट को भी विकसित किया गया है। दिल्ली के पर्यावरण एवं वन मंत्री गोपाल राय ने आज वन एवं वन्यजीव विभाग के अधिकारियों के साथ इस गौरेया ग्राम का आज दौरा किया। नुक्कड़ नाटक की मदद से उपस्थित लोगों को गौरेया पक्षी के बारें में भी अवगत कराया गया। इस गौरेया ग्राम में तितलियों के भी नेचुरल हैबिटैट का विकास किया गया हैं। साथ ही सामान्य जनता के लिए हर्बल गार्डन की सुविधा भी उपलब्ध कराइ गई हैं।

गौरेया ग्राम के दौरे के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए बताया कि दिल्ली के अंदर पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए और प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हर उचित कदम उठा रही हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दिल्ली के राज्य पक्षी गौरेया की प्रजाति को बचाए रखने के लिए, सरकार ने गढ़ी मांडू सिटी फॉरेस्ट में दिल्ली का पहला गौरेया ग्राम विकसित किया गया हैं। इस गौरेया ग्राम का मुख्य उद्देश्य गौरेया पक्षी को इकोलॉजिकल सपोर्ट देना हैं।

उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले गौरैयों की संख्या में तेजी से गिरावट हुई है। कई अध्ययनों ने इसे दिल्ली में बढ़ रहें शहरीकरण और कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग और विद्युत चुम्बकीय विकिरण को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। कृषि में बढ़ रहें कीटनाशकों के उपयोग से गौरेया पक्षियों के लिए भोजन की कमी हो गई हैं , जिसके कारण उनकी प्रजाति भी धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राज्य पक्षी गौरेया के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस गौरेया ग्राम का विकास किया जा रहा हैं।

क्या हैं गौरेया ग्राम की विशेषताएँ ?

पर्यावरण एवं वन मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के पहले गौरेया ग्राम के बारें में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में पहले फेज में तैयार किए जाने वाले वर्ल्ड क्लास लेवल 4 सिटी फॉरेस्ट के नामो में शुमार गढ़ी मांडू सिटी फॉरेस्ट में दिल्ली का पहला गौरेया ग्राम तैयार किया गया हैं। इस गौरेया ग्राम में दिल्ली के राज्य पक्षी गौरैया के जीवन चक्र का चित्रण किया गया है। यहाँ गौरेया पक्षियों के खाने के लिए कीट घर बनाए गए हैं ताकि पक्षियों को भोजन के लिए भटकना ना पड़े। साथ ही शहरों में नेस्टिंग होल की कमी को देखते हुए यहाँ नेस्टिंग होल का निर्माण भी किया गया हैं।

उन्होंने बताया कि गौरैया के लिए यहां विभाग द्वारा करोंदा और कुंडली जैसे देशी जामुन, घास और झाड़ियां लगाई हैं। इसके साथ ही गौरैया ग्राम में फीडर बाक्स, कृत्रिम घोंसले और मिट्टी के बर्तन भी रखे गए हैं। इसके साथ साथ तितलियों के लिए भी नेचुरल हैबिटैट का विकास किया गया हैं। जिसके कारण उनकी संख्या में पहले से काफी वृद्धि देखि गई हैं।

सामान्य जनता के लिए बनाया गया हर्बल गार्डन

पर्यावरण एवं वन मंत्री गोपाल राय ने बताया कि गौरेया ग्राम में गौरेया पक्षी के साथ साथ आम जनता के लिए भी सुविधा विकसित की गई हैं। गौरेया ग्राम में सामान्य जनता के लिए हर्बल गार्डन भी खोला गया है। इस हर्बल गार्डन से लोग औषधीय पौधों को मुफ्त में अपने घर उपयोग के लिए ले जा सकते हैं। इनमे पत्थर चट्टा अजवायन, तुलसी , एलोवेरा आदि पौधे शामिल हैं।

दिल्ली में वर्ल्ड क्लास लेवल पर तैयार किए जाएँगे 4 सिटी फॉरेस्ट

दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए वन एवं वन्य जीव विभाग ने दिल्ली के चारों कोनो में मौजूद मुख्य 4 सिटी फारेस्ट को पहले प्रारंभिक फेज में विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया हैं।

इनमे दक्षिण पश्चिम दिल्ली का मित्राओं सिटी फारेस्ट , उत्तरी दिल्ली का अलीपुर सिटी फारेस्ट , पूर्वी दिल्ली का गढ़ी मांडू सिटी फारेस्ट और दक्षिण दिल्ली का जौनापुर सिटी फारेस्ट शामिल है। यह चारों सिटी फारेस्ट दिल्ली के लगभग 286 एकड़ में फैले हुए हैं। इस परियोजना के तहत मित्राऊ सिटी फारेस्ट के पॉकेट ए और बी का 98 एकड़, अलीपुर सिटी फारेस्ट का 48 एकड़, गढ़ी मांडु सिटी फारेस्ट का 42 एकड़ और जौनापुर सिटी फारेस्ट का 98 एकड़ में विकास किया जाएगा।

पर्यावरण एवं वन मंत्री गोपाल राय ने वन एवं वन्यजीव विभाग को गौरेया ग्राम के लिए बधाई देते हुए कहा कि इस गौरेया ग्राम के ज़रिए हमारा उद्देश्य इस विलुप्त होती प्रजाति के बारे में जन साधारण को जागरूक करना और इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाना है । साथ ही हमारी सरकार दिल्ली के लोगों को ऐसी जगह देना चाहती हैं जहाँ लोग प्रकृति का आनंद ले सकें और साथ-ही आने वाली पीढ़ी को भी प्रकृति के बारे में जागरूक कर सके। केजरीवाल सरकार दिल्ली के सिटी फारेस्ट को और बेहतर बनाने तथा इकोलॉजिकल सुरक्षा के आधार पर इनका विकास करने के लिए तत्पर हैं।

मुंडका में हुए अग्निकांड के खिलाफ ऐक्टू ने विरोध मार्च निकालते हुए मुख्यमंत्री के समक्ष किया प्रदर्शन

मुंडका, नरेला, झिलमिल, करोल बाग से लेकर बवाना तक हो रहे मज़दूरों के नरसंहार पर रोक लगाओ

आनंद राय गौरवशाली भारत

नई दिल्ली । मुंडका समेत दिल्ली के अन्य हिस्सों में लगातार हो दुर्घटनाओं के विरोध में आज आल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (ऐक्टू) ने मुख्यमंत्री के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। ऐक्टू के नेतृत्व में दिल्ली के विभिन्न इलाकों से आए मज़दूरों ने सुश्रुत ट्रामा सेंटर से मार्च निकालते हुए मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय के निकट विरोध सभा की। प्रदर्शन में छात्र संगठन आइसा ने भी भागीदारी की। कुछ दिन पहले, 17 मई को भी ऐक्टू व अन्य ट्रेड यूनियन संगठनों द्वारा दिल्ली के श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर, मुंडका अग्निकांड के संबंध में प्रदर्शन किया गया था। दिल्ली के बवाना, नरेला, पीरागढ़ी, करोल बाग, सुल्तानपुरी, झिलमिल, अनाज मंडी से लेकर मुंडका तक मज़दूरों के जिंदा जल जाने की घटनाएं लगातार जारी हैं। सभी घटनाओं का कारण दिल्ली सरकार के श्रम विभाग, एमसीडी, स्थानीय पुलिस-प्रशासन व अन्य सरकारी एजेंसियों की आपराधिक मिलीभगत है। दिल्ली के फैक्ट्री मालिकों को मुनाफ़ा कमाने के लिए सरकार ने पूरी छूट दे रखी है। इतने मज़दूरों के मारे जाने के बावजूद भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार मज़दूरों की सुध लेने को तैयार नहीं हैं।

सभा को संबोधित करते हुए ऐक्टू के राज्य अध्यक्ष संतोष राय ने कहा कि कई धरने-प्रदर्शनों के बाद भी कार्यस्थल पर मज़दूरों की सुरक्षा को लेकर सरकार बिल्कुल भी गम्भीर नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अन्य राज्यों में जाकर झूठे वादे कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी विदेश-यात्राओं में ही व्यस्त हैं। मज़दूरों गरीबों के रोज़ी-रोटी-रोज़गार-सुरक्षा पर दोनों सरकारें चुप हैं।

फैक्ट्री, सीवर, निर्माण स्थलों से लेकर घरों तक मे मारे जा रहे हैं मज़दूर : केंद्र और राज्य सरकार, दोनों हैं ज़िम्मेदार

दिल्ली में हर रोज़ मज़दूर या तो किसी सीवर में मारे जाते हैं या फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हुए। अभी-अभी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में एक घरेलू कामगार महिला के साथ हिंसा-उत्पीड़न का मामला सामने आया है। अगर राज्य और केंद्र की सरकारें, देश की राजधानी में भी मज़दूरों की सुरक्षा की गारंटी नही कर सकती तो इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी।

ऐक्टू ने आज प्रदर्शन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय को ज्ञापन सौंपते हुए ये मांग उठाई कि प्रत्येक मृत मज़दूर के परिवार को 50 लाख का मुआवजा और आश्रित को नौकरी दी जाए। घटना में 27 से ज़्यादा मज़दूरों के मारे जाने की संभावना को देखते हुए मृतकों-घायलों की संख्या के जांच की मांग भी उठाई गई।

ऐक्टू की राज्य सचिव श्वेता ने यह कहा कि दिल्ली के मज़दूरों के पास पेट की आग से भूखों मरने और फैक्ट्री की आग में जलने के अलावा और कोई विकल्प नही है। संसद और विधानसभा के अंदर मज़दूरों के मुद्दों को लेकर कोई बातचीत नही हो रही। आनेवाले दिनों में मोदी सरकार द्वारा लाए जा रहे मज़दूर-विरोधी श्रम कोड कानूनों के चलते ऐसी घटनाएं और बढ़ेगी। ऐक्टू कार्यस्थल पर मज़दूरों की सुरक्षा को लेकर आगे भी मज़दूरों का पक्ष मुखर रूप से उठाता रहेगा। दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में इस मुद्दे को लेकर संयुक्त अभियान भी चलाया जाएगा।

दिल्ली के टॉयलट पर भाजपा नेता ने लगाया 'ओरंगजेब मूत्रालय' पोस्टर, कहा- ज्ञानवापी का बदला

नई दिल्ली। भाजपा नेता आंचल शर्मा ने नई दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक शौचालय पर औरंगजेब मुत्रालय का पोस्टर लगाया है। उन्होंने लोगों से क्षेत्र के अन्य शौचालयों में भी इसी तरह के पोस्टर लगाने का आग्रह किया। मामले में ट्वीट करते हुए भाजपा नेता ने इसे ज्ञानवापी केस से जोड़ा है। अपने ट्वीट में भाजपा नेता आंचल शर्मा ने कहा, मैं हिन्दू समाज के लोगों से निवेदन करता हूं कि जहां भी आपको शौचालय दिखे, उसका नाम ओरंगजेब मूत्रालय रखा जाए। जो काशी विश्वनाथ मंदिर में ओरंगजेब ने ज्ञानवापी में किया है। हमारे भोलेनाथ के शिवलिंग को 500 सालों तक बंद करके रखा। हिन्दू समाज अब उन्हें इसका उत्तर देने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि शुक्रवार को ज्ञानवापी केस पर बड़ा फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई वाराणसी जिला अदालत को ट्रांसफर कर दी है। साथ ही कहा कि ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग स्थान को सील करके सुरक्षित किया जाए और वुजु के लिए जिलाधिकारी कोई अन्य स्थान चयनित करे। साथ ही शीर्ष अदालत ने मस्जिद में लोगों को नमाज पढ़ने से न रोकने का भी आदेश दिया है।

वीजा घोटाले में कार्ति की गिरफ्तारी से तीन दिन पहले नोटिस दें : अदालत

नयी दिल्ली। दिल्ली के एक अदालत ने शुक्रवार को वीजा घोटाले में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कि उन्हें (श्री कार्ति) को जांच का सामना करना होगा और यदि केंद्रीय जांच ब्यूरो को उन्हें (श्री कार्ति) को गिरफ्तार करने की जरूरत होगी, तो जांच एजेंसी को उन्हें (श्री कार्ति) को गिरफ्तार करने से तीन दिन पहले नोटिस देना होगा। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के लोकसभा सांसद कार्ति के खिलाफ सीबीआई ने 2011 में कथित तौर पर 50 लाख रुपये रिश्वत लेकर चीन के 250 नागरिकों को वीजा मुहैया कराने को लेकर मामला दर्ज किया है। इस सिलसिले में सीबीआई ने श्री कार्ति तथा उनके पिता एवं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के दिल्ली और चेन्नई स्थित ठिकानों पर मंगलवार को छापा मारा था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार ने जांच एजेंसी की याचिका पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को श्री कार्ति के चार्टर्ड अकाउंटेंट को एस. भास्करन को चार दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था। सीबीआई ने भास्करन को पंजाब में तलवांडी सबो पावर प्लांट में काम करने वाले चीन के 263 नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कार्ति ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

बिना राशन कार्ड वालों के लिए शुरू हो घर-घर राशन योजना : बिधूड़ी

सुप्रीम कोर्ट 60 लाख गरीबों को राशन उपलब्ध कराने का दे चुका है निर्देश

विवेक राय गौरवशाली भारत

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने केजरीवाल सरकार को सलाह दी है कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा घर-घर राशन योजना रद्द किए जाने के बाद वह अब बिना राशन कार्ड वाले लोगों के लिए यह योजना लागू करे। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में 60 लाख लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं। दिल्ली सरकार अपने संसाधनों से योजना बनाकर इन लोगों के लिए घर-घर राशन योजना शुरू कर सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को यही सलाह दी है।

बिधूड़ी ने कहा कि भाजपा पहले से ही यह कह रही थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोदी जी की केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अनाज के वितरण में कोई तब्दीली नहीं कर सकती। केंद्र सरकार दिल्ली के राशन कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन उपलब्ध कराती है और दिल्ली सरकार का काम सिर्फ उस अनाज को राशन की दुकानों तक पहुंचाना होता है। दिल्ली सरकार राशन के वितरण का तरीका ही बदलना चाहती थी जोकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत बदला नहीं जा सकता। इसके अलावा केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिल्ली के गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराती है और वह भी केंद्र सरकार की ही योजना है। अब दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में भी वही बातें कही गई हैं जो अब तक भाजपा कहती आ रही है।

बिधूड़ी ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के उन गरीबों को राशन मुहैया कराने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश दे चुका है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। अब हाई कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार से कहा है कि वह अपने संसाधनों से अनाज खरीदकर इस तरह की योजना करके लोगों के पास राशन पहुंचा सकती है। इस तरह अब केजरीवाल सरकार के पास मौका है कि वह दिल्ली के 60 लाख उन गरीबों के घर-घर जाकर राशन पहुंचाए जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं। ये लोग आठ साल से राशन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं लेकिन दिल्ली सरकार राशन कार्ड नहीं बना पाई। अब कम से कम उन्हें राशन तो दे दे।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर सरकार ऐसी कोई योजना चलाती है तो विपक्ष उसका स्वागत करेगा क्योंकि हम समय-समय पर यह मांग करते रहे हैं कि दिल्ली सरकार इन गरीबों तक राशन पहुंचाए।

केजरीवाल सरकार से मृतक परिवार को एक करोड़ और घायलों को 10-10 लाख देने की मांग की

वीडियोकॉन टॉवर के पास साइकिल मार्किट में लगी आग से करोड़ों का नुकसान, नींद से कब जागेगी सरकार

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुस्तफाबाद में लगी आग में जान गवाने वाले इंद्रजीत पांडेय और घायलों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भ्रष्ट नीतियों का शिकार दिल्ली की मासूम जनता हो रही है। जिस तरह से आए दिन फैक्ट्री, होटल, दुकानों और झुग्गियों में आग लग रही है, उसकी एकलौती जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है। आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि मुस्तफाबाद में लगी आग में जान गवाने वालों के परिवारवालों को एक करोड़ रुपये और घायलों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाए।

आदेश गुप्ता ने कहा कि साल 2014 से लेकर अब तक कई आग्निकांड को दिल्लीवाले अपनी आंखों से देख चुके हैं और सैकड़ों मासूम और निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। यही नहीं आज झंडेवालान वीडियोकॉन टॉवर के पास साइकिल मार्केट में भी आग लग गई जिसमें दर्जनों दुकानें जलकर खाक हो गई और करोड़ो रुपये का नुकसान हो गया

है। आखिर केजरीवाल सरकार हाथ पर हाथ धरे किस बात का इंतजार कर रही है। लगातार दिल्ली में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं और केजरीवाल सिर्फ कोरी बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। सोई हुई केजरीवाल सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। वह अपनी कुंभकर्णी नींद से कब जागेगी।

आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में पिछले एक हफ्ते के अंदर 28 मासूम लोगों की जान चली गई। लेकिन उससे अरविंद केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता।

फायर एनओसी देने में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बेहिसाब भ्रष्टाचार किया है और उस भ्रष्टाचार के शिकार आए दिन दिल्ली की मासूम जनता हो रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की पुरानी आदत है कि जब-जब दिल्ली में कोई हादसा होता है, वे या तो पार्टी कर रहे होते हैं या लाइव आकर घड़ियाली आंसू बहाने लगते हैं।

आदेश गुप्ता ने कहा कि आखिर साल 2019 में दिल्ली में हुए आग के भीषण हादसे को कौन भूल सकता है जब पूरी दिल्ली शोक में डूबी हुई थी, उस समय केजरीवाल तिमारपुर में चुनावी भाषण दे रहे थे जहां उन्हें जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। इस घटना से नाराज लोग मंच पर चढ़ गए और उनके विधायक से हाथापाई की। अभी हाल ही में गोकलपुरी में लगी आग से जब गरीबों का सब कुछ जल कर राख हो गया तो उनसे मिलकर उनका दुख जानने की जगह केजरीवाल हाथ हिलाते हुए वहां फोटो सेशन करा रहे थे।

उन्होंने कहा कि हर एक अग्निकांड के बाद जांच बैठाई जाती है लेकिन पिछले तीन सालों में हुई एक दर्जन से अधिक आग लगने की घटनाओं के लिए जांच कमेटी तो बनाई गई लेकिन आग लगने के कारणों और जांच कमेटी के रिपोर्ट ठंढे बस्ते से निकल नहीं रही है जिसका इंतजार आज भी दिल्ली की जनता कर रही है।

नोएडा : ओयो होटल के डस्टबिन में मिला चार महीने का भ्रूण

कमरे में युवक के साथ रुकी थी दिल्ली की युवती

नोएडा। नोएडा के थाना फेस-3 क्षेत्र के सेक्टर-71 स्थित एक ओयो होटल में एक 4 माह का भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि एक युवक-युवती होटल में भ्रूण को छोड़कर गए हैं। फिलहाल पुलिस होटल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है।

थाना प्रभारी ने बताया कि 18 मई को सूचना मिली थी कि सेक्टर-71 के एक ओयो होटल के कमरे में एक भ्रूण पड़ा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि कमरे में रखे कूड़ेदान के अंदर पॉलीथिन में भ्रूण पड़ा था। पुलिस ने भ्रूण को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं।

पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी

कैमरे की फुटेज खंगाली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि दो दिन पहले एक युवक-युवती 16 मई को होटल के उस कमरे में ठहरे थे, जिसमें भ्रूण मिला है। जब वह 18 मई को होटल छोड़कर गए तब होटल कर्मचारियों को सफाई के दौरान कूड़ेदान में भ्रूण मिला। फिर पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने भ्रूण का पोस्टमॉर्टम कराया है।

दिल्ली की रहने वाली है युवती, युवक का पता फर्जी

जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि युवती का आधार कार्ड ठीक है। वह दिल्ली की रहने वाली है। वह फिलहाल नोएडा में एक कंपनी में नौकरी करती है। पुलिस ने दिल्ली में संबंधित पते पर जाकर पूछताछ की तो वहां युवती की मौसी मिली। उन्होंने युवती के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया। वहीं, युवक द्वारा होटल में दिया गया आधार कार्ड फर्जी है। थाना प्रभारी का कहना है कि आधार कार्ड पर सेक्टर-34 का पता है। यहां पर युवक वर्ष 2016 में किराये पर रहता था। पुलिस युवती की तलाश कर रही है, ताकि युवक के बारे में भी जानकारी मिल सके।

पुलिस को युवक के डॉक्टर होने का शक

पुलिस को युवती के साथ आए युवक पर डॉक्टर होने का शक है। थाना प्रभारी का कहना है कि तीन महीने के बाद गर्भपात कराने में भी खतरा रहता है, जबकि आशंका है कि दवाइयों के माध्यम से युवती की सामान्य डिलीवरी की गई है। इसके अलावा पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी मामले की जांच कर रही है।

संपादकीय

सवालों के घेरे में पूजा-स्थल कानून

देश में इस वक्त ज्ञानवापी मामले की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। वाराणसी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इससे जुड़े मामलों पर सुनवाई कर रहे हैं। इन सुनवाइयों में 1991 का पूजा स्थल कानून सबसे ज्यादा चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका में वाराणसी कोर्ट के आदेश को पूजा स्थल कानून, 1991 का उल्लंघन बताया गया है। इस कानून की विरोधाभासी व्याख्या की जा रही है। ज्ञानवापी परिसर के संदर्भ में यह कानून बेहद महत्त्वपूर्ण है। याचिकाकर्ता ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 की धारा दो, तीन और चार की संवैधानिक वैद्यता को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये तीनों धाराएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14,15, 21, 25, 26 और 29 का उल्लंघन करती हैं। याचिका के मुताबिक ये सभी हमारे संविधान की मूल भावना और प्रस्तावना के खिलाफहैं।

आखिर ये पूजा स्थल कानून-1991 क्या है ? उस समय इसे लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी ? इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में किस आधार पर चुनौती दी गई है ? क्या ये याचिका ही काशी और मथुरा जैसे विवादों का रास्ता खोलने वाली याचिका बनी है ? कितने धार्मिक स्थल हैं जिनके बारे में दावा है कि वो मंदिर तोड़कर बने हैं ? मुस्लिम पक्ष के नेता, प्रवक्ता और मौलाना-मौलवी एक ही सुर में दलीलें दे रहे हैं कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करा और कथित शिवलिंग की विशेष सुरक्षा करा निचली अदालत ने 1991 के कानून का उल्लंघन किया है। दूसरी तरफभाजपा और हिंदू पक्ष का स्पष्टीकरण है कि उक्त कानून की संवैधानिक वैधता सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है, लिहाजा इस कानून की दलीलें देना गलत है। चूंकि 1991 का कानून संसद और भारत सरकार के जरिए पारित किया गया है, लिहाजा वह आज भी 'लागू' कानून है। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने पूजा स्थल कानून लेकर आई थी। यह वो समय था, जब रामजन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के साथ ही उन तमाम मस्जिदों को परिवर्तित करने की मांग उठने लगी जहां पूर्व में मंदिर रहे थे। ऐसे समय में नरसिंह राव की सरकार ने सांप्रदायिक उन्माद को शांत करने के लिए एक कानून बनाना आवश्यक समझा और वह कानून था, प्लेसेज ऑफवर्शिप एक्ट, या उपासना स्थल अधिनियम। यह भी जानना जरूरी है कि कांग्रेस ने 1991 के अपने चुनावी घोषणापत्र में ऐसे कानून को लाने की बात पहले ही कर दी थी। अधिनियम के बिल को बहस के लिए संसद के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया गया। तत्कालीन गृह मंत्री, शंकरराव चव्हाण ने 10 सितंबर 1991 में लोकसभा में बहस के दौरान इस बिल को भारत के प्रेम, शांति और आपसी भाईचारे के महान संस्कारों का एक सूचक बताया और कहा कि 'सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता हमारी महान सभ्यता का चरित्र है।'

इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे एक से तीन साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में था इसलिए उसे इस कानून से अलग रखा गया था। जुलाई 1991 में जब केंद्र सरकार ये कानून लेकर आई थी तब भी संसद में भाजपा ने इसका विरोध किया था। उस वक्त राज्यसभा में अरुण जेटली और लोकसभा में उमा भारती ने इस मामले को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की थी। अयोध्या मामले का फैसला आने के बाद एक बार फिर काशी और मथुरा सहित देशभर के करीब 100 पूजा स्थलों पर मंदिर की जमीन होने को लेकर दावेदारी की जा रही है, लेकिन 1991 के कानून के चलते दावा करने वाले कोर्ट नहीं जा सकते। ज्ञानवापी में इसी कानून के उल्लंघन की बात मुस्लिम पक्ष कह रहा है।

अफगानिस्तान में महिलाओं की दिन पर दिन दयनीय होती स्थिति को दुनिया बस देख रही है

नीरज कुमार दुबे

अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है। तालिबान सरकार एक के बाद एक ऐसे हुक्म जारी कर रही है जिससे महिलाओं के सपनों, उनकी उम्मीदों, उनके अधिकारों पर तो चोट पहुँच ही रही है साथ ही अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में महिलाओं की भूमिका भी पूरी तरह खत्म होती जा रही है। दुनिया में अफगानिस्तान के अलावा शायद ही इस समय कोई ऐसा देश होगा जो अपनी ही आधी आबादी की खुशियों को कुचल देने पर आमादा होगा। 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से वैसे तो तालिबान महिलाओं के खिलाफ कई आदेश जारी कर चुका है लेकिन अब उसने जो हालिया आदेश जारी किया है उसके चलते अफगानिस्तान में महिला टीवी एंकरों को कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान अपना चेहरा ढकने पर मजबूर होना पड़ा है। अफगानिस्तान के सबसे बड़े मीडिया संस्थान 'टोलो न्यूज' चैनल के एक ट्वीट के मुताबिक तालिबान के आचरण और नैतिकता मंत्रालय और सूचना एवं संस्कृति मंत्रालय के बयानों में यह आदेश जारी किया गया है। तालिबान सरकार के बयान में कहा गया है कि यह आदेश ''अंतिम'' है और इसमें ''कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।'' तालिबान सरकार के इस आदेश के बाद से अफगान मीडिया में हड़कंप है क्योंकि एकतरफा जारी किये गये इस आदेश में चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं रखी गयी है। इसलिए अब अफगान टीवी चैनलों के समक्ष कोई विकल्प नहीं बचा होने के चलते वहां महिला टीवी एंकरों ने अपने चेहरे ढक लिये हैं। तालिबान सरकार के इस आदेश के बाद कई महिला टीवी कार्यक्रम प्रस्तोताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा कीं हैं जिनमें वे कार्यक्रम प्रस्तुत करने के दौरान अपने चेहरे को मास्क से ढके हुए दिख रही हैं। 'टोलो न्यूज' की एक प्रमुख प्रस्तोता यल्दा अली ने चेहरे पर मास्क पहनते हुए अपना एक वीडियो पोस्ट किया और इसका शीर्षक लिखा, ''आचरण एवं नैतिकता मंत्रालय के आदेश पर एक महिला को मिटाया जा रहा है।'' हम आपको याद दिला दें कि तालिबान जब 1996 से 2001 तक सत्ता में रहा था, तो उसने महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। तालिबान अफगानिस्तान में पिछले साल अगस्त में फिर से सत्ता पर काबिज होने के बाद शुरुआत में महिलाओं पर प्रतिबंधों को लेकर थोड़ा नरम रुख अपनाते प्रतीत हुआ था, लेकिन हालिया सप्ताहों में उसने फिर से प्रतिबंध कड़े करने शुरू कर दिए हैं। तालिबान ने इस महीने की शुरुआत में ही महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर सिर से लेकर पैर तक बुर्के में ढके रहने का आदेश दिया था। तालिबान के आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की केवल आंखें दिख सकती हैं। देखा जाये तो कुल मिलाकर तालिबान सरकार का प्रयास है कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को पूरी तरह खत्म किया जाये। तालिबान का मानना है कि शिक्षित महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है इसलिए उसे शिक्षित होने से रोका जाये। इसके लिए तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करते ही स्कूल, कॉलेजों में लड़कियों के जाने पर रोक लगाई और उसके बाद नौकरीपेशा महिलाओं को घर बैठने के लिए कहा गया। फिर टीवी कार्यक्रमों में महिलाओं को दिखाये जाने पर रोक लगा दी, फिर महिलाओं के ब्यूटी पार्लर बंद करवा दिये, फिर महिलाओं के अकेले कहीं आने-जाने या घूमने पर रोक लगा दी, फिर बच्चियों को बगैर हिजाब के स्कूल जाने पर मनाही कर दी, फिर लड़कियों के खेलों में भाग लेने पर रोक लगा दी, फिर लड़के और लड़कियों के एक साथ शिक्षा हासिल करने पर रोक लगाते हुए तीन दिन कॉलेज लड़कों के लिए और बाकी तीन दिन लड़कियों के लिए खोले जाने का फरमान सुना दिया। इसके बाद तालिबान सरकार ने अपनी आलोचक महिलाओं को नॉटी बताते हुए उन्हें घर पर ही रहने की सख्त हिदायत दे डाली। इसके बाद तालिबान ने महिलाओं के कॉफी शॉप में जाने और हमाम को इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। उसके बाद तालिबान सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं बुर्के से पूरी तरह ढकी होनी चाहिएं और अब टीवी एंकरों के चेहरे भी ढकवा दिये।

मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि केस और हिंदू-मुस्लिम पक्ष के बीच हुए 1968 के समझौते की कहानी

अभिनय आकाश

अब मथुरा की भी फाइल खुल गई है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद विवाद की याचिका स्वीकार कर ली गई है, जिसके बाद अब कृष्ण जन्मभूमि से सटी ईदगाह मस्जिद को हटाने की याचिका पर अदालती कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ है।

1990 का वो दौर राम मंदिर आंदोलन के दौरान एक नारा लगाया जाता था- अयोध्या तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। अब धीरे-धीरे वो नारा चरितार्थ होने लगा है। रास्ता वो हो न हो लेकिन अदालतती दरवाजे के रास्ते मंदिर कुछ वैसी ही दिखती है। काशी में ज्ञानवापी पर देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से केस वापस से जिला जज के पाले में ट्रांसफर कर दिया है। मतलब, जिला जज जिन्होंने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने से लेकर सर्वे के आदेश दिए थे। अब फिर से मामले की सुनवाई करेंगे। लेकिन इन सब के बीच अब मथुरा की भी फाइल खुल गई है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद विवाद की याचिका स्वीकार कर ली गई है, जिसके बाद अब कृष्ण जन्मभूमि से सटी ईदगाह मस्जिद को हटाने की याचिका पर अदालती कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ है। एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री ने भगवान श्रीकृष्ण के सखी के तौर पर एक केस सितंबर 2020 में सिविल कोर्ट के समक्ष दाखिल किया था जिसे उस वक्त सिविल कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अक्टूबर में ये केस रिविजन के लिए जिला जज की कोर्ट में दाखिल किया गया।

मथुरा कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है?

जिला और सत्र न्यायाधीश राजीव भारती ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और अन्य निजी पार्टियों द्वारा उस भूमि के स्वामित्व की अपील की, जिस पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी है। ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल के बगल में है, जहां भगवान कृष्ण का जन्म माना जाता है। विवाद में अनिवार्य रूप से 13.37 एकड़ भूमि का स्वामित्व शामिल है, जो याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह देवता भगवान श्री कृष्ण विराजमान का है। याचिका को पहले निचली अदालत ने खारिज कर दिया था, और बाद में जिला न्यायाधीश के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी। दीवानी वाद की सुनवाई अब निचली अदालत करेगी। राजस्व रिकॉर्ड देखने के अलावा, अदालत को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान - मंदिर प्रबंधन प्राधिकरण, जो कानून के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है - और ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह के बीच 1968 के समझौता समझौते की वैधता भी तय करनी होगी। जिसके द्वारा मंदिर प्राधिकरण ने भूमि के विवादास्पद हिस्से को ईदगाह को दे दिया। याचिका में 1968 में हुए समझौते को भी रद्द करने की मांग की गई है। याचिकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में संस्थान को समझौता करने का अधिकार ही नहीं है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट की निगरानी में जन्मभूमि परिसर की खुदाई कराई जाए। उनका दावा है कि जिस जगह पर मस्जिद बनाई गई थी, उसी जगह पर वो कारागार मौजूद है जिसमें भगवान जन्मे थे। उनका ये भी कहना है कि कृष्ण जन्मभूमि का भी ज्ञानवापी की तरह से वीडियो सर्वे कराया जाए, जिससे सच पता लगेगा। हिंदुओं को मंदिर में पूजा करने का अधिकार दिया जाए। याचिका में संसद से पारित धर्म स्थल कानून यानी प्लेसेज ऑफ वर्सिप एक्ट 1991 को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि धर्मस्थलों का प्रबंधन और कानून व्यवस्था राज्य सरकार की सूची का विषय है। इस बाबत कानून और नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को ही होना चाहिए। ऐसे में संसद में ये कानून बनाकर राज्य सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप किया गया है।

क्या है 1968 में हुए समझौते का विवाद

मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि से लगी हुई है। इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब ने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट करके शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया। 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से वाराणसी के हिंदू राजा को जमीन के कानूनी अधिकार सौंप दिए गए थे, जिस पर मस्जिद खड़ी थी। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर ये तय किया गया कि वहां दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण होगा और उसका प्रबंधन ट्रस्ट की तरफ से किया जाएगा। 1958 में श्रीकृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन किया गया।

कानूनी तौर पर ये संस्था को जमीन पर मालिकाना हक हासिल नहीं था। लेकिन ट्रस्ट के लिए तय सारी भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी गई। इस संस्था ने 1964 में पूरी जमीन पर नियंत्रण के लिए सिविल केस दाखिल किया। लेकिन 12 अक्टूबर 1968 में खुद ही मुस्लिम पक्ष के साथ एक समझौता कर लिया। श्रीकृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह के प्रतिनिधियों में समझौता किया गया। 17 अक्टूबर 1968 को इस समझौता पेश किया गया और 22 नवंबर 1968 को मथुरा सब रजिस्टार के यहां इसे रजिस्टर किया गया। 1968 समझौते के अनुसार, शाही ईदगाह कमिटी और श्री कृष्णभूमि ट्रस्ट के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार, जमीन ट्रस्ट के पास रहेगी और मस्जिद के प्रबंधन अधिकार मुस्लिम कमिटी को दिए जाएंगे। लेकिन अब याचिका में कहा गया है कि वो समझौता श्रीकृष्ण भक्तों की भावना के खिलाफ था। याचिका में कहा गया कि कटरा केशव देव की संपूर्ण संपत्ति ट्रस्ट की है और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को उसका मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता है। इसलिए उसके द्वारा किया गया समझौता यहां अवैध होगा। कटरा केशवदेव की संपत्ति पर शाही ईदगाह का किसी प्रकार का अधिकार नहीं हो सकता। इसिलिए उस पर किया गया निर्माण भी अवैध है। अब इसी आधार पर शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की बात की जा रही है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि और मथुरा का इतिहास भी जान लीजिए

जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ पहले वह कारागार हुआ करता था। यहां पहला मंदिर 80-57 ईसा पूर्व बनाया गया था। इस संबंध में महाक्षत्रप सौदास के समय के एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि किसी वसु नामक व्यक्ति ने यह मंदिर बनाया था। इसके बहुत काल के बाद दूसरा मंदिर सन् 800 में विक्रमादित्य के काल में बनवाया गया था, जबकि बौद्ध और जैन धर्म उन्नति कर रहे थे। इस भव्य मंदिर को सन् 1017-18 ई. में महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था। बाद में इसे महाराजा विजयपाल देव के शासन में सन् 1150 ई में जज्ज नामक किसी व्यक्ति ने बनवाया। यह मंदिर पहले की अपेक्षा और भी विशाल था, जिसे 16वीं शताब्दी के आरंभ में सिकंदर लोदी ने नष्ट करवा डाला। ओरछा के शासक राजा वीर सिंह बुंदेला ने फिर से इस खंडहर पड़े स्थान पर पहले से भी विशाल मंदिर बनवाया। जिसके बारे में कहा जाता था कि ये इतना ऊंचा था कि इसे आगरा से भी देखा जा सकता था। लेकिन 1679 में मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर उत्तर भारत में कई जगह ऐतिहासिक मंदिर तोड़े गए। इसके पीछे धार्मिक कारण थे और हिंदुओं की आस्था पर चोट करना इसका मकसद था। इसके अलावा इसके आर्थिक उद्देश्य भी थे, क्योंकि इन मंदिरों में काफी धन संपदा होती थी जिसे औरंगजेब ने लूट लिया। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर को भी उसी समय तोड़ा गया। इसका अभिलेखीय साक्ष्य भी है कि कब ऐसे आदेश दिए गए।

औरंगजेब के कोर्ट में एक मुहतसिब होता था, जो धार्मिक आचरण को नियंत्रित करता था और उसी की सलाह पर औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाया।% औरंगजेब की तरफ से जन्मभूमि के आधे हिस्से पर ईदगाह बना दी गई, जो आजतक कायम है।

समुद्री जैव विविधता और अनुसंधान

पुखराज प्राज
छत्तीसगढ़

समुद्र यानी नीले पानी से भरा एक विस्तृत क्षेत्र है। समुद्र को लेकर मनुष्यों में प्रारंभ से जिज्ञासा की लहरें तेज रही है। समुद्र की लहरें जो हमेशा चुनौतियों और रोमांच के लिए आकर्षित करते हैं। सन 1787 में जॉन फिच ने स्टीम इंजन लगा कर नाव का आविष्कार किया था। वैसे तो नाव के संदर्भ में प्रारंभ अवस्था से होमोसेपियंस ने पानी पर तैरने की कला और लकड़ियों के सहारे से नाव से छोटी यात्राओं को सीख लिया था। वहीं इसी अवधारणा को परिभाषित करने वाले आर्कमिडीज का सिद्धांत कहता है, जब कोई वस्तु पूरी-पूरी या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोई जाती है। तो उसके भार में कमी आती है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए द्रव के भार के बराबर होती है। बाहर में वह कमी द्रव की उत्प्लावन बल के बराबर होती है। ऐसे ही बहुत ये वैज्ञानिकों की जिज्ञासा पानी और पानी से भरे बड़े क्षेत्र यानी समुद्र की ओर रही है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में समुद्री जैव विविधता को हमेशा कम अच्छी तरह से समझा गया है। समुद्री सर्वेक्षण और पानी के भीतर नमूना लेने के स्पष्ट खतरे और आर्थिक चुनौतियां गहराई से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बाधाएं रहती हैं और रहेगी। बात करें भारत की तटीय लंबाई 6100 किमी और द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7516.6 कि.मी. है। भारत में कुल राज्यों में समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या 9 है। जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल तक फैला है। इसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा भी समुद्र तट से लगती है। जो दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक फैली हुई है। इतने विशाल समुद्रीय तटीय वाले राष्ट्र के लिए समुद्र के प्रति लगाव और पर्यटन का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। इसके साथ ही समुद्र के गहराई विषय में अनुसंधान बढ़ने लगे हैं।

डीप ओशन मिशन की शुरुआत भारतीय समुद्री सीमा में गहरे समुद्र का अन्वेषण करने के लिए कुछ समय पूर्व प्रारंभ किया गया है। जोकि गहरे समुद्र से संबंधित स्थितियों, जीवन अनुकूल अणुओं, तथा जैविक संघटकों की रचना संबंधी अध्ययन शामिल है। जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पर प्रकाश डालने का प्रयास करेगा। 70 फीसदी जल राशि समाहित इस पृथ्वी के हिस्से में समुद्री जीव-जंतु पाये जाते है। गहरे समुद्र के लगभग 95.8त्न भाग मनुष्य के लिए आज भी मर्म का विषय बना हुआ हैं। पीआईबी के रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटक के नील अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्र तटीय पर्यटन में मदद करेगा। गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार, सूक्ष्मजीवों सहित गहरे समुद्र की वनस्पतियों और जीवों की जैव-पूर्वेक्षण और गहरे समुद्र में जैव-संसाधनों के सतत उपयोग पर अध्ययन इसका मुख्य केंद्र बनकर उभरेगा।

इस मिशन की छ : उद्देशिकाएं निर्धारित है। जिनमें गहरे समुद्र में खनन और मानव युक्त पनडुब्बी के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास, महासागर जलवायु परिवर्तन परामर्श सेवाओं का विकास, गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज एवं संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार, गहरे समुद्र में सर्वेक्षण व अन्वेषण, समुद्र से ऊर्जा एवं ताजा पानी प्राप्त करना, और समुद्री जीव-विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन विकास शामिल है। समुद्री पारिस्थितिकी के संदर्भ में होने वाले इस अनुसंधान से निश्चित ही भावी समय में हम समुद्र के गहरे पानी के अंदर का मर्म समझ पायें। वहां पाने वाले जीवों, खनिजों और समुद्र के अध्ययनों के सहारे जैविक विविधता के समझ को और विकसित कर पायेंगे।

आरबीआई कहता है कैश छोड़ो डिजिटल हो जाओ

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी कमर्शियल बैंकों से कहा है कि वह जल्दी से जल्दी एटीएम मशीनों पर बिना डेबिट कार्ड के पैसा निकालने की सुविधा दें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी योनो स्कीम के तहत पहले ही यह सेवा दे रहा है। आरबीआई का कहना है कि फिजिकल कार्ड न होने से कार्ड क्लोनिंग और डिवाइस से छेड़छाड़ जैसी धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आएगी। नए सिस्टम में यूपीआई पिन का इस्तेमाल करके ग्राहक रुपए निकाल सकेंगे। इस सुविधा के लिए बैंक एटीएम चार्ज नहीं ले पाएंगे। यह सभी नागरिकों के लिए एक अच्छी सुविधा होगी और कार्ड साथ में रखना जरूरी नहीं होगा। भारत में डिजिटल बैंकिंग का चलन बढ़ता जा रहा है। लगभग 20 करोड़ भारतीय फिलहाल डिजिटल बैंकिंग का लाभ ले रहे हैं। आरबीआई इस संख्या को बढ़ाना चाहता है। अभी देश का बड़ा तबका डिजिटल नहीं पाया है। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का फायदा सभी तक पहुंचाने के लिए, आरबीआई ने बैंकों को डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोलने के लिए कहा है। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का कहना है कि जुलाई में देश के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू हो जाएंगे। इन बैंकिंग यूनिट्स में वह सारे काम होंगे जो आप इंटरनेट बैंकिंग यानी नेट बैंकिंग से करते हैं। यहां बस कैश का लेनदेन नहीं होगा। कैश के अलावा इन ब्रांचों में बचत खाता, चालू खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ट्रांजिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक लोन, भीम क्यूआर कोड आदि सेवाएं मिलेंगी। कस्बों तक में डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोली जाएंगी। कमर्शियल बैंक पहले से ही डिजिटल बैंकिंग का विकल्प दे रहे थे, लेकिन अब डिजिटल बैंक भी चला सकेंगे। ये एक तरीके से फिजिटल बैंक कहलाएंगे, जोकि फिजिकल और डिजिटल से मिलकर बना है। इन यूनिटों में जाकर आप अपनी डिजिटल बैंकिंग संबंधी जरूरतों को समझ पाएंगे और बैंक की मदद ले पाएंगे। यूपीआई से पहले ही कैशलेस भुगतान को बढ़ावा मिला है, जिससे डिजिटल पेमेंट लोकप्रिय हो रहा है। रिटेल डिजिटल पेमेंट की बात करें तो बीते चार सालों में इसमें यूपीआई की हिस्सेदारी दोगुने से अधिक हो चुकी है। यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस।

'याद करेगा हिंदुस्तान'

भारत के प्रगतिशील प्रभावी और दयालु पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित

राहुल राव
चेयरमैन मीडिया विभाग
भारतीय युवा कॉंग्रेस

31 साल पहले भारत रत्न श्री राजीव गांधी इस दुनिया से चले गए। इस दिन हमने न केवल एक विद्वान राजनेता बल्कि एक अद्भुत इंसान भी खो दिया। आज, हम अपने देश में बदलाव लाने के प्रति उनके समर्पण, प्रतिबद्धता और करुणा को याद करते हैं और उन्हें संजोते हैं। इस दिन और उम्र में भी हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने कई फैसले लिए, जिसने भारत को सही दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने वैज्ञानिक विकास का समर्थन किया और भारत को विकसित करने और 21वीं सदी के लिए तैयार होने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर दिया और इसलिए कई मिशन शुरू किए, जिनसे सभी को लाभ हुआ, जैसे टीकाकरण, पेयजल, शुष्क भूमि की खेती और कई अन्य। उनकी जैसी अलग मानसिकता के साथ, भारत ने सरकार की ओर से कई ऐसी पहल देखीं, जिनकी देश ने पहले कल्पना भी नहीं की थी। पेश किया गया बजट एक ऐसी ही पहल थी जिसने अर्थव्यवस्था के कायाकल्प को बढ़ावा दिया और अर्थव्यवस्था की बहाली और 1991 के अभूतपूर्व सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। आज के युवा उन्हें सलाम करते हैं और मतदान की उम्र कम करके देश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए धन्यवाद देते हैं। जिसे भारत के युवा दिमाग अपना नेता चुन सके। आज हम भारत की सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्रांति के जनक% को नमन करते हैं और याद करते हैं कि कैसे उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, कैसे उन्होंने अत्याधुनिक दूरसंचार तकनीक विकसित की, और ऐसा करने की प्रक्रिया में सही नाम मिला। डिजिटल इंडिया के वास्तुकार के रूप में। उन्होंने अपना ध्यान समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान की ओर केंद्रित किया। उनका मानना था कि समाज के कमजोर वर्ग, जैसे शोषित, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,

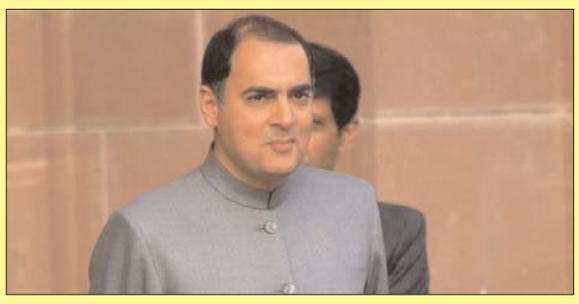

शिक्षा के लिए उचित जोखिम दिए जाने पर फल-फूल सकते हैं। उन्होंने इस मुद्दे को कई बार उठाया और स्वीकार किया कि शिक्षा अभी तक समाज के कमजोर वर्ग तक नहीं पहुंची है और शिक्षा प्रदान करने से निश्चित रूप से देश के कमजोर वर्गों का कल्याण होगा। यहां तक कि हमारे देश के लोकतंत्र में भी पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम देखा गया। राजीव गांधी के सत्ता में आते ही उन्होंने भारतीय राजनीति में शौच की समस्या को संबोधित किया, जो भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के साथ इस प्रथा को प्रतिबंधित करके लोकतंत्र के नैतिक आधार पर एक विनाशकारी प्रथा और बेहद अनैतिक थी। राजीव गांधी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि महिलाएं किसी भी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हर समुदाय की सफलता और समृद्धि का अंदाजा दूसरे आधे लोगों के विकास से लगाया जा सकता है, उनका मानना था। आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक विचारों सहित सभी क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। जब बलिदान और बहादुरी की बात आती है, तो कभी भी असहमति नहीं रही है। हमारी आजादी की लड़ाई यही दर्शाती है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं का योगदान, चाहे घर पर हो या काम पर, पुरुषों की तुलना में कभी भी कमजोर या कम नहीं रहा है, लेकिन महिलाओं को अभी भी पर्याप्त शैक्षिक और नौकरी के अवसरों से वंचित रखा गया है। इसके अलावा राजीव गांधी ने सामाजिक न्याय को सभी समूहों और क्षेत्रों के विकास के रूप में परिभाषित किया। समाज की। वह चाहते थे कि हर कोई, जाति, जन्म, धर्म या त्वचा के रंग की परवाह किए बिना, विकास का अनुभव करे। 23 जनवरी, 1984 को, उन्होंने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एक बहस के दौरान कहा, कांग्रेस विभिन्न विचारधाराओं की प्रतिनिधि है, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष, आत्मनिर्भरता के लिए संघर्ष, धन के केंद्रीकरण के खिलाफ, सभ्य सार्वजनिक उपक्रमों का मतलब है लोगों के कल्याण, धर्मनिरपेक्षता और गुटनिरपेक्षता और शांति की नीतियों के लिए। 17 दिसंबर 1985 को, उन्होंने 7वीं योजना पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में घोषणा की, हमने 7वीं योजना में अपने विकल्पों को संशोधित नहीं किया है। राजनीतिक विरोधी उनके विरोधी नहीं थे, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था में एक स्थान चाहने वाले साथी नागरिक थे। उनके मैत्रीपूर्ण व्यवहार और सुखद मुस्कराहट ने उन्हें राजनीतिक बाधाओं को तोड़ने में सहायता की। वह आसानी से गलियारे में कदम रख सकते थे क्योंकि वे अपनी पार्टी को पार कर सकते थे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत, श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भेजें। राजनीतिक पूर्वाग्रहों ने उन्हें परेशान नहीं किया, न ही अपशब्दों या आक्षेपों ने, क्योंकि उन्हें भारत में शासन में एक आदर्श बदलाव लाने की अपनी क्षमता पर भरोसा था। हम, भारत के लोग इतने युवा और भयानक रूप से दूरदर्शी, स्पष्ट-प्रधान और गतिशील नेता को खो देने के लिए बेहद बदकिस्मत थे। अगर राजीव गांधी रहते, तो आज हम एक अलग प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था देखते। उनकी मानवीय और समकालीन विचार-प्रक्रिया उन्होंने राजनीति को स्वार्थ के अंधेरे काल कोठरी से मुक्त करने में मदद की और इसे केवल लोगों के लाभ के लिए काम करने की अनुमति दी। भारत के समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के प्रति उनकी निष्ठा सेवा करती है सांप्रदायिक और फासीवादी प्रभावों के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक सबक और मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में। हम भारत के एक प्रगतिशील, प्रभावशाली और दयालु प्रधान मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने भारत को एकजुट करने की मांग की और अपने आदर्शों और मूल्यों का पालन करके और उन्हें आज की दुनिया में भी लागू करके 21 वीं सदी में इसे आगे बढ़ाने में मदद की।

शार्ट न्यूज

विद्युत उत्पादन निगम में एई के 125 पदों पर भर्ती के लिए 23 से आवेदन

लखनऊ। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल, कंप्यूटर साइंस तथा सिविल से इंजीनियरिंग में स्नातक करने वाले युवाओं को उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम में सहायक अभियंता प्रशिक्षु (एई ट्रेनी) बनने का मौका जल्द मिलेगा। निगम ने एई के रिक्त 125 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगें हैं। समूह ख के इन रिक्त पदों पर प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से भर्ती होनी है। इन पदों पर आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के तहत आवेदन कर सकते हैं। इन पद पर पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा केलव अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत होंगे। आवेदन की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें आयु सीमा में पांच साल की छूट मिलेगी। यदि कोई पुरुष या महिला अभ्यर्थी जो एक से अधिक जीवित पत्नी/पति रखे हैं वह चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे। लिखित परीक्षा के लिए लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में केंद्र बनाए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी। अंतिम तिथि 14 जून है।

बीयर सेल्समैन हत्याकाण्ड में तीन गिरफ्तार

बस्ती। उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के परशुरामपुर थाने की पुलिस ने शहर में बीयर की एक दुकान के सेल्समैन की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बस्ती के अपर पुलिस अधीक्षक दीपेन्द्र कुमार चौधरी ने शुक्रवार को बताया कि परशुरामपुर थाना क्षेत्र में बीयर की दुकान के सेल्समैन विनय सिंह को गोली मार कर तीन व्यक्तियों ने हत्या कर दी थी। इनकी पहचाप इरफान, रोहन सिंह उर्फ चमन सिंह निवासी ग्राम कड़सरा थाना परसरामपुर तथा मोहम्मद इस्लाम निवासी ग्राम सुरवारपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के रूप में हुई है। चौधरी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गयी थी। पुलिस ने जांच पड़ताल करके तीनो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक देशी पिस्तौल और 22 हजार रुपये बरामद किया है। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तो के विरूद्व मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है।

सहारनपुर : ज्ञानवापी मामले में आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने का आरोपी गिरफ्तार

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़े एक आपत्तिजनक पोस्ट को सोशल मीडिया में चस्पा करने पर पुलिस ने सहारनपुर के एक युवक को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर के पुलिस थाना नकुड़ के निरीक्षक नरेश कुमार ने बताया कि इस मामले में 21 वर्षीय नासिर पुत्र सुल्तान ने वाट्सअप के जरिये शिवलिंग जैसी दिखने वाली विभिन्न वस्तुओं को वायरल किया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर स्थानीय अदालत में आज पेश कर जेल भेज दिया। इंस्पेक्टर नरेश कुमार और नकुड़ के सीओ अरविंद सिंह पुंडीर ने बताया कि वाट्सअप पर डाली गयी आपत्तिजनक पोस्ट की शिकायत गांव छापुर निवासी अभिगुर्जर ने कोतवाली नकुड़ में बीती रात दर्ज कराई थी। बड़ी संख्या में लोग शिकायत करने कोतवाली नकुड़ पहुंचे थे। पुलिस ने अभिगुर्जर की शिकायत पर आरोपी नासीर पुत्र सुल्तान के खिलाफ आईटी एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

भाजपा राज में अराजकता को बढ़ावा

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता के संरक्षण में अराजकता और अव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा हैं। यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में आरोप लगाया कि भाजपा के नेता तो अहंकार में डूबे हुए हैं और स्थानीय प्रशासन भी सत्तारूढ़ भाजपा के दबाव में असल गुनाहगारों को बचाने लगा है। जनसामान्य के दु:खदर्द की कहीं सुनवाई नहीं। भाजपा राज में हत्या, छेड़खानी, रेप की घटनाएं बेलगाम हैं और बच्चियों तथा महिलाओं को सर्वाधिक अपमानित होना पड़ रहा है। उन्होने कहा कि भाजपा राज में बाल अपराध के नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। एक जनवरी से 30 अप्रैल के बीच चार जिलों में 35 बच्चे 47 बच्चियों समेत कुल 82 मासूम लापता हो गए। देवरिया में 7 बच्चे 16 बच्चियां कुल 23 लापता है। गोरखपुर में 10 बच्चे व 6 बच्चियां कुल 16 तथा कुशीनगर में 15 बच्चे 16 बच्चियां कुल 28 बच्चे गायब है। महाराजगंज में 3 बच्चे 12 बच्चियां कुल 15 बच्चे लापता है। इस तरह 82 बच्चे गायब हुए जिनमें 79 का कोई सुराग नहीं लगा है। अपहरण के केस भी समय से दर्ज नहीं हुए हैं। भाजपा सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि वास्तव में बेखौफ लुटेरों की वजह से महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। भाजपा राज में बहन बेटियां खुद को पूर्णत: असुरक्षित महसूस कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि अपराधियों, भाजपाइयों और पुलिस की तिकड़ी जुगलबंदी से लोगों को और खासकर बहन बेटियों को कैसे बचाया जाए।

मऊ में राशन लेने निकली महिला की सड़क दुर्घटना में मौत

मऊ। उत्तर प्रदेश में मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को सरकारी राशन गल्ले की दुकान पर राशन लेने निकली महिला की डंपर वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि धौरहरा गांव निवासी गीता देवी (55) राशन लेने के लिए सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर पैदल जा रही थी,इस बीच रास्ते में गांव का ही एक लड़का जो साइकिल से जा रहा था। उसकी साइकिल पर बैठकर जाने लगी। जैसे ही कुछ ही दूर पर अतरारी गांव के पास स्थित खैराबाद पुलिस चौकी के समीप साइकिल अनियंत्रित हो गई और पीछे बैठी महिला सड़क पर गिर गई। इस बीच अतरारी चुंगी के तरफ से मुबारकपुर की तरफ जा रही एक डंपर गाड़ी की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई।

सोनभद्र में पत्नी की हत्या कर की आत्महत्या

सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के कोन क्षेत्र में शुक्रवार को एक व्यक्ति ने गृह क्लेश के दौरान कांच की बोतल से प्रहार कर अपनी पत्नी को घायल कर दिया और बाद में खुद पर भी बोतल घोंप ली। गंभीर हालत में दोनो को अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान दोनो की मौत हो गयी। पुलिस अधीक्षक अमरेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि आज सुबह करीब आठ बजे करइल गांव निवासी सरदार उर्फ शारदा चेरो (38) का पत्नी फुलवा देवी (32) से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने काँच की बोतल तोड़ कर पत्नी के पेट में घुसेड़ दी और बाद में खुद को भी घायल कर लिया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोपन पहुंचाया जहाँ इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गय। मृतक दम्पति के तीन बच्चे हैं जिनमें सबसे बड़ा 13 वर्षीय बेटा है।

घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया लेखपाल

जौनपुर। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक इकाई (एंटी करप्शन टीम) की वाराणसी टीम ने शुक्रवार को जौनपुर में एक लेखपाल को भूस्वामी से जमीन की पैमाईश के लिए पांच हजार रुपये की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन टीम प्रभारी इंस्पेक्टर उपेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि आवश्यक कानूनी औपचारिकतायें पूरी कर गिरफ्तार लेखपाल को वाराणसी ले जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मामले की प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में मड़ियाहूं तहसील के जवंसीपुर गांव निवासी राज बहादुर सिंह भूमि कानून के तहत अपनी जमीन में फाट के अंश का रिपोर्ट लगवाने के लिए लेखपाल अजय सिंह पटेल के पास महीनों से चक्कर लगवा रहे थे। लेखपाल उनसे 10 हजार रुपये घूस लिये बिना फाट बनाने के लिए तैयार नहीं था। इसके लिए काश्तकार ने लेखपाल से काफी मिन्नतें की तो वह पांच हजार रुपये लेकर फाट बनाने के लिए राजी हुआ। जिसके बाद शिकायतकर्ता राज बहादुर सिंह पुत्र गिरजा शंकर सिंह निवासी जवंसीपुर ने वाराणसी स्थित भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन टीम) से संपर्क किया और लेखपाल से शुक्रवार को पैसे देने की बात हुई।

आजम खान का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहा- जड़ में अपनों ने डाला जहर

एजेंसी

रामपुर। सीतापुर जेल से बाहर निकल रामपुर पहुंचते ही आजम खान ने इशारों में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है।

आजम के परिवार ने पहले ही उपेक्षा का आरोप लगाकर साफ कर दिया था कि अखिलेश यादव पार्टी के दिग्गज नेता का भरोसा खो चुके हैं। अब आजम ने कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि ज्यादा जुल्म अपनों ने ही किया है। उन्होंने यहां तक कहा कि दरख्तों की जड़ों में अपनों ने ही जहर डाला है।

आजम खान ने जेल में बिताए अपने समय को बेहद कठिन बताते हुए कहा, हमें जेल में ऐसे रखा गया जैसे अंग्रेजों के जमाने में उन कैदियों को रखा जाता था जिन्हें दो-तीन दिन में फांसी होने वाली होती थी। हमारे बैरक के पास ही फांसी घर भी था। हमने जेल में कैसे वक्त गुजारा है, हम ही जानते हैं। पत्नी और बच्चे के आने के बाद बहुत तन्हा महसूस किया। जेल में सुबह होती थी तो शाम का इंतजार और शाम होती थी तो सुबह का इंतजार रहता था मेरे परिवार के साथ जो हुआ कभी नहीं भूल सकते। घर पहुंची भीड़ का शुक्रिया अदा करते हुए आजम खान ने कहा कि हम पर ज्यादातर जुल्म हमारे अपनों ने किया। इन सूखे दरख्तों की जड़ों में जहर डालने वाले हमारे अपने हैं। माना जा रहा है कि आजम खान का इशारा अखिलेश यादव की ओर है। हाल ही में आजम के करीबियों ने खुलकर आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव ने बुरे वक्त में साथ नहीं दिया।

इसके बाद आजम खान ने अखिलेश यादव की ओर से भेजे गए दूतों से मिलने से इनकार कर दिया था।

आजम खान ने कहा, मेरे शहर को उजाड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि यहां तुम्हारी आबादी है। तारीख तो तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है लेकिन भुलाया नहीं जा सकता। आजम खान ने अपने संघर्ष को याद करते हुए कहा, जिंदगी की शुरूआती दौर में जब एएमयू में सेक्रेट्री थे तब मुल्क में इमरजेंसी लगी, तब हमें पौने दो साल बनारस की जेल काटी थी।

जब जिंदगी की शुरूआत हुई थी उस वक्त भी हालात ने हमसे कुर्बानी ली थी और जिंदगी के इस मोड़ पर एक बार फिर कुर्बानी ली चालीस साल का यह लंबा सफर बेकार नहीं जाएगा आसमान की कसम खाकर कहता हूं कि इन सूखे दरख्तों में फिर कपोले फूटेंगी। फिर बहार आएगी।

जुल्म और जालिम की मुद्दत अधिक नहीं होती : आजम

रामपुर। 26 महीने 24 दिन जेल में बिताने के बाद अपने गृह जिले रामपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक मोहम्मद आजम खान ने शुक्रवार को कहा कि जुल्म और जालिम की मुद्दत अधिक नहीं होती है। तारीख गवाह है जब जुल्म खत्म होता है, तो जालिम भी खत्म होता है।

अपने आवास टंकी नंबर 5 पर एक बड़े काफिले के साथ पहुंचे आजम का स्वागत वहां पहले से मौजूद हजारों समर्थकों ने गर्मजोशी से किया। घर के बाहर मुमताज पार्क किनारे आजम ने लोगों को संबोधित करते हुये कहा हमने यह गलियां साढ़े तीन साल बाद देखीं हैं। हम जिंदा खड़े हैं यह एक मोअजजा आश्चर्य है, क्योंकि जहां हमें रखा था,वहां अंग्रेजों के जमाने की कालकोठरी है। जहां अगले दिन बाद फांसी दे दी जाती थी। हमारे बराबर में फांसी घर भी था। बीवी बच्चों के आने के बाद सुबह होती थी तो शाम का ख्याल और रात होती थी तो सुबह का ख्याल होता था।

उन्होने कहा हमारे आपके बीच जो रिश्ते हैं उनमें जुदाई का ख्याल भी नहीं था। जब बहुत छोटे थे तो इमरजेंसी लग गई थी और अलीगढ़ में यूनियन के सेक्रेटरी थे, तब भी हमें गिरफ्तार होना पड़ा था। पौने दो साल बनारस की जेल काटी थी, जब जिंदगी की शुरुआत थी। हमारा 40 साल के सफर में कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी।

बेहद भावुक अंदाज में सपा के बुजुर्ग नेता ने कहा शिक्षा के मंदिर के रूप में हमने यूनिवर्सिटी का पौधा लगाया। दुश्मनों को सद्बुद्धि दे ईश्वर। जिन पेड़ों को यह समझा जा रहा है कि यह सूख गए हैं। तुम्हारे खून पसीने की कसम इन दरख्तों में नई कोपलें निकलेंगी। इन दरख्तों में नई बाहर आएंगी। हम तो नहीं होंगे लेकिन हमारी नस्ले शिक्षा के मंदिर की बहुत बड़ी शक्ल देखेंगे। याद रखो तारीख को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, लेकिन तारीख को मिटाया नहीं जा सकता।

उन्होने कहा मेरे साथ, मेरे घर के साथ, मेरे खानदान के साथ, मेरे शहर और मेरे जिले के साथ जो कुछ हुआ उसे आने वाली नस्लें बर्बादी की यह तारीख पढ़ कर रोया करेंगी। जब उन्हें यह मालूम होगा कि कैसे चमन उजाड़े जाते हैं। यह चमन सिर्फ इसलिए उजाड़ दिया गया कि यहां तुम्हारी आबादी और गिनती ज्यादा है। अगर तुम इस अहसास को महसूस नहीं करोगे तो हमारे जैसे लोग कितने आएंगे और मायूस होकर चले जाएंगे। तुम्हारे मुकद्दर के संभालने वाले थक जाएंगे। उन्हें थकने मत देना।

आजम ने कहा कि जब आप मिलने आते थे तो हम कहते थे कि जिंदा आएंगे तो गाज़ी कहलाएंगे और जनाजा जाएगा तो शहीद कहलाएंगे। तुम्हारे बीच जिंदा आ गए हैं, यह एक आश्चर्य है।

कुछ दिन के लिए आपसे जुदाई चाहते हैं सेहत की वजह से। आज शुक्रिया अदा करेंगे उन इंसाफ करने वालों का जिन्होंने यह साबित किया कि अभी इंसाफ का जमीर जिंदा है।

उन्होने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जज साहब से कहा था कि ऊपर वाले ने अपनी शक्तियों देकर आपको इस कुर्सी पर बैठाया है। इसलिए इंसाफ करना हमारी कम और आपकी ज्यादा जरूरत है। हमारे हक में एक फैसला भी ऐसा नहीं है, जो इंडियन जुडिशरी की तारीफ ना करें । इसीलिए मैं कहता हूं की सुप्रीम कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने विधाता की दी हुई ताकत को इंसाफ के तराजू पर पूरा तौल कर साबित किया कि कायनात के मालिक तूने जो हमें जिम्मेदारी दी थी उसमें ना हमने मजहब देखा, ना धर्म देखा, ना हिंदू, ना मुसलमान देखा और ना मुझ जैसा नादार गरीब देखा। हमें अदालतों का शुक्रगुजार होना है। इंसाफ मिला है उसके लिए शुक्रगुजार होना है।

आजम के रामपुर पहुंचने पर जिले की पुलिस हाई अलर्ट पर रही और उनके घर से लेकर विभिन्न सार्वजनिक चौराहों पर बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद रही और कड़ी निगरानी इंतजाम किए गए। आजम खान जिला रामपुर अपने बेटे अब्दुल्ला आजम और अदीब आजम पत्नी डॉ तजीन फातिमा व अन्य परिजन व समर्थकों के भारी काफिले के साथ अपने आवास पर पहुंचे थे।

अंतरराज्यीय नशा तस्कर गिरोह की सरगना लाखों की स्मैक के साथ गिरफ्तार

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त एक अंतरराज्यीय महिला गिरोह से 23 लाख रुपये की स्मैक के साथ गिरोह की आठ महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया।

शहर के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने शुक्रवार को बताया कि थाना कुतुबशेर पुलिस ने भूरी गिरोह की आठ महिलाओं की कल देर शाम गिरफ्तारी की थी, जिन्हें आज जेल भेजा गया। कुमार ने बताया कि गिरफ्तार महिलाओं में भूरी उर्फ उजमा पत्नी अब्दुल कादिर और बबली उर्फ मुस्तफा पत्नी जहांगीर, नशे की तस्करी के आरोप में पहले भी जेल जा चुकी हैं, जबकि इस गिरोह की छह अन्य महिला तस्कर पहली बार गिरफ्तार हुई हैं। इनमें इमराना पत्नी फिरोज, चांदनी पत्नी नौशाद, हाजिरा पत्नी सलीम, इशरत पत्नी नसीम, अफसाना पत्नी मोहम्मद नदीम और सोनिया पत्नी वसीम शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इस गिरोह की लीडर भूरी उर्फ उजमा का पति अब्दुल कादिर फरार हैं। वह भी नशे के इस अवैध कारोबार में शामिल है। कुमार ने बताया कि महिलाओं का यह गिरोह सहारनपुर में स्कूल, कालेजों और आसपास के मोहल्लों में स्मैक बेचते हैं। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और युवा वर्ग नशे की चपेट में आया है।

सहारनपुर पुलिस को इस गिरोह की गिरफ्तारी के लिए खासतौर से लगाया गया था। थानाध्यक्ष कुतुबशेर पीयूष दीक्षित ने बताया कि गिरफ्तार महिला गिरोह की सभी सदस्य सहारनपुर की रहने वाली हैं। उनके पास से 12490 रुपये भी बरामद हुए हैं। यह गिरोह हरिद्वार, देहरादून, हरियाणा, पंजाब आदि स्थानों पर बड़ी मात्रा में स्मैक की सप्लाई करता है। ये लोग घरों में और उसके आसपास फुटकर में स्मैक बेचते हैं। सोनिया और भूरी बड़ी मात्रा में स्मैक लेकर देहरादून और हरिद्वार तक भी सप्लाई करती हैं।

एसपी सिटी ने यह भी बताया कि गैंग में शामिल युवतियों के साथ अनैतिक कार्य भी कराया जाता है।

देवबंद : विवाहिता से छेड़छाड़ के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं का थाने पर हंगामा

देवबंद। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के देवबंद में बीती रात एक विवाहिता के साथ छेड़छाड़ की घटना के विरोध में दो समुदायों के बीच मारपीट और जमकर हंगामा हुआ। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एवं अन्य संगठनों के लोग देर रात तक देवबंद कोतवाली में डटे रहे।

सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रात में ही एसपी देहात सूरज कुमार राय को देवबंद भेजा। पुलिस ने पांच में से चार नामजद आरोपियों की रात में ही गिरफ्तारी कर ली और पांचवे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिये पुलिस की तीन टीमों को लगाया गया है। घटना के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती थी, लेकिन पुलिस की प्रभावी कार्रवाई से हालात काबू में ही रहे।

कोतवाली प्रभारी प्रभाकर कैंतुरा ने शुक्रवार को बताया कि बीती रात साढ़े आठ बजे के अनाजमंडी क्षेत्र में दूसरे संप्रदाय की विवाहित लड़की के साथ अब्दुल्ला नामक युवक ने छेड़छाड़ की जिसका पीड़िता ने डटकर मुकाबला किया। लड़की के पिता और अन्य करीबी रिश्तेदारों की दुकानें घटना स्थल के पास ही है। हंगामा होते देख मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी अब्दुल्ला के दो भाइयों आफताब एवं गुलजार और उनके पिता इम्तियाज एवं एक अन्य व्यक्ति सलमान पुत्र भूरा ने लड़की पक्ष का साथ देने वालो के साथ मारपीट की।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाठियां भांजकर स्थिति पर काबू पाया।

लड़की के ससुर ने आफताब, गुलजार, अब्दुल्ला और उनके पिता इम्तियाज एवं सलमान पुत्र भूरा के खिलाफ छेड़छाड़, बलवा, जान से मारने की कोशिश और डकैती की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया।

गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में पिछड़ी चीनी मिलों के खिलाफ होगी कार्रवाई : डा. दिनेश्वर मिश्र

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर मंडल में चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 02 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाये के भुगतान में पिछड़ रही चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए जल्द किसानों का बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया है।

राज्य के उप गन्ना आयुक्त डा. दिनेश्वर मिश्र ने शुक्रवार को यहां कहा कि गन्ना किसानों का सहारनपुर मंडल में 2.38 हजार करोड़ रुपये का बकाया है। सबसे ज्यादा, 845 करोड़ रुपये शामली की मिलों पर बकाया है। सहारनपुर की चीनी मिलों पर 656 करोड़ रुपये और मुजफ्फरनगर की चीनी मिलों पर 537 करोड़ रुपये का बकाया है। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की सतत समीक्षा की जा रही है और इसमें भुगतान नहीं करने वाली मिलों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

डा. मिश्र ने बताया कि सहारनपुर मंडल में कुल 17 चीनी मिलों ने इस सत्र में पेराइ की। इनमें से 11 चीनी मिलें पेराई बंद कर चुकी हैं। सहारनपुर की त्रिवेणी ग्रुप की देवबंद और निगम की सरसावा, मुजफ्फरनगर की त्रिवेणी ग्रुप की खतौली एवं सहकारी चीनी मिल मोरना, मंसूरपुर और तितावी चीनी मिलों में ही पेराई सत्र जारी है।

उन्होंने कहा कि भुगतान में पिछड़ी चीनी मिलों के प्रबंधकों को भुगतान के लिए नोटिस दिया गया है और उनसे भुगतान करने की योजना की जानकारी मांगी है। डा. मिश्र ने कहा कि भुगतान के मामले में सहारनपुर मंडल में त्रिवेणी शुगर ग्रुप की देवबंद और खतौली चीनी मिलें समय पर भुगतान कर रही हैं। उन्होंने बताया कि देवबंद चीनी मिल 25 अप्रैल तक खरीदे गए गन्ने का मूल्य भुगतान कर चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि त्रिवेणी शुगर ग्रुप की देवबंद यूनिट के प्रमुख पुष्कर मिश्र के मुताबिक 23 अप्रैल से 25 अप्रैल तक खरीदे गए गन्ना मूल्य की 9 करोड़ 64 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया।

मंडल में 19 मई तक के आंकड़ों के अनुसार 2 हजार 38 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान बकाया है।

मथुरा में वकीलों के कार्य बहिष्कार से दूसरे दिन भी न्यायिक काज प्रभावित

मथुरा। उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा वकीलों के आचरण संबंधी एक पत्र की भाषा से आहत वकीलों के न्यायिक कार्य से विरत होने के कारण मथुरा में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन अदालती कामकाज नही हो सका।

वकीलों के कार्य बहिष्कार से उन तमाम मुवक्किलों को परेशानी हुई जो बार एसोसिएशन के इस निर्णय से अनभिज्ञ थे। वकीलों ने जहां कल बार एसोसिएसन मथुरा द्वारा लिये गए निर्णय के कारण गुरूवार को कार्य बहिष्कार किया वही आज बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर कार्य बहिष्कार किया ।

बार एसोसिएसन मथुरा के अध्यक्ष अजीत तेहरिया ने बताया कि विशेष सचिव प्रफुल्ल कमल ने 14 मई को प्रदेश के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर कहा था कि न्यायालयों में अधिवक्ता की ओर से किये जाने वाले अराजकतापूर्ण कृत्यों का तत्काल संज्ञान लिया जाना सुनिश्चित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए वैक्सीन शीघ्र तैयार होगी : आनंदीबेन

वाराणसी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की भांति ही गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर की रोकथाम के लिए देश में वैक्सीन विकसित की जा रही है। वैक्सीन शीघ्र ही बनकर तैयार हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन का लाभ देश को ही नहीं, बल्कि अन्य देशों को भी मिलेगा।

वैक्सीन का मूल्य न्यूनतम रखे जाने की अपील की गई है। प्रयास यह होना चाहिए कि इसका मूल्य 100 या 200 रुपये से अधिक नहीं हो।

राज्यपाल ने शुक्रवार को यहां

सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग व किशोरियों के ह्यूमन पैपीलोमा वायरस (एचपीवी) टीकाकरण के सम्बन्ध में आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित किया।

उन्होंने 150 किशोरियों के टीकाकरण के अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने किशोरियों के स्वास्थ्य के प्रति अभिभावकों से सजग रहने की अपील की।

उन्होंने कहा कि किशोरी स्वास्थ्य के लिए सरकार काफी प्रयास कर रही है। इन प्रयासों को जमीन पर उतारने के लिए विशेष पहल करने की जरूरत है, ताकि एक स्वस्थ किशोरी स्वस्थ भारत का निर्माण कर देश को सशक्त कर सके।

उन्होंने बताया कि राजभवन के 15 से 20 लाख रुपए प्रति वर्ष के चिकित्सा बजट की धनराशि इस योजना पर खर्च की जाएगी।

राज्यपाल को बताया गया कि वाराणसी की दो लाख महिलाओं का कैंसर जांच के रूप में स्क्रीनिंग किया जाना है। यदि इसमे कोई पीड़ित मिली, तो उसका समुचित इलाज भी सुनिश्चित कराया गया है। इसके साथ ही 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों का टीकाकरण भी कराया जाएगा।

उन्होंने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि प्राय: महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होती है, आवश्यकता होने पर भी वह जांच नहीं कराती हैं। 30 वर्ष के पश्चात महिलाओं को सर्वाइकल एवं विशेष रूप से स्तन कैंसर की जांच नियमित रूप से कराया जाना चाहिए।

मर्यादित आचरण से आदर्श प्रस्तुत करे यूपी विधानसभा: ओम बिरला

लखनऊ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्यों से मर्यादित आचरण, जनहित के लिए प्रतिबद्धता और सामूहिक जवाबदेही के साथ काम करने का आह्वान किया है।

संसदीय लोकतंत्र को शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली बताते हुए उन्होंने संसद और विधानमंडलों को जनता की आकांक्षाओं का मंच कहा और विधायकों को अधिकाधिक चर्चा और संवाद में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया।

श्री बिरला ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की 18 वीं विधानसभा के सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम और विधानसभा को पेपरलेस करने के लिए लागू नई तकनीक %ई विधान% का औपचारिक शुभारंभ किया। उन्होने उत्तर प्रदेश को देश की आध्यत्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना के केंद्र की संज्ञा देते हुए विधानसभा के गौरवशाली इतिहास को भी रेखांकित

किया और कहा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा शायद देश की सबसे बड़ी विधानसभा होगी, यह प्रदेश वो प्रदेश हैं जहां के सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रीय राजनीति के अंदर भी उत्तर प्रदेश की विशेष भूमिका रही है।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हमारे नेताओं ने संसदीय प्रणाली को अपनाया। यह बहस और चर्चा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि विधानसभा की पवित्रता को बनाए रखना जरूरी है। हमें हमेशा लोगों के मुद्दों को सामने रखते हुए तथ्यों के माध्यम से बोलने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने अंत्योदय के लक्ष्य के साथ विधानमंडल को चर्चा-संवाद के सार्थक केंद्र बनाने के लिए प्रेरित भी किया। ओम बिरला ने मात्र एक-डेढ़ माह में %ई-विधान% व्यवस्था को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को धन्यवाद भी दिया।

इस अवसर पर श्री योगी ने कहा हम सदन में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित के लिए चिंतन-मनन करने के लिए आये हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुरूप शासन को तकनीकी से जोड़ने का कार्य हो रहा है। श्री मोदी के डिजिटल मिशन को बढ़ाते हुए %वन नेशन वन एप्लिकेशन% के भाव के साथ विधानसभा में %ई-विधान% प्रणाली लागू की गई है। सीएम योगी ने कहा कि हमने 02 वर्ष पहले ही पेपरलेस बजट को प्रस्तुत कर लिया था। ई कैबिनेट और ई बजट के बाद अब पूरी विधानसभा पेपरलेस हो रही है। 23 मई से शुरू हो रहे सत्र में आवश्यकतानुसार दस्तावेजों की हार्डकॉपी मिल सकेगी लेकिन आगामी सत्रों से सब कुछ पूरी तरह पेपरलेस होगा। नई प्रणाली से परिचय कराते हुए उन्होंने विधायकों से कहा अब सदन में आपको बहुत मोटा बैग लाने की ज़रूरत नहीं होगी। पहले विधायक जब सदन में आते थे तो अपने साथ सहायक को साथ लेकर चलते थे। बहुत बार उनकी सुरक्षाकर्मियों के साथ बहस होती थी कि उनका सहायक बैग लेकर सदन तक उनके साथ जाए। अब ई-विधान के बाद आपका काम सरल हो जाएगा।

कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने विचार रखे। इस पर मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को भी धन्यवाद दिया।

साथ ही कहा कि हम जनता के हितों के लिए मिलकर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के द्वारा उठाये गए सवाल आलोचनात्मक जरूर होते हैं, लेकिन ये सीधे 25 करोड़ जनता के हित के लिए भी होते हैं।

श्री यादव ने कहा कि विधानसभा को देखकर उन्हें तो लगा कि जैसे यह कोई आईटी सेंटर हो।

ग्राम पंचायतों में खुलेंगे कामन सर्विस सेंटर, मिलेंगे रोजगार के अवसर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश ग्रामीण अंचलों में एक लाख 80 हजार कामन सर्विस सेंटर के जरिये साढ़े चार लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की एक कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के चरण में है।

आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि सरकार लोगों तक सभी सुविधाओं को आसानी से पहुंचाने के साथ ही युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश सरकार गांवों 1.80 लाख सीएससी (कामन सर्विस सेंटर) खोलने जा रही है। इससे 4.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

उन्होने बताया कि सरकार अगले पांच वर्षों में प्रदेश में सभी परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार से जोड़ना चाहती है।

साथ ही सरकार की मंशा है कि लोगों को सुविधाओं के लिए भटकना नहीं पड़े और सभी सुविधाएं लोगों को घर के पास उपलब्ध हों। इसी को देखते हुए अगले पांच वर्षों में गांवों में 1.80 लाख सीएससी खोलने की योजना है। इसके जरिए 4.50 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। सरकार की योजना हर ग्राम पंचायत में कम से कम दो सीएससी खोलने की योजना है।

सूत्रों ने बताया कि सीएससी में सरकारी और गैरसरकारी सेवाओं का लाभ ग्रामीण प्राप्त कर सकते हैं। सीएससी में बहुत सारे डिजिटल काम एक ही जगह पर हो जाते हैं।

किसी के खाते में पैसे जमा करना या खाते से पैसे निकालना हो या आनलाइन कोई भी प्रमाणपत्र बनवाना हो तो कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से किए जा सकते हैं।

इसके जरिए युवा गांव में ही आय का साधन विकसित कर सकते हैं। साथ ही दूसरे को रोजगार भी दे सकते हैं।

शार्ट न्यूज

एमेज़ॉन ने स्थानीय स्टोर को डिजिटल दुकान में बदलने के लिए 'स्मार्ट कॉमर्स' किया लॉन्च

नयी दिल्ली। ऑनलाइन मार्केटप्लेस एमेज़ॉन इंडिया ने स्मार्ट कॉमर्स के शुभारंभ की घोषणा की जोकि स्थानीय स्टोर को डिजिटल दुकान में बदलने के लिए एक नई पहल है और 2025 तक 1 करोड़ छोटे व्यवसायों को डिजिटाइज़ करने की प्रतिबद्धता जताई। एमेज़ॉनडॉटइन का उपयोग कर 1.5 लाख से अधिक स्थानीय स्टोर पहले से ही ऑनलाइन बिक्री कर रहे हैं। स्मार्ट कॉमर्स के साथ, स्टोर अब और आगे बढ़ सकते हैं और अपने ऑफ़लाइन संचालन को डिजिटाइज़ कर सकते हैं, अपने स्टोर पर आने वाले ग्राहकों को इन-स्टोर खरीदारी अनुभव प्रदान कर सकते हैं, और सीधे ग्राहकों की सेवा के लिए अपने स्वयं के ऑनलाइन स्टोरफ्रंट बना सकते हैं। किसी भी आकार के स्टोर सीधे अपने स्टोर में या सीधे अपने ऑनलाइन स्टोरफ्रंट के माध्यम से, या एमेज़ॉनडॉटइन पर, अब अपने ग्राहकों को एक विश्वसनीय और भरोसेमंद अनुभव प्रदान करने के लिए एमेज़ॉन के सर्वश्रेष्ठ शॉपिंग इनोवेशन, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल पेमेंट आदि का लाभ उठा सकते हैं। कंपनी ने यहां जारी बयान में कहा कि आने वाले हफ्तों में, स्मार्ट कॉमर्स स्थानीय स्टोरों को बिलिंग और इन्वेंट्री प्रबंधन को डिजिटाइज़ करने और अपने ग्राहकों को एक बेहतर इन-स्टोर अनुभव प्रदान करने में मदद करने के लिए समाधानों का अपना पहला सेट जारी करेगा। इसके बाद उन क्षमताओं का शुभारंभ होगा जो उन्हें मिनटों में अपना ऑनलाइन स्टोरफ्रंट बनाने में सक्षम करेगा, और एक सिंपल वॉइस और चैट-आधारित खरीदारी अनुभव के माध्यम से अपने ग्राहकों की सेवा करेगा।

यात्रियों के लिए ओयो ने की नई पेशकश

नयी दिल्ली। वैश्विक हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ओयो ने आज अपने ग्राहकों को हर बार होटल में पांच रात रहने के बाद मुफ्त में ठहरने का ऑफर देने की घोषणा की है। ओयो ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि इस पहल से भारत में महामारी के बाद के दौर में यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। यह फ्री रूम नाइट ऑफर ओयो के विज़ार्ड लॉयल्टी प्रोग्राम के गोल्ड सदस्यों के लिए उपलब्ध होगा। इसके द्वारा भारत में ओयो के विज़ार्ड होटलों पर 10 प्रतिशत तक की छूट भी दी जाएगी। ओयो ने अपने विज़ार्ड क्लब मेम्बर्स के लिये डिस्काउंट कूपन और वाउचर की पेशकश करने के लिये 13 से ज्यादा जाने-माने ब्राण्ड्स जैसे डोमिनॉज़, लेंसकार्ट, रेबेल फूड्स, गाना, आदि के साथ गठबंधन भी किया हैं। प्लेटफॉर्म के मुख्य सेवा अधिकारी श्रीरंग गोडबोले ओयो विजार्ड की लॉन्चिंग पर कहा, ओयो पैसे को लेकर सचेत रहने वाले ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता है, फिर चाहे यह परिवार हों, दोस्त, छोटे बिजनेस या बड़े कॉर्पोरेट्स के कर्मचारी। मुफ्त में और रियायती मूल्य पर ठहरने जैसे हमारे प्रोत्साहन ग्राहकों को बार-बार ओयो में ठहरने का एक और आकर्षक कारण देते हैं। हमारा मानना है कि लॉयल्टी से जुड़ी बेहतर पेशकश ज्यादातर ग्राहकों को बहुत पसंद आएगी।

रिजर्व बैंक करेगा सरकार को 30307 करोड़ अधिशेष का हस्तांतरण

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड ने वर्ष 2021-22 के लिए 30307 करोड़ रुपये के अधिशेष को केन्द्र सरकार को हस्तातंरित करने को अनुमोदित कर दिया है। आरबीआई के केन्द्रीय बोर्ड की आज हुयी 596वीं बैठक में यह अनुमोदन किया गया। गवर्नर शिक्तकांत दास की अध्यक्षता में हुयी इस बैठक में अपात जोखिम भंडार को भी 5.50 प्रतिशत पर बनाये रखने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद जारी बयान में केन्द्रीय बैंक ने यह जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि केन्द्रीय बोर्ड ने वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट को भी अनुमोदित कर दिया है। इस बैठक में डिप्टी गवर्नर सर्वश्री महेश कुमार जैन, माइकल देबब्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, रबिशंकर और आरबीआई के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक शामिल हुये जिसमें सतीश के मराठे, एस गुरूमूर्ति, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और सुश्री रेवती अय्यर हैं। इस बैठक में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ और वित्तीय सेवायें विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा भी शामिल हुये।

रुपया सात पैसे टूटा

मुंबई। डॉलर के नरम पड़ने और घरेलू स्तर पर शेयर बाजार में तेजी रहने के बावजूद आज अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में अमेरिकी मुद्रा की मांग बढ़ने के कारण रुपया 7 पैसे टूटकर 77.63 रुपये प्रति डॉलर पर रहा। रुपया पिछले सत्र में 77.56 रुपये प्रति डॉलर पर रहा था। रुपया आज पाँच पैसे की मजबूती के साथ 77.51 रुपये प्रति डॉलर पर खुला। सत्र के दौरान यह 77.63 रुपये प्रति डॉलर के निचले और 77.49 रुपये प्रति डॉलर के उच्चतम स्तर के बीच रहा। अंत में पिछले दिवस की तुलना में सात पैसे गिरकर 77.63 रुपये प्रति डॉलर पर रहा।

लगातार दसवें सप्ताह गिरा विदेशी मुद्रा भंडार, 2.7 अरब डॉलर घटकर 593.3 अरब डॉलर

मुंबई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 13 मई को समाप्त सप्ताह में लगातार दसवें सप्ताह कम होता हुआ 2.7 अरब डॉलर घटकर 593.3 अरब डॉलर पर आ गया। इससे पूर्व विदेशी मुद्रा भंडार 06 मई को समाप्त सप्ताह में 1.8 अरब डॉलर कम होकर 595.9 अरब डॉलर, 29 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 2.7 अरब डॉलर घटकर 597.7 अरब डॉलर, 22 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 3.3 अरब डॉलर लुढ़ककर 600.4 अरब डॉलर, 15 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 31.1 करोड़ डॉलर फिसलकर 603.7 अरब डॉलर, 08 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 2.5 अरब डॉलर गिरकर 604 अरब डॉलर, 01 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में रिकॉर्ड 11.2 अरब डॉलर की गिरावट लेकर 606.5 अरब डॉलर पर आ गया। इसी तरह 25 मार्च को समाप्त सप्ताह में दो अरब डॉलर कम होकर 617.6 अरब डॉलर, 18 मार्च को समाप्त सप्ताह में 2.6 अरब डॉलर घटकर 619.7 अरब डॉलर और 11 मार्च को समाप्त में 9.6 अरब डॉलर लुढ़ककर 622.3 अरब डॉलर रहा था। रिजर्व बैंक की ओर से शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़े के अनुसार, 13 मई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 1.3 अरब डॉलर घटकर 529.5 अरब डॉलर पर आ गया। इसी तरह इस अवधि में स्वर्ण भंडार 1.2 अरब डॉलर की गिरावट लेकर 40.6 अरब डॉलर रह गया। आलोच्य सप्ताह विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 16.5 करोड़ डॉलर की कम होकर 18.2 अरब डॉलर पर आ गया। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास आरक्षित निधि 3.9 करोड़ डॉलर की गिरावट के साथ 4.9 अरब डॉलर रह गई।

सरकार को 2021-22 की बचत से 30,307 करोड़ रुपये देगा आरबीआई

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय निदेशक मंडल ने लेखा वर्ष 2021-22 की आरबीआई की बचत से केंद्र सरकार को 30,307 करोड़ रुपये देने के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दी। आरबीआई के गर्वनर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में निदेशक मंडल की बैठक में आकस्मिक संकट के लिए सुरक्षित निधि (सीआरबी) को 5.50 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखने का फैसला किया है। आरबीआई के एक बयान में कहा गया है,% निदेशक मंडल ने लेखा वर्ष 2021-22 के लिए बचत से 30,307 करोड़ रुपये केंद्र सरकार को देने और आकस्मिक संकट के लिए सुरक्षित निधि (सीआरबी) को 5.50 प्रतिशत रखने का फैसला किया है। आरबीआई के निदेशक मंडल की बैठक में घरेलू और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों की भी समीक्षा की गयी। निदेशक मंडल ने लेखा वर्ष 2021-22 में केंद्रीय बैंक के काम की समीक्षा भी की। निदेशक मंडल ने आरबीआई की लेखा वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा-जोखा को भी मंजूरी दी। बैठक में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रबि शंकर और अन्य निदेशक उपस्थित थे। निदेशक मंडल की बैठक में वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि और मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ और वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा शामिल थे।

झूमा शेयर बाजार, ढाई प्रतिशत से अधिक की तेजी

मुंबई। अमेरिका में बेरोजगारी दर अनुमान से कम रहने और चीन के ब्याज दर में पंद्रह आधार अंक की कटौती से वैश्विक अर्थव्यवस्था के मजबूत बने रहने की उम्मीद में स्थानीय स्तर पर हुई चौतरफा लिवाली से सेंसेक्स और निफ्टी पिछले दिवस की भारी गिरावट से उबरते हुए आज ढाई प्रतिशत से अधिक की तेजी पर रहे।

निवेशकों की आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ने एवं आसमान छूती महंगाई की चिंताओं के बीच चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को समर्थन करने के उद्देश्य से आज प्रधान ऋण दर (एलपीआर) में 15 आधार अंक की कटौती कर दी। इससे वैश्विक बाजार में निवेशकों का उत्साह बढ़ा। इससे ब्रिटेन का एफटीएसई 1.93, जर्मनी का डैक्स 1.78, जापान का निक्केई 1.27, हांगकांग का हैंगसेंग 2.96 और चीन का शंघाई कंपोजिट 1.60 प्रतिशत चढ़ गया। साथ ही अमेरिका में बेरोजगारी दर अनुमान से कम रहने का असर भी शेयर बाजारों पर पड़ा। इससे स्थानीय स्तर पर भी निवेशकों की चौतरफा लिवाली से बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 1534.16 अंक की छलांग लगाकर 54 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर के पार 54326.39 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 456.75 अंक उछलकर 16 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर 16266.15 अंक रिपीट 16266.15 अंक पर पहुंच गया। इस दौरान बीएसई का मिडकैप 1.98 प्रतिशत चढ़कर 22,506.85 अंक और स्मॉलकैप 2.13 प्रतिशत की बढ़त लेकर 26,351.29 अंक पर रहा। इस दौरान बीएसई में कुल 3466 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 2524 में लिवाली जबकि 828 में बिकवाली हुई वहीं 114 स्थिर रहे। इसी तरह एनएसई में 48 कंपनियां हरे जबकि शेष दो कंपनी लाल निशान पर रही।

चौतरफा लिवाली से बीएसई के सभी 19 समूहों में तेजी रही। रियल्टी समूह ने सबसे अधिक 4.22 प्रतिशत मुनाफा कमाया। इसके अलावा बेसिक मैटेरियल्स 2.20, सीडीजीएस 2.22, ऊर्जा 2.97, एफएमसीजी 2.16, वित्त 2.53, हेल्थकेयर 3.04, इंडस्ट्रियल्स 3.05, दूरसंचार 2.07, ऑटो 2.74, बैंकिंग 2.91, कैपिटल गुड्स 3.14, धातु 3.75 और तेल एवं गैस समूह के शेयर 2.20 प्रतिशत चढ़े।

कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 722 अंक उछलकर 53,513.97 अंक पर खुला लेकिन बिकवाली के दबाव में थोड़ी देर बाद 53,403.29 अंक के निचले स्तर पर आ गया। इसके बाद शुरू हुई लिवाली से यह लगातार चढ़ता हुआ कारोबार के अंतिम चरण में 54,396.43 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अंत में पिछले दिवस के 52,792.23 अंक की तुलना में 2.91 प्रतिशत की तेजी लेकर 54,326.39 अंक पर रहा।

इसी तरह निफ्टी 234 अंक चढ़कर 16,043.80 अंक पर खुला और सत्र के दौरान 16,003.85 अंक के न्यूनतम जबकि 16,283.05 अंक के उच्चतम स्तर पर भी रहा। अंत में पिछले सत्र के 15,809.40 अंक के मुकाबले 2.89 प्रतिशत की छलांग लगाकर 16,266.15 अंक पर रहा।

इस दौरान सेंसेक्स की सभी 30 कंपनियां तेजी में रही। डॉ. रेड्डी ने सबसे अधिक 8.10 प्रतिशत का मुनाफा कमाया। इनके अलावा बढ़त पर रही प्रमुख कंपनियों में रिलायंस 5.77, टाटा स्टील 4.22, एलटी 4.01, एक्सिस बैंक 3.55, सन फार्मा 3.52, एसबीआई 3.31, एचडीएफसी 3.13, आईसीआईसीआई बैंक 2.79, मारुति 2.40, भारती एयरटेल 2.05, इंफोसिस 1.98, एनटीपीसी 0.91 और टीसीएस 0.71 प्रतिशत है।

भारत में 2021-22 में 83.57 अरब डॉलर की एफडीआई का नया रिकॉर्ड

नयी दिल्ली। सरकार की ओर शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में देश में प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआई) 83.57 अरब डॉलर रहा जो अब तक का सबसे ऊंचा वार्षिक एफडीआई है।

इससे पहले वित्त वर्ष 2020-21 में एफडीआई 81.97 अरब डॉलर के बराबर था।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के एक बयान में कहा है कि यूक्रेन संकट और कोविड-19 महामारी के बावजूद वर्ष 2021-22 में एफडीआई इससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 1.60 अरब डॉलर ऊंचा रहा और वर्ष के दौरान इसका नया रिकॉर्ड बना। वित्त वर्ष 2014-15 में एफडीआई 45.15 अरब डॉलर के बराबर था।

बयान में कहा गया है, भारत में वित्त वर्ष 2003-04 के मुकाबले एफडीआई का स्तर 20 गुना ऊंचा हो चुका है। उस वर्ष यह केवल 4.3 अरब डॉलर था।

मंत्रालय का कहना है कि एफडीआई प्रवाह से भारत के प्रति वैश्विक निवेशकों का आकर्षण संकेत मिलता है। भारत तेजी से दुनिया में निवेश के एक आकर्षक स्थान के रूप में उभर रहा है।

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में सिंगापुर का भारत में एफडीआई प्रवाह सबसे शीर्ष पर रहा, वहां से प्राप्त निवेश का हिस्सा 27 प्रतिशत रहा। उसके बाद अमेरिका का 18 प्रतिशत और मॉरिशस का 16 प्रतिशत रहा था।

विज्ञप्ति के अनुसार वित्त वर्ष के दौरान सबसे ज्यादा (करीब 25 प्रतिशत) एफडीआई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में आया। इस क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा एफडीआई आकर्षित करने वाले राज्यों में कर्नाटक (53 प्रतिशत), दिल्ली (17 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (17 प्रतिशत) सबसे ऊपर रहे।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल प्राप्त एफडीआई में 38 प्रतिशत हिस्से के साथ कर्नाटक सबसे ऊपर रहा। उसके बाद महाराष्ट्र (26 प्रतिशत) और दिल्ली (14 प्रतिशत) का स्थान है।

मंत्रालय ने कहा, पिछले कई वर्षों से नीतियों में सुधार का फल मिला है और एफडीआई में वृद्धि हुयी है।

विनिर्माण क्षेत्र ने वर्ष 2021-22 में 21.34 अरब डॉलर का एफडीआई आकर्षित किया जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में 12.09 अरब डॉलर का एफडीआई आया था।

आइकॉन्स ऑफ भारत के पहले संस्करण की घोषणा

नयी दिल्ली। छोटे उद्यमियों और किसानों के जीवन बदलने वाली सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए इंडियनमनी डॉट कॉम के फ्रीडमऐप ने आज बहुप्रतीक्षित टेलीविजन श्रृंखला, आइकॉन ऑफ भारत लॉन्च करने की घोषणा की।

ऐप के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी एस सुधीर यह घोषणा करते हुये कहा कि तीन महीनों तक यह श्रृंखला एनडीटीवी इंडिया पर हर शनिवार और रविवार को 29 मई से प्रसारित होगा। आइकॉन्स ऑफ भारत में कुल 28 एक घंटे के एपिसोड होंगे। प्रत्येक एपिसोड में भारत के पांच आइकान्स शामिल होंगे, जिन्हें उनकी सफलता की प्रेरक कहानियों के आधार पर चुना गया है।

उन्होंने कहा कि श्रृंखला की कल्पना एक ऐसे मंच के रूप में की गई है जो सपने देखने वालों के असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प का जश्न मनाएगा 7 स्किलिंग भारत के लिए प्राथमिकता होने के साथ, भारत के प्रतीक उन लोगों को समर्पित हैं जिन्होंने न केवल छोटे व्यवसायों के माध्यम से जीवन में वृद्धि की है, बल्कि देश को वैश्विक जनसांख्यिकी पर उद्यमिता के एक गतिशील केंद्र के रूप में चिह्नित किया है। आइकॉन्स ऑफ भारत उन उद्यमियों और किसानों द्वारा किए गए बाधाओं-विरोधी प्रयासों की एक सच्ची स्वीकृति है, जिन्होंने छोटे व्यवसायों, छोटे खेतों और यहां तक कि अपने घरों से भी अपनी आजीविका विकसित करके वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की है।

सुधीर ने कहा कि देश लगातार विकास कर रहा है और कई स्तरों पर नवप्रवर्तन कर रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर नवप्रवर्तन की निरंतर आवश्यकता है।

सऊदी पर्यटन ने ईजमायट्रिप के साथ किया समझौता किया

एजेंसी

नयी दिल्ली। सऊदी पर्यटन प्राधिकरण ने ईजमायट्रिप के व्यापक यात्रा नेटवर्क का लाभ उठाते हुए सऊदी अरब में आने वाले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के साथ एक समझौता किया है।

ईजमायट्रिप ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि इस समझौते के तहत दोनों सऊदी अरब में गुणवत्तापूर्ण पर्यटन अनुभवों को बढ़ावा देने और विकसित करने के साथ भारतीय बाजार में विस्तार करने के लिए प्रमुख पहलों पर संयुक्त रूप से सहयोग करने और विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के अवसरों की तलाश करेंगे।

ईजमायट्रिप इस समझौते के तहत विजिट सऊदी (सऊदी में आओ) पहल को बढ़ावा देगी, भारत में गंतव्य को लेकर जागरुकता और सऊदी अरब के विविध यात्रा अनुभवों को बढ़ाएगा।

सऊदी अरब के लिए ईजमायट्रिप विशेष रूप से पर्यटन पैकेज और विभिन्न गंतव्य ट्रैवल पैकेज की पेशकश कर अपने ग्राहकों के लिए अधिक सुविधा प्रदान करेगा।

सूर्या रोशनी ने एक अरब डॉलर राजस्व को छुआ

नयी दिल्ली। ईआरडब्ल्यू पाइप्स की निर्यातक, ईआरडब्ल्यू जीआई पाइप्स की उत्पादक और लाइटिंग कंपनी सूर्या रोशनी लिमिटेड ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष में एक अरब डॉलर के राजस्व का आंकड़ा हासिल कर लिया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 में 7731 करोड़ रुपये का कारोबार किया है जो इससे पिछले वित्त वर्ष के 5561 करोड़ रुपये के राजस्व की तुलना में 39 प्रतिशत अधिक है। कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के बाद जारी वित्तीय लेखाजोखा में कहा गया है कि इस वित्त वर्ष में उसका शुद्ध लाभ भी 29 प्रतिशत बढ़कर 205 करोड़ रुपये पर पहुंच गया जो मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष में 158 करोड़ रुपये रहा था।

कंपनी के प्रबंध निदेशक राजू बिस्टा ने कहा कि यदि सभी व्यवसायों में लागत अत्यधिक मुद्रास्फीति से प्रभावित नहीं होता तो लाभप्रदता और भी बेहतर होती 7 उच्च लागत को आंशिक रूप से कम करने के लिए सक्रिय रूप से कई मूल्य वृद्धि की गई 7 विवेकपूर्ण वित्तीय कुशाग्रता से प्रेरित, नकद रूपांतरण चक्र सकारात्मक बना रहा। वित्त वर्ष 2021 में 73 दिनों की तुलना में वित्त वर्ष 2022 में कार्यशील पूंजी के दिन घटकर 58 दिन हो गए हैं7

उन्होंने कहा, हमें कंपनी के लिए अब तक के सबसे अधिक राजस्व की रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है, जिसने एक अरब डॉलर का राजस्व के मील के पत्थर को हासिल किया है। मैं इस अभूतपूर्व उपलब्धि का श्रेय हमारी टीम के अथक प्रयासों और नवाचार, उत्पाद और बाजार के विकास, प्रीमियमीकरण और मजबूत ब्रांड इक्विटी पर जोर को देना चाहता हूं।

कंपनी ने मार्च 22 में समाप्त तिमाही में 83 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में अर्जित 58 करोड़ रुपये के लाभ की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है। इस तिमाही में कंपनी का कुल राजस्व 2301 करोड़ रुपये रहा है जो मार्च 21 की इसी तिमाही के 1722 करोड़ रुपये की तुलना में 34 प्रतिशत अधिक है।

ओला-उबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण एजेंसी का नोटिस

एजेंसी

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने एप आधारित टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली दो प्रमुख कंपनियों ओला-उबर के खिलाफ कारोबार में अनुचित व्यवहार अपनाने और उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी किए हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन दोनों कंपनियों के पास शिकायत निवारण की उचित व्यवस्था न होने, सेवाओं में कमी, बुकिंग रद्द करने पर अनाप-शनाप शुल्क और किराए लगाने में इस्तेमाल किए जाने वाले एल्गोरिथम में गड़बड़ी की शिकायतों पर सीसीपीए ने उन्हें नोटिस जारी किए हैं। विज्ञप्ति में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि 01 अप्रैल 2021 से 01 मई 2022 के बीच ग्राहकों ने ओला के खिलाफ 2,482 और उबर के खिलाफ 770 शिकायतें दर्ज करायीं।

विभाग ने पिछले सप्ताह ऐसी कंपनियों की एक बैठक बुलायी थी और उन्हें शिकायत निवारण व्यवस्था के मामले में एनसीएच के साथ जुड़ने को कहा गया था ताकि उनकी शिकायत निवारण व्यवस्था में सुधार हो और वे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और ई-वाणिज्य नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन करें। इस बैठक में ओला-उबर के अलावा रैपिडो, मेरु कैब्स और जुगनु के प्रतिनिधि शामिल हुए।

ओला के खिलाफ इस दौरान मिली शिकायतों में सबसे अधिक 1340 (54 प्रतिशत) शिकायतें सेवा में कमी की रहीं।

कंपनी के खिलाफ 521 (21 प्रतिशत) शिकायतें पैसा वापस ना किए जाने की रहीं। इसी तरह उबर के खिलाफ सेवा में कमी की 473 (61 प्रतिशत) शिकायतें मिली और उपभोक्ता धन ना लौटाने की शिकायतों की संख्या 105 (14) प्रतिशत रही।

आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ताओं ने ओला-उबर के खिलाफ अनाधिकृत किराए लगाने, एमआरपी से ऊपर पैसा लेने, गिफ्ट का वादा उसे ना भेजने, अकाउंट पर रोक लगाने, सेवा में देरी, कटा हुआ पैसा लाभार्थी के खाते में वापस जमा ना होने और धोखाधड़ी आदि की शिकायतें मिली हैं।

मंत्रालय ने कहा है कि इन कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर ग्राहक सेवा नंबर और शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण न होना, शिकायत निवारण व्यवस्था में कमी के दायरे में आता है।

मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि बुकिंग रद्द कराने पर शुल्क ऐसी स्थिति में मनमाना जाता है जहां प्लेटफॉर्म पर यह नहीं दर्शाया गया होता है कि ग्राहक किसी भी बुकिंग को कितने समय के अंदर रद्द करा सकता है। इसी तरह रद्दीकरण शुल्क को बुकिंग के समय मोटे अक्षरों में दर्शाया जाना चाहिए।

पेट्रोल-डीजल के दामों में 44वें दिन भी कोई बदलाव नहीं

नयी दिल्ली। देश में तेल विपणन कंपनियों के शुक्रवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने से लगातार 44वें दिन ईंधन के दाम स्थिर रहें।

सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 105.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल 96.67 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रहा। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 120.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 104.77 रुपये प्रति लीटर है। यूक्रेन तथा रूस के बीच जारी जंग से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में घट-बढ़ जारी है। अंतरराष्ट्रीय लंदन ब्रेंट क्रूड आज 0.77 प्रतिशत गिरकर 111.18 डॉलर प्रति बैरल पर और अमेरिकी क्रूड 1.21 प्रतिशत के दबाव के साथ 110.05 डॉलर प्रति बैरल की कीमत पर कारोबार कर रहा है।

देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें 137 दिन की स्थिरता के बाद गत 22 मार्च से बढ़नी शुरू हुई थीं। जिससे अबतक 14 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की गयी। इस दौरान इनके दामों में करीब 10 रुपये प्रति लीटर की तेजी आयी है।

पेट्रोल-डीजल के मूल्यों की प्रतिदिन समीक्षा की जाती है।

जेट एयरवेज को फिर उड़ान की इजाजत, रॉकेट की तरह भाग रहा कंपनी का शेयर

नई दिल्ली। तीन साल बाद एक बार फिर प्राइवेट सेक्टर की जेट एयरवेज एयरलाइन उड़ान भरने को तैयार है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इसकी अनुमति दे दी है। डीजीसीए प्रमुख अरुण कुमार के मुताबिक जेट एयरवेज को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (एओसी) दे दिया गया है। यह एयरलाइन को कॉमर्शियल उड़ान संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति देता है। एयरलाइन की 2022 में जुलाई-सितंबर तिमाही में कॉमर्शियल उड़ान संचालन को फिर से शुरू करने की योजना है। बीते 5 मई को जेट एयरवेज ने पहली बार टेस्ट उड़ान भरी थी। इसके बाद 3 अनिवार्य उड़ान सेवाएं संचालित की गई थीं। इस उड़ान में डीजीसीए के अधिकारी भी शामिल थे। इसी के बाद एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि वित्तीय संकट की वजह से जेट एयरवेज ने अप्रैल 2019 में उड़ान सेवाएं बंद कर दी थी। वर्तमान में जालान-कलरॉक कंसोर्टियम जेट एयरवेज का प्रमोटर है। इस बीच, सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन जेट एयरवेज के शेयर ने एक बार फिर उड़ान भरी। बीएसई इंडेक्स पर शेयर का भाव 113.30 रुपये था, जो एक दिन पहले के मुकाबले करीब 5 फीसदी की तेजी को दर्शाता है।

विदेशी निवेशकों को भारत पसंद : विदेश से आया रिकॉर्ड तोड़ 83.57 अरब डॉलर का निवेश

नई दिल्ली। जहां एक तरफ महंगाई के मोर्चे पर लगातार बुरी खबर आ रही है। वहीं, दूसरी तरफ विदेशी निवेश के मामले में भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। विदेशी निवेशक देश में जमकर निवेश कर रहे हैं। निवेश के लिए भारत पसंदीदा देश बनता जा रहा है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में देश में रिकॉर्ड तोड़ विदेशी निवेश आया है। इसकी जानकारी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई हासिल किया है, जो अब तक किसी भी वित्त वर्ष में सबसे अधिक है।

सिंगापुर से आया सबसे ज्यादा FDI

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर की अब तक का सबसे ज्यादा सालाना एफडीआई आया है।'' इससे पहले वित्त वर्ष 2020-21 में एफडीआई इनफ्लो 81.97 अरब अमेरिकी डॉलर था। भारत में निवेश करने वाले प्रमुख निवेशक देशों के मामले में सिंगापुर 27 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद अमेरिका है जो कि 18 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर और 16 फीसदी के साथ मॉरीशस तीसरे का स्थान है।

इस सेक्टर में सबसे अधिक निवेश

मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबकि, ''मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत बहुत तेजी से विदेशी निवेश के लिए पसंदीदा देश के रूप में तेजी से उभर रहा है।'' मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई इक्विटी इनफ्लो 2020-21 (12.09 अरब डॉलर) की तुलना में 2021-22 में (21.34 अरब डॉलर) 76 प्रतिशत बढ़ा है। मंत्रालय के मुताबिक, भारत में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के सेक्टर में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश देखने को मिला है। इसके बाद सबसे अधिक विदेशी निवेश सर्विस सेक्टर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मिला है।

शार्ट न्यूज

सोनी ने भारत में रौलां गैरो के लिए चार भाषाओं में कमेंटरी की व्यवस्था की

मुंबई। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क साल के दूसरा ग्रैंड स्लेम इवेंट रौलां गैरो 2022 के प्रसारण की तैयारी कर रहा है, जो 22 मई से शुरू होने जा रहा है। यह पहला साल है जब स्पोर्ट्स नेटवर्क प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम दिखाएगा और इसका प्रसारण इवेंट के लाइव कवरेज के साथ चार भाषाओं में किया जाएगा। भारत में पहली बार दर्शक अपनी पसंद की भाषा, इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु में रौलां गैरो को देख सकेंगे। इस इवेंट का प्रसारण सोनी सिक्स, सोनी टेन 2, सोनी टेन 3, और सोनी टेन 4 चैनलों और टूर्नामेंट की लाइव-स्ट्रीम इसके ऑन-डिमांड ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनीलिव पर किया जाएगा। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क दर्शकों को चार भाषाओं और एक लाइव स्टूडियो शो के साथ टूर्नामेंट के संपूर्ण कवरेज के द्वारा इस विशाल आयोजन का बेमिसाल दृश्यात्मक अनुभव प्रदान करेगा। इस टूर्नामेंट में एक्स्ट्रा सर्व की वापसी होगी जो ग्रैंड स्लेम टूर्नामेंटों के लिए प्रसारक का प्रमुख शो है। इस शो को सार्थक लाल होस्ट करेंगे और ओलंपियन सोमदेव देववर्मन, डेविस कप खिलाड़ी पूरव राजा और पूर्व टेनिस खिलाड़ी गौरव नाटेकर जैसे विशेषज्ञ पैनलिस्ट दिखाई देंगे। सोनी टेन 3 चैनलों पर हिंदी भाषा में मनीष बताविया, आतिश ठुकराल और गौरव नाटेकर कमेंटरी करेंगे। वर्तमान भारतीय खिलाड़ी जीवन नेदुन्शेझियन और अरुण वेणुगोपाल तमिल कमेंटरी पैनल में शामिल होंगे, जबकि एशियाई गेम के पदक विजेता विष्णु वर्धन तथा संदीप कुमार इस चैनल पर तेलुगु भाषा में कमेंटरी करेंगे।

वॉर्म-अप मैच से पहले न्यूज़ीलैंड के तीन सदस्य हुए कोरोना से संक्रमित

लंदन। इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज़ खेलने गई न्यूज़ीलैंड के तीन सदस्य कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। शुक्रवार सुबह को तेज़ गेंदबाज़ ब्लेयर टिकनर, बल्लेबाज़ हेनरी निकोलस और गेंदबाज़ी कोच शेन ज्युरगेंसन के रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद तीनों सदस्यों को पांच दिन के आइसोलेशन में भेज दिया गया है। यह सभी इस समय होटल के कमरों में आइसोलेशन का समय व्यतीत कर रहे हैं। न्यूज़ीलेंड क्रिकेट द्वारा जारी की गई मीडिया रीलीज़ में इस बात की पुष्टि हुई है कि संक्रमित पाए गए तीनों सदस्यों के अलावा तमाम सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं 20 मई से 23 मई तक खेले जाने वाला ससेक्स के ख़िलाफ़ वॉर्म-अप मैच प्रभावित नहीं होगा। 46 टेस्ट मैचों में 40.38 के औसत से आठ टेस्ट शतक बनाने वाले निकोलस न्यूज़ीलैंड के मध्य क्रम का अहम हिस्सा हैं। तेज़ गेंदबाज़ टिकनर ने अब तक टेस्ट मैचों में न्यूज़ीलैंड के लिए पदार्पण नहीं किया है। हालांकि वह दो वनडे और आठ टी20 मुक़ाबलों में न्यूज़ीलैंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। गेंदबाज़ी कोच ज्युरगेंसन 2016 से ही न्यूज़ीलेंड के गेंदबाज़ी कोच बने हुए हैं, उनका मौजूदा कार्यकाल 2022 में समाप्त होगा। इससे पहले वह 2008 से लेकर 2010 तक न्यूज़ीलैंड को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ससेक्स के ख़िलाफ़ मैच खेलने के बाद न्यूज़ीलैंड को 26 मई को एफ़सीसी ड्ढ के विरुद्ध भी एक वॉर्म अप मैच खेलना है। तीन मैचों की टेस्ट सीरीज़ 2 जून से शुरु होगी जबकि दूसरा टेस्ट नॉटिंघम में 10 जून से शुरु होगा। वहीं सीरीज़ का अंतिम मुक़ाबला 23 जून को हेडिंग्ली में शुरु होगा।

अनिकेत चौधरी का रघुबीर क्रिकेट के उद्घाटन मैच में शानदार खेल

नयी दिल्ली। मैन ऑफ द मैच अनिकेत चौधरी (3/31), योगेश नागर (2/5), अरुण छपराना (45 रन), वैभव रावल (36 रन), प्रमोद चंदेला (23) के दम पर एसीसी इलेवन ने मॉडर्न स्कूल बाराखंभा रोड में शुक्रवार से शुरु हुए 45वें अखिल भारतीय लाला रघुबीर सिंह मेमोरियल हॉट वेदर क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में हरियाणा क्रिकेट अकादमी को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। पराजित टीम की ओर से जसमीत नैन (40), विपुल कम्बोज (25) ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। इससे पहले टूर्नामेंट का उद्घाटन अशोक प्रताप सिंह और डॉ. विजय दत्ता (प्रिंसिपल और आयोजक सचिव) ने किया। संक्षिप्त स्कोर: हरियाणा अकादमी: 149 रन 38.3 ओवर में ऑलआउट (जसमीत नैन 40, विपुल कम्बोज 25, अनिकेत चौधरी 3/31, योगेश नगर 2/5), एसीसी इलेवन : 28 ओवर में 154/3 ? (अरुण छपराना 45 रन, वैभव रावल 36 रन, प्रमोद चंदेला 23, हितेश जेमिनी 1/12)

ज़िंग बेल्स जले तो आउट दो : आकाश चोपड़ा

मुम्बई। पूर्व भारतीय बल्लेबाज़ और क्रिकइंफ़ो में एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा का मानना है कि अगर ज़िंग बेल्स जल जाती हैं और गिरती नहीं है तब भी बल्लेबाज़ को आउट देना चाहिए। यह बात उन्होंने उस वाकये के बाद कही जब गुरूवार को वानखेड़े में गुजरात टाइटंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुक़ाबले में बल्लेबाज़ी करने आए ग्लेन मैक्सवेल, राशिद ख़ान की पहली ही गेंद पर पूरी तरह से बीट हुए और गेंद स्टंप्स से टकराते हुए बाउंड्री पर चली गई लेकिन ज़िंग बेल्स गिरी ही नहीं। चोपड़ा ने कहा, बत्ती जल गई तो बल्लेबाज़ की बत्ती गुल हो जानी चाहिए इसमें कोई शक नहीं है। ये ज़िंग बेल्स हैं, जो बहुत भारी होती हैं। जब लकड़ी की बेल्स आई थीं तो इसलिए आई थीं कि अगर गेंद हल्की सी भी स्टंप्स पर लगे तो यह गिर जाती थीं। कई बार तो यह हवा अधिक चलने पर ही गिर जाती थीं, तब इनको गीला करके रखा जाता था। आज कल ज़िंग बेल्स हल्का सा थपकी भी लगाओ तो गिरती नहीं हैं क्योंकि ये बहुत भारी होती हैं। मेरा तो यही मानना है कि लाइट जलती है तो आउट देना चाहिए। इस नियम में बदलाव की ज़रूरत है। चोपड़ा ने इस मामले में कहा, यह दुर्भायपूर्ण है कि हम सब लकीर के फ़कीर बन जाते हैं। अब अगर आपके पास वह सबूत नहीं है और थर्ड अंपायर के भी हाथ बंधे हैं तो यह प्रोटोकॉल है कि अंपायर को आउट देना होगा। हालांकि, मेरा मानना है कि तब सामान्य बुद्धि के साथ जाना चाहिए। थोड़ा सा नियमों में लचीलापन होना जरूरी है। ग़लती कोई जानबूझकर नहीं करेगा, लेकिन सामान्य बुद्धि का प्रयोग होना चाहिए। इस मैच में ऐसा ही एक वाकया पहली पारी में अल्ट्रा ऐज़ को लेकर भी हुआ। मैक्सवेल की गेंद पर मैथ्यू वेड को अंपायर ने एलबीडब्ल्यू दे दिया। वेड ने तुरंत डीआरएस ले लिया क्योंकि वह जानते थे कि गेंद उनके बल्ले या ग्लव्स से लगकर पैड पर लगी है, लेकिन अल्ट्रा एज़ में दिखा कि गेंद कहीं भी बल्ले या ग्लव्स से नहीं लगी है। थर्ड अंपायर ने भी उन्हें आउट दिया और वेड बेहद निराश दिखे। पवेलियन पहुंचकर उन्होंने अपना हेलमेट दीवार पर देकर मारा और बल्ला भी फ़ेंक दिया।

'हम भविष्य की टीम का निर्माण कर रहे हैं'

मुम्बई। मुम्बई इंडियंस के मुख्य कोच माहेला जयवर्धने ने कहा है कि टीम अगले सत्र से पहले किन योजनाओं पर काम करेगी और साथ ही यह भी बताया कि टीम में प्रतिभाशाली नए चेहरों का क्या महत्व है। जयवर्धने ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले मैच की पूर्वसंध्या पर कहा कि उन क्षेत्रों की पहचान करना जरूरी है जिनमें सुधार की आवश्यकता है और सीजन से हासिल सकारात्मक पक्षों को संजोना - इस तरह मुंबई इंडियंस आईपीएल 2022 के बाद खुद को डीब्रीफ और रीग्रुप करेगी। सीजन से हासिल अनुभवों को लेकर मुख्य कोच जयवर्धने की सोच बिल्कुल स्पष्ट दिखी। जयवर्धने ने कहा, इस साल हमारे लिए चिंता की मुख्य बात यह रही कि टूर्नामेंट के शुरुआती चरणों में दबाव की स्थिति में हम खुद को ठीक से संभाल नहीं सके। ऐसे कई मैच थे जहां हमें जीतने के मौके मिले। आमतौर पर हम उन मैचों में जीत हासिल कर लेते हैं लेकिन इस साल हम ऐसा नहीं कर सके और हमने बल्ले और गेंद दोनों के साथ कई अवसर गंवाए। हम लोगों से इस बारे में बात करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हम आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हैं। यह एक चक्र है और हमें यह समझना होगा कि अगले साल इस चक्र को पूरा करने के लिए हमें टीम को फिर से खड़ा करना है। एमआई एक ब्रांड है और इसी कारण हमें इस टीम को पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से अच्छे से निकालना है। हां, इस साल हमें काफी कुछ सीखने को मिला है। और हम यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि हम आगे चलकर वही गलतियाँ न करें। मुख्य कोच ने कहा, हमारे पास मैच को अपने पक्ष में करने क लिए जरूरी किलर इंस्टिंक्ट नहीं था।

धोनी अगले साल भी कर सकते हैं चेन्नई की कप्तानी

चेन्नई। आईपीएल के गत विजेता चेन्नई सुपर किंग्स और उनके समर्थकों के लिए एक बड़ी ख़ुशी की बात है कि महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर अगले साल चार बार विजयी रह चुकी टीम में दिख सकते हैं। यही नहीं 41 वर्षीय धोनी शायद इस फ़्रैंचाइज़ी की कप्तानी भी करते दिखेंगे।

2022 का सीज़न चेन्नई के लिए निराशाजनक रहा है और वह प्लेऑफ़ की दौड़ से बाहर होने वाली दूसरी टीम है।

ईएसपीएनक्रिकइंफ़ो को पता चला है कि धोनी ने टीम प्रबंधन से अगले साल उपलब्ध होने की बात की है और यह भी बताया है कि वह कप्तानी करेंगे। साथ ही कप्तानी छोड़ने के बाद चोटिल होने के बाद इस सीज़न से बाहर हुए हरफ़नमौला रवींद्र जडेजा भी 2023 आईपीएल के लिए टीम में लौटेंगे। उनके बाहर जाने के तरीक़े से अफ़वाहों का बाज़ार गर्म हो गया था।

सीज़न के शुरुआत में चेन्नई ने जिन चार खिलाड़ियों को रिटेन किया था उनमें ये दोनों सबसे प्रमुख थे। जहां जडेजा को 16 करोड़ रुपयों की राशि में सबसे पहले टीम में रखा गया था तो वहीं धोनी 14 करोड़ के साथ दूसरे नंबर के पिक थे।

इस सीज़न के नौवें मैच से पहले जडेजा ने कप्तानी त्यागने का फ़ैसला किया था और सनराइज़र्स हैदराबाद के ख़िलाफ़ धोनी पुनः चेन्नई के लिए टॉस में दिखे थे। जब डैनी मॉरिसन ने उनसे पूछा कि क्या वह अगले सीज़न फिर से चेन्नई की पीली जर्सी में खेलते दिखेंगे तो उन्होंने कहा था, आप मुझे ज़रूर पीली जर्सी में देखेंगे लेकिन यह वाली या कोई और इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा।

जडेजा के कप्तानी से हटने और फिर टीम से हट जाने पर चेन्नई की दीर्घावधि में कप्तानी के विकल्पों पर काफ़ी बातचीत होती रही है। धोनी ने ख़ुद जडेजा के बचाव में हैदराबाद के साथ मैच के बाद कहा था, जब आप कप्तान बन जाते हो, तो कई चीज़ें आपके दिमाग़ को प्रभावित करती हैं।

मुझे लगता है कि कप्तानी से उनकी तैयारी और प्रदर्शन प्रभावित हुआ। एक खिलाड़ी से कप्तान बनना एक धीमी प्रक्रिया होती है। आपको मैच के महत्वपूर्ण क्षणों में अपनी ज़िम्मेदारी लेते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। जब आप कप्तान बन जाते हैं तो आपको अपने खेल के अलावा भी कई चीज़ों पर ध्यान देना होता है। जडेजा इतना दबाव ले रहे थे कि उनसे कैच छूटने लगे थे। अमूमन ऐसा नहीं होता है। पिछले साल अक्तूबर में आईपीएल ख़िताब जीतने के बाद चेन्नई के मालिक एन श्रीनिवासन ने कहा था कि धोनी चेन्नई का ही नहीं पूरे तमिलनाडु का अभिन्न हिस्सा हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा था, धोनी के बिना कोई सीएसके नहीं और सीएसके के बिना कोई धोनी नहीं।

उसके एक महीने बाद जब टीम का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था तब उन्होंने कहा था, लोग उन्हें परेशान करते रहते हैं कि क्या आप खेलना जारी रखेंगे ? अरे वह हमारे साथ ही हैं और कहीं नहीं जा रहे।

ऐसे में मैं ख़ुश हूं कि जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्या उत्तरदान छोड़ कर जा रहे हैं तो उनका जवाब हमेशा होता है, मैं कहीं गया ही नहीं।

अगला साल मेरा आखिरी होगा या नहीं, मुझे नहीं पता

मुम्बई। चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शुक्रवार को कहा कि अगले साल मेरे पास चेन्नई में खेलने का मौक़ा होगा। अगला साल मेरा आख़िरी साल होगा या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। धोनी ने टॉस जीतने के बाद कहा, मेरे लिए चेन्नई में जाकर नहीं खेलना नाइंसाफी होगी। एक खिलाड़ी या व्यक्ति के तौर पर वहां मुझे बहुत प्यार मिला है। अगले साल मेरे पास चेन्नई में खेलने का मौक़ा होगा। अगला साल मेरा आख़िरी साल होगा या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता लेकिन मैं यह ज़रूर कह सकता हूं कि अगले साल हम मज़बूती से वापसी करेंगे।

हम पहले दिन से ही जानते थे कि चटगांव टेस्ट ड्रॉ होगा : धनंजय डीसिल्वा

एजेंसी

चटगांव। चटगांव टेस्ट में तीन पारियां भी पूरी नहीं हो पाईं। विपरीत परिस्थितियों से गुज़रे बांग्लादेश और श्रीलंका, दोनों के बल्लेबाज़ी क्रम ने ज़हूर अहमद चौधरी स्टेडियम की सपाट पिच पर रनों की प्यास मिटाने का अच्छा काम किया। भारत में मार्च में खेलते हुए श्रीलंका ने चार पारियों में 208 से अधिक नहीं बनाए थे और वहीं बांग्लादेशी टीम पिछले छह महीनों में चार बार 150 से कम पर ऑल आउट हो चुकी थी। इसमें दक्षिण अफ़्रीका में पिछले महीने बनाए 53 और 80 भी शामिल हैं।

बल्लेबाज़ों ने इस टेस्ट में 44.88 की औसत से तीन शतक और छह अर्धशतक जड़े। कई बार विकेट गुच्छों में गिरे लेकिन आने वाले बल्लेबाज़ों ने पारी को संभाल लिया। श्रीलंका के साथ ऐसा पहले, दूसरे और पांचवे दिन में हुआ और मेज़बान टीम ने भी ऐसा चौथे दिन के दूसरे सत्र में कर दिखाया। नईम हसन ने पारी में छह विकेट लिए और कसुन रजिता और तैजुल इस्लाम ने चार-चार विकेट लिए लेकिन गेंदबाज़ों के लिए ना तो परिस्थितियां अनुकूल थीं और ना ही चटगांव का मौसम।

पिछले साल काइल मेयर्स के अविजित 210 ने वेस्टइंडीज़ को चटगांव में ही अविश्वसनीय जीत दिलाई थी। पिच ने वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा बांग्लादेश के गेंदबाज़ों ने उम्मीद की थी। इसी मैदान पर श्रीलंका ने 2014 और 2018 के अपने पिछले दोनों मुक़ाबलों में ख़ूब सारे रन बनाए थे और 2018 में इस पिच को आईसीसी का डिमेरिट अंक भी मिला था। 2016 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट में चटगांव पिच की प्रशंसा हुई थी।

दिल्ली कैपिटल्स के लिए करो या मरो का मुकाबला

मुम्बई। दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुम्बई इंडियंस के खिलाफ शनिवार को वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला आईपीएल का 69वां मैच करो या मरो का मुकाबला होगा जिसे जीतने की सूरत में ही दिल्ली प्लेऑफ में पहुंच पाएगी। दिल्ली के 13 मैचों में सात जीत के बाद 14 अंक हैं और वह तालिका में पांचवें स्थान पर है। अगली जीत उसे 16 अंकों पर पहुंचाएगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी कल की जीत के बाद 16 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है और उसकी उम्मीदें भी दिल्ली की हार पर टिकी हुई हैं। बेंगलुरु का नेट रन रेट -0.253 है जबकि दिल्ली का नेट रन रेट 0.255 हैं। दोनों टीमों के 16 अंक होने की सूरत में नेट रन रेट प्लेऑफ की चौथी टीम का फैसला करेगा।

दिल्ली की उम्मीदें उसके ओपनर डेविड वॉर्नर पर टिकी हुई हैं। इस सीज़न में दिल्ली के प्रमुख रन स्कोरर बने वॉर्नर ने 11 मैचों में 427 रन बनाए हैं, जिसमें उनकी औसत 53.37 और स्ट्राइक रेट 151.95 रहा है। 2016 से मुंबई के ख़िलाफ़ उन्होंने आठ मैचों में 64.83 के औसत से 389 रन बनाए हैं। मुंबई के ख़िलाफ़ उनके अंतिम तीन स्कोर 36, 85* और 60 के हैं।

इस सीज़न में चोट के कारण तीन मैच नहीं खेलने के बाद भी ख़लील अहमद ने नौ मैचों में 18.18 के औसत से 16 विकेट लेकर शीर्ष विकेट लेने वालों में से एक हैं। उन्होंने मुंबई के ख़िलाफ़ खेले गए तीन मैचों में छह विकेट लिए हैं। इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ियों में से एक मिचेल मार्श ने साबित कर दिया है कि क्यों वह टी20 मैचों में विशेष हैं। पावरप्ले में उन्होंने 136.90 के स्ट्राइक रेट से 115 रन बनाए हैं और सिर्फ़ दो बार ही आउट हुए हैं।

उनके अंतिम दो स्कोर 89(62) और 63(48) हैं और उन्होंने तीन पारियों में चार विकेट भी लिए हैं।

दिल्ली के ख़िलाफ़ मुम्बई के विकेटकीपर बल्लेबाज़ इशान किशन का बल्ला ख़ूब बोलता है। उन्होंने दिल्ली के ख़िलाफ़ 12 मैचों में 48.25 के औसत और 147.33 के स्ट्राइक रेट से 386 रन बनाए हैं। उन्होंने किसी भी अन्य आईपीएल विपक्ष की तुलना में दिल्ली के ख़िलाफ़ अधिक रन बनाए हैं। उन्होंने इस सीज़न में दस कैच लपके और दो रन आउट भी किए।

इशान किशन के ओपनिंग पार्टनर और मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा हैदराबाद के ख़िलाफ़ 36 गेंदों में 48 रन बनाकर आख़िरकार फ़ॉर्म में आ गए हैं। उन्होंने 2019 के बाद से वानखेड़े स्टेडियम में 10 मैचों में 39.66 की औसत और 135.74 के स्ट्राइक रेट से 357 रन बनाए हैं। 2022 में वह पावरप्ले में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिनके नाम 18 टी20 मैचों में 303 रन हैं।

चोट से उबरने के बाद एनरिक नोर्त्जे ने शानदार वापसी की है और अंतिम चार पारियों में सात विकेट लिए हैं।

अमेरिका तक पहुंचा मंकी पॉक्स, जानें- कैसे होता है संक्रमण; किन्हें बना रहा ज्यादा शिकार

नई दिल्ली। यूरोपीय और अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाल के दिनों में मंकीपॉक्स के कई मामलों की पहचान की है। मंकीपॉक्स के केस युवा पुरुषों में अधिक देखे जा रहे हैं। अफ्रीका के बाहर यह बीमारी पहली बार इतनी बड़ी संख्या में रिपोर्ट की जा रही है। भारत सहित दुनिया भर के स्वास्थ्य अधिकारी इसके मामलों पर नजर रख रहे हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं।

क्या है मंकीपॉक्स?

मंकीपॉक्स एक वायरस है जो कि आम तौर पर जंगली जानवरों में होता है। लेकिन इसके कुछ केस मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के लोगों में भी देखे गए हैं। पहली बार इस बीमारी की पहचान 1958 में हुई थी। उस वक्त रिसर्च करने वाले बंदरों में चेचक जैसी बीमारी हुई थी इसीलिए इसे मंकीपॉक्स कहा जाता है। पहली बार इंसानों में इसका संक्रमण 1970 में कांगों में एक 9 साल के लड़के को हुआ था। मंकीपॉक्स किसी संक्रमित जानवर के काटने या उसके खून या फिर उसके फर को छूने से हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि यह चूहों,

चूहों और गिलहरियों द्वारा फैलता है।

मंकीपॉक्स के लक्षण और इलाज?

मंकीपॉक्स चेचक वायरस परिवार से संबंधित है। अधिकतर मरीज बुखार, शरीर में दर्द, ठंड लगना और थकान जैसे लक्षण का अनुभव करते हैं। अधिक गंभीर बीमारियों वाले लोगों के चेहरे और हाथों पर दाने और घाव हो सकते हैं जो कि शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकते हैं। यह आमतौर पर 5 से 20 दिनों के बीच ठीक हो जाता है। अधिकतर लोगों को इसके लिए हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है।

मंकीपॉक्स 10 में से एक व्यक्ति के लिए घातक हो सकता है और बच्चों के केस में इसे गंभीर माना जता है। चेचक के टीकों का मंकीपॉक्स पर भी प्रभाव रहता है। मंकीपॉक्स को लेकर अब एंटीवायरल दवाएं भी विकसित की जा रही हैं।

कितने लोग मंकीपॉक्स से प्रभावित होते हैं?

वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि करीब एक दर्जन अफ्रीकी देश हर साल मंकीपॉक्स से प्रभावित होते हैं। इसमें से सबसे अधिक केस कांगो से रिपोर्ट होते हैं। कांगो में सालाना 6000 केस रिपोर्ट होते हैं।

इके साथ ही नाइजीरिया में सालाना 3000 केस रिपोर्ट होते हैं।

अफ्रीका के बाहर अब तक गिने-चुने केस ही दिखाई दिए हैं। ये मामले भी अफ्रीका से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि पीड़ित इंसान मंकीपॉक्स प्रभावित क्षेत्र में गया हो। 2003 में अमेरिका में मंकीपॉक्स के 47 केस सामने आए थे।

मंकीपॉक्स के अभी आ रहे केस अलग तरह के हैं?

रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब मंकीपॉक्स उन लोगों में फैल रहा है जो अफ्रीका की यात्रा पर नहीं गए थे। यूरोप में ब्रिटेन, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन में मंकीपॉक्स के केस आए हैं। अधिकतर केस में वे पुरुष मंकीपॉक्स से पीड़ित हुए हैं जो पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाए हैं हालांकि सभी केस के पीछे यह कारण नहीं है। क्या सेक्स करने से मंकीपॉक्स हो सकता है ? ऐसा संभव है लेकिन अब तक इसका कोई साफ-सीधा जवाब नहीं है। ऐसे में अधिकारी अभी भी संक्रमणों के कारणों की जांच कर रहे हैं।

भारत के लिए खतरे की घंटी?

अशोका यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफ़ेसर और वायरोलॉजिस्ट सोक्टोर शाहिद जमील का कहना है कि इसे लेकर चिंता करने की करने जरूरत नहीं है लेकिन साफ-सफाई और जागरूकता जरूरी है। चिकित्सक और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ राजीव जयदेवन ने कहा है कि हमें मंकीपॉक्स के बारे में अभी बहुत जानकारी नहीं है ऐसे में इसके बारे में अभी हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। चूंकि मंकीपॉक्स कई देशों में पहुंच चुकी है ऐसे में हमें सतर्क रहने की जरूरत है।

हमजा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर एलएचसी करेगा सुनवाई

इस्लामाबाद। लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) शुक्रवार को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में हमजा शाहबाज के चुनाव को चुनौती देने वाली पीटीआई द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। जियो न्यूज ने यह जानकारी दी। एलएचसी के मुख्य न्यायाधीश अमीर भट्टी की अध्यक्षता वाली पीठ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सांसद सिब्तैन खान और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में दावा किया है कि पुलिस ने पीटीआई और पीएमएल-क्यू के सदस्यों को श्री हमजा के इशारे पर वोट देने के उनके अधिकार का प्रयोग करने से रोकने के लिए पंजाब विधानसभा से बाहर करने के लिए मजबूर किया जिसके कारण दंगे और अराजकता हुई। इसके बाद हमजा को पंजाब का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया। उन्होंने प्रांतीय विधानसभा के अंदर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी पर भी सवाल उठाया, यह कहते हुए कि विधानसभा के सचिव ने गैर-सदस्यों को विधानसभा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उप सचिव ने सदन के अंदर 300 गैर-सदस्यों को बुलाया था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि चुनाव में फर्जी मतदान हुआ था। उन्होंने दावा किया कि पीटीआई एमपीए अहसान सलीम बरियार ने वोट नहीं डाला जबकि उनका नाम मतदाता सूची में था। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि हमजा शाहबाज के पंजाब के मुख्यमंत्री के चुनाव को अमान्य घोषित किया जाए। इस बीच, पंजाब विधानसभा अध्यक्ष चौधरी परवेज इलाही, जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी थे, ने हमजा के चुनाव को चुनौती देते हुए एक अलग याचिका दायर की। इस याचिका में हमजा और अन्य संबंधित व्यक्तियों को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया। इलाही ने कहा है कि श्री हमजा के पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने के लिए अपेक्षित समर्थन नहीं है। उन्होंने यह दावा करते हुए कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मुहम्मद मजारी ने श्री हमजा के सीएम-चुनाव को अन्यायपूर्ण घोषित किया। कुछ दिनों पहले, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 3- 2 के विभाजन के फैसले में, अर्थात् पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर ने सहमति व्यक्त की कि असंतुष्ट सदस्यों के वोटों की गणना नहीं की जानी चाहिए जबकि न्यायमूर्ति जमाल मंडोखाइल और न्यायमूर्ति मजहर आलम खान मियांखेल ने फैसले से असहमति जताई।

क्या यूक्रेन युद्ध में रूस की हार हो गई है, ऐसा क्यों कहने लगे हैं कुछ जानकार

नई दिल्ली। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और किसी को नहीं पता है कि यह युद्ध कब और कैसे खत्म होगा लेकिन यह करीब-करीब साफ है कि रूस अभी नहीं जीत रहा है। रूस अब तक यूक्रेन की सरकार को बदलने और कीव पर कब्जा करने में नाकाम रहा है और अब तो रूस यूक्रेन के पूर्वी भाग के कुछ इलाकों में सिमटकर रह गया है। इतना ही नहीं रूस को यूक्रेनी सेना को पीछे धकेलने में भी मुश्किलें आ रही हैं। तो क्या यूक्रेन युद्ध जीत रहा है ?

रूसी सेना की कमजोरियों पर यूक्रेन का वार

यूक्रेनी सेना ने बेहद चतुराई से काम किया है और रूसी सेना की कमजोरियों पर वार कर फायदा उठाया है। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के एलियट कोहेन ने मामले को लेकर कहा, मुझे लगता है कि यहां जिस परिदृश्य को कम करके आंका जा रहा है, वह वास्तविक रूसी पतन की संभावना है। मुझे लगता है कि मौलिक स्तर पर पुतिन पहले ही हार चुके हैं और मुझे व्यक्तिगत रूप से यह कल्पना करना मुश्किल लगता है कि वह बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहें।

रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों पर अब यूक्रेन का नियंत्रण?

जिस तरह से रूसी सेना ने यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया है उसे डॉक्यूमेंट किया गया है लेकिन यूक्रेनी सेना ने

रूसी सेना को कितना नुकसान पहुंचाया है यह बेहतर तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है। यह सच है कि कई जगहों पर यूक्रेनी सेना पीछे हटी थी लेकिन अब उन जगहों पर फिर एक बार यूक्रेनी सेना का नियंत्रण है। इसमें पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा शामिल नहीं है क्योंकि वहां अभी भी रूसी सैनिक बड़े हिस्से में जमे हुए हैं। सुरक्षा थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक माइकल क्लार्क ने कहा, %मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन के पतन की संभावना है। यूक्रेन को जीत सुनिश्चित करने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करने जा रहे हैं।

दलदल में फंस गया है यूक्रेन?

युद्ध में कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब किसी भी पक्ष की हार या जीत नहीं होती है। बराबरी पर छूट जाता है।

ऐसे हालात में यह संभव है कि किसी पक्ष का अधिक नुकसान हुआ हो और किसी का कम लेकिन जीत या हार किसी की नहीं होती। विश्लेषकों का कहना है कि अगर यूक्रेन डोनबास में मौजूदा रूसी आक्रमण का सामना कर सकता है, तो यूक्रेनियन अगले कुछ हफ्तों में अपने जवाबी हमले को तेज कर देंगे।

डोनबास और क्रीमिया पर है यूक्रेन की नजर?

स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय में रणनीतिक अध्ययन के प्रोफेसर फिलिप्स ओ ब्रायन बताते हैं कि ऐसा लगता है कि रूस ने जो एज हासिल किया था उसे खो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि वह किस पॉइंट पर आगे बढना बंद कर देंगे और क्या यूक्रेनी सेना उन्हें पीछे धकेल सकेगी ?

किंग कॉलेज लंदन के प्रोफेसर लावरेंस फ्रेडमेन का कहना है कि अगर यूक्रेनी सेना रूसी सेना को पीछे धकेलने में सफल रहती है तो वहां कहां जाकर रुकेंगे, यह बड़ा सवाल है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं... से मुद्रित एवं , ब्लाक नं 23 मकान नं 399 त्रिलोक पुरी दिल्ली -91 से प्रकाशित
संपादकः प्रवीण कुमार सिंह, आरएनआई नं. -DELHIN/2011/38334, किसी भी विवाद के लिए पीआरबी एक्ट अंतर्गत उत्तरदायी, टेलीफोन नं.: 011-26700510/11 , ई-मेल : info@gauravshalibharat.com, समस्त विवादो का न्यायलय दिल्ली होगा

सब्जियों को दें उन्नत तकनीक की खुराक

लम्बी अवधि वाले पौधों में शीघ्र पुष्पन

आलू, पालक, मिर्च इत्यादि में जल्दी ही फूल आ जाते है जिबरेलिक एसिड 200-800 पी.पी.एम सान्द्र घोल से छिड़काव करना चाहिए व 2,4 डी के 100 पी.पी.एम. घोल का शकरकंद के ऊपर छिड़काव करने से फूल जल्दी आ जाते है. सब्जी के पौध रोपण को अच्छा बनाने के लिए व हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, इण्डोल एसिटिक एसिड के द्वारा जड़ों को 0.1-0.2 मि.ग्रा. प्रति लीटर 24 घंटे तक उपचारित करें यह टमाटर, बैंगन व गोभीवर्गीय फसलों में लाभदायक होता है. सब्जियों को बहुत अधिक सर्दी से बचाने के लिये 0.75 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर साइकोसिल (सी.सी.सी.) का छिड़काव कलिका बनने से पहले आलू की फसल में करने से पौधों में अधिक सर्दी को सहन करने की क्षमता आ जाती है. टमाटर में 0.4 से 0.5 प्रतिशत साइकोसिल और जिबरेलिक एसिड 25 पी.पी. एम. के छिड़काव से इसे सर्दी के प्रति कठोर बनाया जा सकता है. मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने (जिनमें नर व मादा फूल अलग-अलग आते हैं -जैसे कुकरबिटेशी कुल के पौधों में व खीरा, लौकी में जिबरेलिक एसिड का 10-30 पी.पी.एम. घोल का छिड़काव हो जाता है. जिससे मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि हो जाती है व उपज भी बढ़ जाती है इसके अतिरिक्त खीरा तथा लौकी में मौलिक हाइड्राक्साइड के दो छिड़काव 25 से 50 पी.पी.एम. दो या चार परती अवस्था में करना चाहिए जिससे मादा पुष्पों की संख्या बढ़ जाती है व उपज में वृद्धि हो जाती है. फलों को सुचारू रूप से बनने तथा विकास को नियमित करने में - टमाटर, मिर्च के लिये नेप्थेलिन एसिटिक एसिड का 20 पी.पी.एम. तथा बैंगन के लिये इण्डोल एसिटिक एसिड 50-100 पी.पी.म के घोल का छिड़काव करें जिससे फलों का विकास अच्छी प्रकार से होता है.

पार्थेनोकार्पी व फलों के विकास में - बैंगन तथा कुकरविट्स में 2,4 डी 25-30 पी.पी. एम. व नेप्थेलीन एसिटिक एसिड 200 पी.पी. एम. के घोल का छिड़काव करने से बीज रहित फल का निर्माण होता है. फलों को एक समान पकाने व रंग लाने के लिये- टमाटर को 1000 पी.पी.एम. व मिर्च को 2000-5000 पी.पी.एम. से दो मिनट तक उपचारित करने से फल एक समान पकते हैं व समान रंग आता है जिससे बाजार मूल्य अच्छा मिलता है.

पौध वृद्धि हार्मोन्स

पादप हार्मोन्स एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो परिवहन पश्चात पादपों के अन्य अंगों में पहुंचकर अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में वृद्धि तथा उपापचय क्रियाओं को प्रभावित तथा नियंत्रित करते हैं. इन्हें पादप हार्मोन्स कहा जाता है इसको निम्न दो वर्गों में बाँटा गया है :-

आक्जिन

अ. इण्डोल ऐसिटिक एसिड, ब. इण्डोल ब्यूटाइरिक एसिड, स. नेप्थेलिन ऐसिटिक एसिड

जिबरेलिक

अ. जिबरेलिक एसिड
साइटोकाइनिन - काइनेटिन, जियेटिन
वृद्धि रोधक
एबसिसिक एसिड

इथाइलीन

पौध वृद्धि नियामकों का सब्जी उत्पादन में लाभदायक प्रयोग -

प्रसुप्ता अवस्था तोड़ने

(अ) आलू फसल में यदि एक प्रतिशत याथोयूरिया, इथाइलीन क्लोराइड या जिबरेलिक एसिड का उपयोग करते हैं तो प्रसुप्तावस्था को तोड़ा जा सकता है. (ब) आलू को बुवाई पूर्व जिबरेलिक एसिड 0.5 मि.ग्रा. प्रति लीटर व बैंगन में 15-25 पी.पी. एम. तथा लौकी, खरबूजा और तरबूज इत्यादि को एथीफान 500 पी.पी. एम. से 24 घंटे तक बीज को बुवाई से पहले भिगोंये.

पाला से बचाने के लिये

टमाटर व पालक को पाला से बचाने के लिये एसिटिक एसिड का खीरा में जिबरेलिक एसिड 1 पी.पी.एम. का उपयोग किया जाता है.

सब्जियों (टमाटर, मिर्च) के पौधों में फलों के गिरने से बचाने के लिये प्लेनोफिक्स 10-20 पी.पी.एम. घोल का छिड़काव करें जिससे फलों को गिरने से रोका जा सकता है.

प्याज में इथियान की 500-1000 पी.पी.एम. की 4-5 पत्ती अवस्था में प्रयोग करने से प्याज की गोंढ़ बनना शीघ्र प्रारंभ हो जाती है.

चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण में 2,4 डी का छिड़काव किया जाता है.

उपरोक्त मात्रा को किसान भाई सही मात्रा व सही समय पर प्रयोग करके सब्जियों के उत्पादन में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

पौध वृद्धि नियामकों के प्रयोग के समय रखी जाने वाली सावधानियाँ

- अधिक मात्रा में इनका प्रयोग करने पर यह डेण्डू की वृद्धि एवं विकास के साथ-साथ गुणवत्ता पर हानिकारक प्रभाव डालता हैं.
- इनका प्रयोग सही अनुपात में करना चाहिए अन्यथा यह सिंक एवं सोर्स के संबंध पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं. जिससे डेण्डू का गिरना तथा विभिन्न प्रकार के फिजियोलॉजिकल डिस्आर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है. ●

यह महंगे होते हैं और बाजार में आसानी से नही मिल पाते है. जिससे किसान इसका प्रयोग अपनी फसलों की उपज बढ़ाने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते है.

प्रदूषित मिट्टी की पहचान एवं समाधान

मिट्टी को उपजाऊ बनाये रखने के लिये आवश्यक है कि उसे क्षरण और प्रदूषण से बचावें। परंतु उससे पहले यह जानना होगा कि क्या मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी से उत्पादकता कम हो रही है या प्रदूषण में जमा हो रहे पदार्थो से उर्वराशक्ति क्षीण हो रही है और यदि मिट्टी में प्रदूषित हो रही है तो उसके कारकों को जाने उवं प्रबंधन करें अन्यथा मनुष्य का जीवन भी सुरक्षित नहीं होगा जिसके कारण वर्तमान समय में नई-नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। कुछ प्रदूषण के कारक निम्नानुसार हैं:

कृषि रसायनिकों के द्वारा मिट्टी प्रदूषणः परंपरागत खेती में मिट्टी में पोषक तत्वों का चक्र मिट्टी-पौधे-पशु-मिट्टी होता था जो आज की आधुनिक खेती में रसायनिक उर्वरकों के कारण छोटा हो गया है इस कारण पौधे/पशु अवशेषों से मिट्टी में प्रदूषण बढ़ा है गुणवत्ता बढ़ाने के स्थान पर प्रदूषित करते हैं। कृषि में प्रयोग किये जाने वाले कृषि रसायनों द्वारा प्रदूषण निम्न प्रकार से होता है।

(अ) रसायनिक कीटनाशियों में मुख्य रूप से दो प्रकार के कीटनाशी प्रयोग किये जाते हैं। वे निम्न है

ओरगेनोंक्लोरीनस

ये कीटनाशी मिट्टी में जीवाणुओं द्वारा अपघटित नहीं होते हैं जिसके कुछ अंश वर्षो तक मिट्टी में विद्यमान रहते हैं जिनके कारण हार्मोन्स एवं एंजाइम्स की क्रियायें परिवर्तित हो जाती है जिससे उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे डीडीटी, बीएचसी आदि।

ओरगेनोफास्फेट

ये मिट्टयों में अधिक मात्रा में प्रयोग किये जाते हैं परंतु जीवाणुओं द्वारा जल्दी अपघटित हो जाते हैं और जीव-जंतुओं के शरीर में संचित नहीं होते हैं।

- **फफूंदनाशकों के द्वारा मिट्टी प्रदूषण:** पारायुक्त रासायनों के उपयोग से मृदा के लाभकारी जीवाणुओं को हानि पहुंचाते हैं जो मिट्टी के संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इन पर भारत शासन द्वारा 1996 में प्रतिबंध लगा दिया है जैसे- एग्रोसान, मोनोसान बीजोपचार दवाओं द्वारा मिट्टी प्रदूषण होता है।
- **खरपतवार नाशकों के द्वारा मिट्टी प्रदूषण:** खरपतवार नाशी मिट्टी परिस्थितिकी को प्रभावित करते हैं साथ ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर भी सीधा कुप्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतनाशी रसायन दलहनी मिट्टी जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं।

ठोस एवं जलीय अपद्रव्यों द्वारा मृदा प्रदूषण

ठोस एवं जलीय अपद्रव्य मिट्टी में निम्नलिखित स्त्रोतों द्वारा मिट्टी में पहुंच कर मिट्टी की उर्वराशक्ति को क्षीण करती हैं।

- **कारखानों के अपद्रव्यों द्वारा प्रदूषण:** फेक्ट्रियों एवं कारखानों से निकली ठोस एवं जलीय अपद्रव्यों को बिना उपचारित किये मिट्टी में विसर्जित करना मिट्टी एवं फसल दोनों को घातक है इनमें विषैले तत्व मिले होने के कारण मिट्टी की उर्वराशक्ति पर घातक प्रभाव डालती हैं। इन ठोस एवं जलीय अपद्रव्यों से मिट्टी की भौतिक, रसायनिक एवं जैविक दशा भी परिवर्तित हो जाती है।
- **रेडियो धर्मी पदार्थो द्वारा प्रदूषण:** रेडियो धर्मी पदार्थ कई प्रकार से मिट्टी में विद्यमान रहते हैं जो जीवों के अलावा मिट्टी की उर्वरता पर भी प्रतिकूल प्रभव डालते हैं।
- **मृत पशुओं से प्रदूषण:** मृत पशुओं को खुला छोड़ने से जीवाणुओं की क्रियाओं से मांस सड़ने लगता है जिससे मिट्टी में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं।
- **घरों का कचड़ा खेतों में फेंकने से प्रदूषण:** किसान भाई बिना गड्ढे में सड़ाये घर का कचड़ा खेतों में डाल देते हैं जो जीव और पौधों को हानि पहुंचाते हैं। और मिट्टी भी प्रदूषित हो जाती है जिसमें कीड़े आदि मिट्टी में उपलब्ध हो जाते हैं।
- **कारखानों के निकली गैसों द्वारा प्रदूषण:** कारखानों के निकली गैसों एवं धुएं में सल्फर एवं नाइट्रोजन के आक्साइड वायुमण्डल से नमी से क्रिया करके गंधक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं जो वर्षा जल या नम धुन्ध से भूमि पर गिरते हैं और मृदा की अम्लीयता को बढ़ाते हैं।

रासायनिक उर्वरकों द्वारा प्रदूषण

मिट्टी में रसायनिक उर्वरकों द्वारा तब प्रदूषण अधिक होता है जब बिना मिट्टी जांच कराये असन्तुलित उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि बुवाई करते समय नमी की कमी होने पर पौधों को जला देती है। साथ ही मिट्टी की भौतिक रसायनिक दशा बदल देती हैं अम्लीयता क्षारीयता को बढ़ा देती है।

- **जल भराव के कारण प्रदूषण:** अधिक जल भराव की स्थिति में मिट्टी लवणीय हो जाती हैं जिससे सूक्ष्म जीवाणुओं की गतिविधियां रूक जाती हैं और मिट्टी प्रदूषित हो जाती है।
- **उत्खनन एवं भवन निर्माण कार्यो से प्रदूषण:** खनिजों के उत्खनन एवं भवन निर्माण कार्यो से प्रदूषण ऊपरी सतह पर खदानों से बहकर हानि कारक पदार्थ जमा हो जाते हैं या निर्माण के समय बचे हुए पदार्थ बह कर मिट्टी सतह पर इकट्ठे हो जाते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है।
- **वनों की अंधाधुन्ध कटाई से प्रदूषण:** वनों के पेड़ों की कटाई से मिट्टी क्षरण बढ़ता है साथ ही वर्षा भी कम होती है जिससे मिट्टी की उर्वराशक्ति क्षीण होती है।

देश की बढ़ती जनसंख्या के भरण

पोषण के लिये आवश्यक हो गया है कि हमारे देश की उपलब्ध मिट्टी को सुरक्षित कैसे किया जाये क्योंकि खेती योग्य जमीन लगातार भवन निर्माण आदि में उपयोग होकर घटती जा रही है तथा कुछ क्षेत्र अम्लीयता क्षारीय के कारण खेती के अयोग्य होता जा रहा है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए आज विचार आवश्यक है अन्यथा बहुत देर हो गई होगी जब हमारा देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भता खो देगा इसलिये आज मिट्टी प्रदूषण का नियंत्रण नहीं प्रबंधन जरूरी है जो हर देशवासी का मानवीय कर्तव्य है।

मिट्टी प्रदूषण को रोकने के लिए प्रबंधन

- एकीकृत पौध संरक्षण अपनाते हुए कीट नियंत्रण करें जब तक आवश्यक न हो तब तक कीट रसायन उपयोग न करें और यदि करना आवश्यक हो तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह से अनुसंशित मात्रा को उचित विधि से उपयोग करें।
- रासायनिक खादों का उपयोग मिट्टी की जांच उपरांत आवश्यक मात्रा को उचित विधि व समय पर दें।
- खरपतवार प्रबंधन में जहॉ तक संभव हो यांत्रिकी विधियों का उपयोग करें यदि रसायन उपयोग करना हो तो उचित सहाय के बाद ही उपयोग करें।
- कारखानों से निष्काषित पदार्थ जल को वैज्ञानिक विधियों द्वारा उपचारित कर शुद्ध करके ही खेतों में दें।
- कारखानों से निष्काषित गैसों की चिमनियों को ऊंचा बनाया जाये और उसके ऊपर वायु शोधन यंत्र भी होना आवश्यक है।
- अधिक वर्षा एवं पर्यावरण शुद्धिकरण हेतु वनों की कटाई न करें बल्कि खेतों की मेढ़ों पर वृक्ष लगावें।
- खेतों की मेढ़ बंदी करें, खेतों को समतल करें और जल निकास की उचित व्यवस्था करें जिससे मिट्टी कटाव न हो।
- घरों से निकलने वाले कचड़े का कम्पोस्ट बनाकर खेतों में डालें।
- मल-मूत्र एवं गंदे पानी को खेतों में सीधा न जाने दें।
- भवन एवं सड़क निर्माण से बचे हुए कचड़े को खेतों में न डालें तथा खदानों के प्रदूषित पानी को खेत में न आने दें।
- यदि खेतों में वायु प्रदूषण के कारण अम्लीयता बढ़ रही है तो मृदा में चूना का उपयोग करें। साथ ही अम्लीयता सहन करने वाली फसलों की बुवाई करें।
- यदि खेतों की क्षारीयता बढ़ रही हो तो जिप्सम उपयोग के साथ-साथ जैविक खादों का उपयोग बढ़ावें।

मूंग का भभूतिया रोग

यह रोग दुनिया भर में पाया जाता है, जहां मूंग की खेती होती है, मध्यप्रदेश में मूंग का क्षेत्रफल 84 हजार हेक्टेयर एवं उत्पादन 28 हजार टन हैं। भारत में यह रोग सन 1918 में रिपोर्ट किया गया था। मूंग पर इस रोग का आक्रमण फलियों के बनते समय आसमान में बादल छायें हो तब अधिक होता है। शीघ्र पकने वाली जातियों में हानि कम होती है। परंतु रोग का जब भीषण प्रकोप होता है तब खेत में फलियों की संख्या 20 से 30 प्रतिशत तक घट जाती है और उपज में 40 प्रतिशत तक की कमी हो जाती है। इस रोग को उत्पन्न करने वाला कवक इरीसाईफी पीसी संसार के विभिन्न भागों में 300 से अधिक परपोषी जातियों पर पाया जाता है और इस कवक के विभिन्न क्रियात्मक प्रभेद कुछ अन्य फसलों जैसे-धनिया, सौंफ, रिजका, उड़द, मटर, गोभी इत्यादि पर भी संक्रमण करते हैं।

लक्षण

सर्वप्रथम रोग पौधों की पत्तियों पर दिखाई देता है तथा बाद में पौधों के दूसरे भागों पर भी फैल जाता है। प्रारंभ में पत्तियों की दोनों सतहों पर सफेद चूर्णी धब्बे बनते हैं जो बाद में फली एवं तने इत्यादि के ऊपर भी बन जाते हैं । पहले धब्बे छोटी-छोटी रंगहीन चित्तियों के रुप में बनते हैं परंतु अंत में इनके चारों ओर चूर्णी समूह फैल जाता है। इस प्रकार से रोगी पौधे छोटे रह जाते हैं उन पर फलियां भी कम लगती हैं तथा दाने हल्के होते है। पत्तियों के जिस स्थान पर परजीवी का कवक जाल फैला रहता है वहां की कोशिकायें ऊतकक्षय के कारण मर जाती है संक्रमित पत्तियां पीली पड़ कर मुड़ जाती है और अंत मे गिर जाती है। रोग का अधिक प्रकोप होने पर पौधा मर जाता है।

कवक इरीसाईफी पीसी अनेक एक वर्षीय एवं बहुवर्षीय परपोषी पौधों पर आक्रमण करता है। पूरे वर्ष अपनी कोनिडियमी अवस्था में ही जीवित बना रहता हैं। वैसे इसके क्लाइस्टोथिसियम भूमि में गिरे पौधों के रोगग्रस्त अवशेषों पर बनते है और यह इन्ही के द्वारा एक मौसम से दूसरे मौसम में जीवित बना रहता है। अगले मौसम में क्लाइस्टोथीसियम भूमि के समीप वाली पत्तियों पर सबसे पहले संक्रमण करते है। रोग का द्वितीयक संक्रमण, प्राथमिक संक्रमण से बने कवकजाल द्वारा उत्पन्न कोनिडियमों से होता है कोनिडियमों का फैलाव (प्रकीर्णन) वायु द्वारा होता है एवं मूंग के बीजों में उपस्थित प्रसुप्त कवकजाल के द्वारा होता है।

रोग नियंत्रणः सफाईः भूमि में पड़े रोगी पौधों के अवशेषों को एकत्र करके सुरक्षित स्थान पर जला देना चाहिये।

भभूतिया निरोधक जातियां

पूसा बोल्ड, नरेन्द्र मूंग -1 , पीडीएम-139 (सम्राट), एमएल-515, के-851. 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गंधक चूर्ण को भुरकना चाहिये। किसी घुलनशील गंधक कवकनाशी जैसेः थायोविट, इलोसाल, सल्फैक्स, इनसल्फगोल्ड आदि की 3 किलो ग्राम मात्रा को 500 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2 या 3 बार छिड़काव करना चाहिए। पहला छिड़काव रोग के प्रारंभ होते ही तथा दूसरा व तीसरा छिड़काव 10 से 15 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। विटावैक्स 0.1 प्रतिशत (1 ग्राम प्रति लीटर जल) का छिड़काव करके भी इस रोग को रोका जा सकता है।